



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170] नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2019/ज्येष्ठ 29, 1941
No. 170] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2019/JYAISTHA 29, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 2019

मामला सं. सीवीडी-05/2018

विषय: चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सेकरीन' के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी/सब्सिडीरोधी शुल्क संबंधी जांच।

फा. सं. 6/18/2018-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे बाद में अधिनियम कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की जांच, मूल्यांकन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए,

क. मामले की पृष्ठभूमि:

- यतः मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत किया है जिसमें सब्सिडीरोधी जांच शुरू करने तथा चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सैकरीन के आयातों पर सब्सिडीरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।
- और यतः प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर, अधिसूचना संख्या 6/18/2018 - डीजीएडी दिनांक 10 अगस्त, 2018 के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें नियमावली के अनुसार संबद्ध जांच की शुरुआत की गई ताकि

संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडीकरण के कारण घरेलू घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और सब्सिडी रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
- क) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (2) के अनुसार जाँच की शुरुआत करने से पहले वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को अधिसूचित किया।
- ख) प्राधिकारी ने स्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से चीन जन. गण. (जिसे आगे जी ओ सी भी कहा गया है) की सरकार को आमंत्रित किया और सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समझौते (ए एस सी एम) के अनुच्छेद 13 के अनुसार एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श किया। यह विचार-विमर्श 20 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें जी ओ सी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
- ग) विचार विमर्श के दौरान जी ओ सी ने दावा किया कि याचिका में दिए गए साक्ष्य कतिपय महत्वपूर्ण बातों की दृष्टि से अधूरे थे। कथित सब्सिडी योजनाएं/कार्यक्रम पहले ही समाप्त हो गए हैं और प्राधिकारी को जांच शुरुआत संबंधी याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। विचार-विमर्श के बाद जी ओ सी के अनुरोधों को इस अधिसूचना के उचित पैराग्राफ में सारांश रूप में दिया गया है।
- घ) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जी ओ सी ने जांच शुरुआत से पहले के विचार विमर्श के दौरान अपने दावों के समर्थन में कोई साक्ष्यांकित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।
- ङ) प्राधिकारी ने याचिका तथा जी ओ सी की दलीलों पर विचार किया है और यह माना है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच की शुरुआत करना और उसे चलाना जरूरी है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक/निर्यातक प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों का लाभ प्राप्त कर रहे थे और ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही थी और यदि हां, तो क्या चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद (जिसे आगे पीयूसी भी कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क उपाय (जिसे आगे सीवीडी या सब्सिडीरोधी शुल्क कहा गया है) को लगाने की सिफारिश करना उचित है और यदि हां तो सी वी डी की ऐसी राशि निर्धारित करना जिसे विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाया जाना चाहिए।
- च. प्राधिकारी ने सब्सिडीरोधी /प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 10 अगस्त, 2018 को प्रकाशित एक अधिसूचना जारी की।
- छ) प्राधिकारी ने 10 अगस्त, 2018 की जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना भारत में चीन जन. गण. के दूतावास, याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्रों के अनुसार चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादक/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा अन्य घरेलू उत्पादकों को जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भेजीं और उनसे जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 40 दिन के भीतर लिखित रूप में उनके विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
- ज) भारत में चीन जन. गण. के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी चीन जन. गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पत्रों के साथ चीन जन.गण. के दूतावास को भेजी गई थी।
- झ) प्राधिकारी ने संबंधित नियमावली के नियम 7(3) के अनुरूप आवेदन के अगोपनीय अंश (जिसे आगे एन सी वी भी कहा गया है) की एक-एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में चीन जन. गण के दूतावास को उपलब्ध कराई थी।
- ट) प्राधिकारी ने ऐसी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों जिनसे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी लाभ चीन सरकार (जीओसी) द्वारा दिया गया हो के संबंध में संगत तथ्य/सूचना मंगाने के

- लिए चीन सरकार (जीओसी) को प्रश्नावलियां भेजीं। जीओसी ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- ठ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 7 (4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों से संगत जानकारी मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी:-
- (i) सुझोऊ फाइन कैमिकल्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - (ii) शंघाई फॉरच्यून कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (iii) कार्डीफेन जिनहुआ फाइन कैमिकल्स
 - (iv) तियानजिन चांगजेई कैमिकल कंपनी लिमिटेड
 - (v) पीएमसी बेईजिंग कैमिकल कं. लिमिटेड
- (ड) इसके उत्तर में केवल शंघाई फाच्यून कैमिकल कंपनी लिमिटेड में विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- (ढ) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उत्पादकों को आयातक प्रश्नावली भेजी।
- (1) इगल ट्रेडिंग कंपनी
 - (2) कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड
 - (3) जनरल इंपोर्ट कंपनी इंडिया
 - (4) जगमोहनदास एंड संस
 - (5) सी जे शाह एंड कंपनी
 - (6) नेक्टर ड्रग्स प्रा. लिमिटेड
 - (7) प्रोक्टर एंड गेम्बल हाइजिन एंड हेल्थ
 - (8) नीरू मार्केटिंग प्रा. लि.
 - (9) स्पेशियली कैमिकल्स
 - (10) नंदिया बेंकटलाल प्रा. लिमिटेड
 - (11) सन साइन कॉस्मेटिक्स लिमिटेड
 - (12) ग्राउर एंड वेइल (इंडिया) लिमिटेड
 - (13) संदीप आर्गेनिक्स
- (ण) केवल ग्रावर एंड वेल (इंडिया) लिमिटेड ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है।
- (त) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंशों और किए गए अनुरोधों को हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराया था।
- थ) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (जिसे आगे डीजीसीआई एंड एस भी कहा गया है) से जाँच अवधि समेत विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदा-वार व्योरे की जानकारी देने का अनुरोध किया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हुए। प्राधिकारी ने सौदों की आवश्यक जाँच के बाद आयातों की मात्रा और अपेक्षित विश्लेषण की गणना के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- द) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जिसे आगे जीएएपी भी कहा गया है) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन की लागत और उसे बनाने और बेचने की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एन आई पी भी कहा गया है) ज्ञात की गई है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सब्सिडी मार्जिन से कम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ध) आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक मौके पर सत्यापन वास्तविक सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा किया गया था। वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ जहां आवश्यक हो वहां आवश्यक सुधार सहित केवल इस तरह की सत्यापित जानकारी पर भरोसा किया गया है।
- न) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक सीमा तक सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा किया गया है।
- प) वर्तमान सब्सिडीरोधी जाँच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 की अवधि तथा जांच की अवधि पर विचार किया गया है।
- फ) सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 7 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने 22 जनवरी, 2019 को हुई मौखिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में भाग लेने वाले सभी पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पक्षों से विरोधी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां लेने और अपने खंडन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई।
- ब) इस जाँच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत पाए गए अनुरोधों पर इस प्रकटन विवरण में ध्यान दिया गया है।
- भ) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच उनके गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर इस प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय माना गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं बताया गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया है कि वे गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय भाग उपलब्ध करायें।
- म) जहां भी किसी हितबद्ध पक्ष ने वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया या जांच में अत्यधिक बाधा डाली तो प्राधिकारी ने ऐसे पक्षों को असहयोगी माना है और अपने पास "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर प्रकटन विवरण को दर्ज किया है।
- य) दिनांक 06.06.2019 को हितबद्ध पक्षों को एक प्रकटन विवरण जारी किया गया जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन अनिवार्य तथ्य दिए गए थे और उन्हें प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने के लिए 14.06.2019 तक का समय दिया गया। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों से प्राप्त प्रकटन के पश्चात की टिप्पणियों पर समुचित रूप से विचार किया है।
- (र) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनियम दर 1 अमरीकी डॉलर = 65.33 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अपने सभी रूपों में "सैकरीन" है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत समझे गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- (क) "सैकरीन" एक गैर-न्यूट्रिटिव स्वीटनर है और उसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पावडर रूप में होता है और गंधरहित होता है। सैकरीन चीनी से 500 से अधिक गुना मीठी होती है। सैकरीन को दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है अर्थात् विलेय और अविलेय सैकरीन।
- (ख) सैकरीन को दो भौतिक रूपों में उत्पादित किया जाता है अर्थात् दानेदार और पाउडर। सोडियम सैकरीन को दानेदार रूप में उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां सैकरीन घुल जाती है। पाउडर रूप जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है को शुष्क मिश्रणों और भेषजों में प्रयोग किया जाता है।

- (ग) सैकरीन को अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, आदि। सैकरीन, औद्योगिक सैकरीन और खाद्य और पेय के लिए सैकरीन के बीच अंतर सैकरीन की शुद्धता के अनुसार होता है।
- (घ) आयातित उत्पाद के विनिर्देशनों और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद के संबंध में कथित अंतर पर्याप्त औचित्य के बिना गोपनीय रूप से दावा किए गए हैं। किसी भी तरह से प्रतिवादी आयातक स्वयं घरेलू उद्योग के उत्पादों का नियमित क्रेता रहा है जिससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आयातक द्वारा आयातित उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- (क) घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद में अलग विनिर्देशन हैं और वह प्रयोक्ता उद्योग की जरूरतों को पूरा नहीं करता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद अपने सभी रूपों में "सैकरीन" है। "सैकरीन" एक गैर-न्यूट्रिटिव स्वीटनर है और उसे गन्ने की चीनी का कम कैलोरी वाला प्रतिस्थापक माना जाता है। प्राथमिक रूप से दो प्रकार के सैकरीन होते हैं अर्थात् विलेय और अविलेय। बाजार शब्दावली में विलेय सैकरीन को सोडियम सैकरीन कहा जाता है जबकि अविलेय सैकरीन को सैकरीन या सैकरीन एसिड कहा जाता है। सैकरीन को दो भौतिक रूपों में उत्पादित किया जाता है अर्थात् दानेदार और पाउडर। सोडियम सैकरीन को दानेदार रूप में उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां सैकरीन घुल जाती है, पाउडर रूप जिसे पीसा और स्प्रे ड्राई किया जाता है को शुष्क मिश्रणों और भेषजों में प्रयोग किया जाता है। यह जल में थोड़ा विलेय होता है। सैकरीन का अविलेय रूप अनेक भेषजों और चिकित्सीय अनुप्रयोगों में प्रयोग किया जाता है। सैकरीन को अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है जैसे खाद्य और पेय, पर्सनल केयर उत्पाद, टेबल टाप स्वीटनर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ब्राइटनर्स, भेषज आदि। सैकरीन के सभी रूप वर्तमान जांच के दायरे के भीतर आते हैं।
8. सैकरीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष सं. 29251100 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, संबद्ध वस्तु का आयात अनेक अन्य टैरिफ उप शीर्षों के अधीन भी किया जाता है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और इस जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं हैं।
9. संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के विनिर्देशनों के याचिकाकर्ता द्वारा विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद से अलग होने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षों द्वारा ऐसे तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में संबद्ध वस्तु के लिए प्रतिवादी पक्ष को बेचने के संबंध में बिक्री बीजक प्रस्तुत किए हैं जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि प्रतिवादी पक्ष ने अनेक बार संबद्ध वस्तु का याचिकाकर्ता से भी खरीदा है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि संबद्ध वस्तु को उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिस्थापनीय रूप से प्रयोग किया जाता है।
10. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के बाद प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु से भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।
11. प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु नियमावली के अनुसार संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

12. घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में जांच की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।
- (क) यह आवेदन मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं। मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. ए.एस. कैमोफार्मा प्रा. लि. और मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. ने इस आवेदन का समर्थन किया है।
- (ख) याचिकाकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी और बाजार आसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता के अलावा, देश में केवल 4 अन्य उत्पादक हैं। अर्थात् मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक, मै. ए एस कैमोफार्मा प्रा.लि., मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज लि. और विष्णु कैमिकल्स। मै. ब्लू सर्किल, मै. ए एस कैमोफार्मा और मै. श्री वरदायिनी ने पहले ही याचिका का समर्थन किया है। किसी भी तरह से क्षति आंकड़े प्रदान करने वाले उत्पादकों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक है। प्राधिकारी ने विगत में संबद्ध वस्तु से संबंधित 3 जांचें की हैं और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के संबंध में एक जांच की है। यह देखा गया है कि वे भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के केवल उत्पादक हैं। किसी भी अन्य उत्पादक ने किसी भी जांच का उत्तर नहीं दिया है। अन्य नामित उत्पादकों के व्यापारी होने की संभावना है या वे ऐसे उत्पादक हैं जो केवल सैकरीन का आगे प्रसंस्करण करते हैं।
- (ग) चूंकि एक समर्थन मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक प्रा. लि. की सूचना इंडोनेशिया से समान उत्पाद के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी जांच में रिकॉर्ड में रखी गई थी उसे संगत होने के लिए वर्तमान जांच में भी प्रस्तुत किया गया है। मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक प्रा. लि. ने 23 एम.टी. संबद्ध वस्तु का आयात किया है। प्राधिकारी स्थिति के प्रयोजनार्थ इसके दायरे पर विचार कर सकते हैं।
- (घ) मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. ए एस कैमोफार्मा प्रा.लि., लघु उद्योग कंपनियां हैं और उन्होंने याचिका का समर्थन किया है।
- (ङ.) ब्लू सर्किल और स्वाति पेट्रो प्राडक्ट प्रा. लि. की संयुक्त सूचना पी ओ आई में घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को दर्शाती है। स्पष्टता के लिए (क) घरेलू उद्योग के रूप में स्वाति पेट्रो और (ख) घरेलू उद्योग के रूप में स्वाति पेट्रो और ब्लू सर्किल पर विचार करते हुए क्षति विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।
- (च) याचिकाकर्ता का अकेले नियमावली और करार के अधीन कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि कितनी मात्रा को प्रमुख हिस्सा माना जाए। डब्ल्यू टी ओ के कानून और डी जी टी आर के पूर्व मामले यह सिद्ध करते हैं कि 50 प्रतिशत से कम भी हिस्सा होता है। अर्जेंटीना- ब्राजील से पोल्ट्री पर निश्चात्मक पाटनरोधी शुल्क के संबंध में डब्ल्यू टी ओ पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है।
- (छ) प्राधिकारी ने विगत में कुल भारतीय उत्पादन के प्रमुख हिस्से के रूप में 50 प्रतिशत से कम हिस्से पर भी विचार किया है। हितबद्ध पक्षों ने वैबसाइट के उद्धरणों के आधार पर अन्य उत्पादकों की मौजूदगी का तर्क दिया है। कुछ कंपनियों के वैबसाइट उद्धरण उत्पादों की लंबी सूची दर्शाते हैं। इन नामित उत्पादकों के संबद्ध वस्तु के व्यापारी होने की संभावना है या ये ऐसे उत्पादक हैं जो केवल सैकरीन का आगे प्रसंस्करण करते हैं। प्राधिकारी संबंधित विभाग से संगत सूचना मंगा सकते हैं या संबद्ध वस्तु के कथित उत्पादकों से भी सूचना की मांग कर सकते हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- (क) मै. स्वाति पेट्रो प्राडक्ट प्रा. लि. का एकमात्र याचिकाकर्ता के रूप में मनमाना चयन घरेलू उद्योग को हुई क्षति को बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए है। पूर्ववर्ती जांच में याचिकाकर्ता ने वर्तमान जांच के लिए आवेदन नहीं करने का विकल्प चुना था। यह वर्तमान जांच के लिए केवल इस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के लिए चयन है कि मै. स्वाति पेट्रो प्राडक्ट प्रा. लि. को क्षति हो रही है।

- (ख) याचिकाकर्ता "घरेलू उद्योग" नहीं है और उन्होंने केवल 5 उत्पादकों के आधार पर अपना हिस्सा सुविधाजनक रूप से 30 प्रतिशत तक बताया है। उसने प्रतिवादी द्वारा अभिज्ञात कम से कम 11 अन्य उत्पादकों की मौजूदगी की उपेक्षा की है। इसकी बिल्कुल संभावना नहीं है कि याचिकाकर्ता का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता हो। यह आंकड़ा सभी अन्य भारतीय उत्पादकों पर विचार करने के बाद निश्चित रूप से कम होगा। दावा किया गया ऐसा हिस्सा प्रमुख हिस्सा माने जाने के लिए अपर्याप्त है।
- (ग) प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग की ओर से दायर याचिका के समर्थकों के आंकड़े भी मांगना अपेक्षित है जिन्होंने प्रमुख उत्पादकों के सरल समर्थन के साथ सीमित हिस्से को मानक बना दिया है।
- (घ) अनेक उत्पादकों का दावा गुमराह करने वाला है। स्थिति के निर्धारण के पश्चात एक अन्य मौखिक सुनवाई प्रदान की जाए।
- (ङ.) घरेलू उत्पादकों का भेदभावपूर्ण चयन- मै. ब्लू सर्कल की क्षमता याचिकाकर्ता की तुलना में लगभग 5 गुनी है जबकि मै. बिष्णु की क्षमता याचिकाकर्ता से दोगुनी है। फिर भी उन्हें याचिकाकर्ता नहीं माना गया है जबकि यह दावा किया गया है कि अन्य लघु उत्पादक जटिल प्रपत्र को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं फिर भी वही उत्पादक संबद्ध देश के लिए पूर्ववर्ती जांच में घटक घरेलू उद्योग थे।
- (च) आयातक उत्पादकों की पात्रता के संबंध में प्राधिकारी का विचार है कि उनके पास पाटनरोधी नियमावली के अधीन स्वविवेक है किन्तु सी वी डी नियमावली के अधीन नहीं है। ऐसी व्याख्या से कतिपय विसंगतियां और विचित्रता उत्पन्न होगी जिनसे बचना चाहिए। दोनों संविधियों में परिभाषा को पूरी योजना के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग से। विशेष रूप से तब जबकि उपबंधों में अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। सी वी डी नियमावली के अधीन सैल शब्द को यह सुनिश्चित करने के लिए एमएवाई (मे) के रूप में पढ़ना होगा कि व्याख्या सुमेलीकृत हो।
- (छ) प्राधिकारी का यह निर्णय कि "याचिकाकर्ता अपने अन्य समर्थकों के साथ नियम 2(ख) के अनुसार भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखता है और याचिकाकर्ता स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है" विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि वह केवल तब भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखता है जबकि समर्थकों से संबंधित सूचना पर विचार नहीं किया जाए। प्राधिकारी का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता स्वयं नियम 2(ख) के अनुसार स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करता है, पूर्ववर्ती वक्तव्य के विपरीत है। इससे पता चलता है कि यदि याचिकाकर्ता तथा समर्थकों के उत्पादन का घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है तो घरेलू उद्योग को उक्त समर्थकों के उत्पादन पर विचार करते हुए भी परिभाषित किया जाना चाहिए।
- (ज) प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि चयनित घरेलू उद्योग की स्थिति भारत में उस उत्पाद के समूचे उद्योग को दर्शाती हो। "प्रमुख हिस्सा" परीक्षण केवल गणितीय नहीं है जिसमें घरेलू उत्पादकों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या तक पहुंचने पर स्वतः ही घरेलू उद्योग बन जाएगा। ई सी-फास्टर (चीन) मामले में डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय का संदर्भ दिया गया है जिसमें यह कहा गया था कि प्रमुख हिस्सा कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाने वाले सापेक्षिक अधिक हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए और उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों नियमों पर विचार होना चाहिए। कोई परीक्षण जो मात्र मात्रात्मक होगा यह सुनिश्चित नहीं करेगा कि घरेलू उद्योग को कुल घरेलू उत्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाने के आधार पर परिभाषित किया जाए।
- (झ) वर्तमान जांच में मै. ब्लू सर्कल को जांच के लिए संगत माना जा रहा है और दूसरी जांच के लिए नहीं। जबकि दोनों जांचों के लिए जांच अवधि समान है। इसके अलावा, दोनों जांचों के लिए क्षति निर्धारण अधिनियम के समान प्रावधानों के अधीन किया गया है।
- (ट) घरेलू उद्योग ने मनमाने रूप से अन्य भारतीय उत्पादकों को घरेलू उद्योग से बाहर कर दिया है जबकि उन्होंने आवेदन का समर्थन किया है। व्यापार सूचना सं. 13/2018 दिनांक 27.9.2018 का संदर्भ दिया गया है।

- (ठ) घरेलू उत्पादकों ने सबसे अकुशल उद्योग को आगे किया है और अन्य भारतीय उत्पादकों की स्थिति घरेलू उद्योग से अलग है जैसा कि दिनांक 21.1.2019 के ई-मेल से स्पष्ट है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

14. सीवीडी नियम 2(ख) में निम्नानुसार प्रावधान है :-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडी प्राप्त वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा।”

15. वर्तमान आवेदन मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और मै. श्री वरदायनी कैमिकल इंडस्ट्री प्रा. लि., मै. ब्लू सर्कल और मै. ए. एस. कैमो फार्मा प्रा.लि. द्वारा समर्थित है।
16. जांच की प्रक्रिया के दौरान मै. ब्लू सर्कल आर्गेनिक ने 10 अगस्त, 2018 के पत्र द्वारा अपनी संपूर्ण सूचना रिकॉर्ड में रखी है। अनुरोध की जांच से पता चला है कि मै. ब्लू सर्कल आर्गेनिक प्रा. लि. ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के 23 एम टी का आयात किया है। सी वी डी नियमावली के नियम 2(ख) में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसे उत्पादक जिन्होंने स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात किया हो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं होंगे। नियमावली में प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली स्वविवेक नीति की अनुमति नहीं है। अतः प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि मै. ब्लू सर्कल आर्गेनिक प्रा. लि. पात्र घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हैं। इस आशय का एक पत्र कि मै. ब्लू सर्कल वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर हैं, मौखिक सुनवाई के बाद सभी हितार्थियों को भेजा गया था।
17. इस दावे कि ऐसे अन्य घरेलू उत्पादक मौजूद हैं जिन पर जांच के लिए विचार नहीं किया गया है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि अन्य उत्पादकों ने वास्तव में संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है। इसके अलावा, कोई भी अन्य उत्पादक इस जांच का समर्थन करने या विरोध करने के लिए आगे नहीं आया है। इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध हाल में संपन्न पाटनरोधी जांच सहित प्राधिकारी द्वारा की गई अनेक पाटनरोधी जांचों में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के कोई अन्य उत्पादक हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध वस्तु के ज्ञात घरेलू उत्पादक मै. स्वाति पेट्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (याचिकाकर्ता), मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. ब्लू सर्कल और मै. ए.एस. कैमोफार्मा प्रा. लि तथा मै. विष्णु कैमिकल्स लिमिटेड हैं।
18. प्राधिकारी ने कुल भारतीय उत्पाद में याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन का हिस्सा निर्धारित किया है। यह देखा जाता है कि कुल भारतीय उत्पादन से मै. ब्लू सर्कल के उत्पादन को बाहर रखने पर याचिकाकर्ता का हिस्सा 56 प्रतिशत है। इसके अलावा, कुल भारतीय उत्पादन में मै. ब्लू सर्कल के उत्पादन को शामिल करने पर याचिकाकर्ता के उत्पादन का हिस्सा 32 प्रतिशत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों स्थितियों में कुल भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे उसके किसी उत्पादक या निर्यातक से संबंधित हैं। यह भी नोट किया जाता है कि याचिका मै. श्री वरदायिनी कैमिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. ब्लू सर्कल और मै. ए.एस. कैमोफार्मा प्रा. लि. द्वारा समर्थित है। इन समर्थकों ने भी अपनी क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है।
19. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि याचिकाकर्ता सी वी डी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी और सी वी डी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है।

ड. विविध अनुरोध

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

20. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- (i) निर्यातक द्वारा अनावश्यक गोपनीयता का दावा किया गया है। मै. शंघाई फॉरच्यून कैमिकल कं. लिमिटेड को “मै. शंघाई फूक्सिन कैमिकल कं.” के नाम से भी जाना जाता है। तथापि इस तथ्य को प्रश्नावली के उत्तर में बताया नहीं गया है। मै. शंघाई फूक्सिन कैमिकल कं. लि. आगे जिनसी समुदाय

- में संबद्ध कंपनी है जिसे "मै. शंघाई फूक्सिन कैमिकल जिनसी ब्रांच" के रूप में जाना जाता है जिसका मुख्यालय में अलग-अलग पता है और वह संबद्ध वस्तु के व्यापार में शामिल है।
- (ii) मै. शंघाई फॉरच्यून कैमिकल कं. लिमिटेड का कार्डफेंग जिनहुआ फाइन कैमिकल कं. लि. द्वारा अधिग्रहण किया गया है जो बाद में पिंगमेई शेनमा ग्रुप की सहायक कंपनी है।
 - (iii) कंपनी के कारखाने का पता 2009 में बदला गया जो शंघाई कैमिकल इंडस्ट्री पार्क में चला गया जो पेट्रोकेमिकल और कैमिकल व्यवसाय का प्राथमिक रूप से विशेषज्ञ औद्योगिक जोन है और उसे केन्द्र सरकार की ओर से शंघाई नगर पालिका द्वारा चलाया जाता है।
 - (iv) निर्यातक ने याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे का पूरी तरह से उत्तर देने से बचना पसंद किया है।
 - (v) जांच की शुरुआत के संदर्भ में लगाए गए आरोपों के कानूनी रूप से गलत होने के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी ने उन्हें प्रथम दृष्टया प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयातों के विरुद्ध जांच शुरू की। तथापि, वह केवल प्राधिकारी को प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर आधारित है। यह अन्य हितबद्ध पक्षों पर है कि वे साक्ष्य के आधार पर अन्यथा को साबित करने की दलील दे।
 - (vi) घरेलू उद्योग ने नियमावली तथा जारी की गई व्यापार सूचना के अनुसार गोपनीयता का दावा किया है और आयातक ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं बताया है। उनके द्वारा पूरे के पूरे खाली पेज प्रस्तुत किए गए हैं। आयातक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद के विनिर्देशन अलग हैं और वे प्रयोक्ता उद्योग की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, कथित अंतरों को किसी औचित्य या तर्कसंगत कारण के बिना गोपनीय माना गया है।
 - (vii) प्राधिकारी को प्रस्तुत सूचना नियमावली के दायरे के भीतर है और प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ही की गई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है जबकि निर्यातक ने स्वयं अपने प्रस्तुत उत्तर में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
 - (viii) आयातक ने प्रश्नावली के अपने उत्तर में व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया है। उनके द्वारा पूरे के पूरे खाली पेज प्रस्तुत किए गए हैं। आयातक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए उत्पाद के विनिर्देशन अलग हैं और वे प्रयोक्ता उद्योग की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। तथापि, कथित अंतरों को किसी औचित्य या तर्कसंगत कारण के बिना गोपनीय माना गया है।
 - (ix) घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में पूर्ववर्ती संपन्न एस एस आर जांच के बाद से काफी बदलाव हुए हैं। घरेलू उद्योग को सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण वर्तमान पी ओ आई में वास्तविक क्षति हो रही है।
 - (x) 13 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा घरेलू उद्योग ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर संशोधित आयात आंकड़े पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। इस आवेदन को आरंभ में जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए प्राप्त डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था जिसे बाद में पी ओ आई को शामिल करने के लिए मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए वार्षिकीकृत किया गया। पूरी पी ओ आई के लिए डी जी सी आई एंड एस आंकड़े प्राप्त करने तक उन्हें ऊपर उल्लिखित पत्र द्वारा विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई से पहले प्राधिकारी को पहले से प्रस्तुत किए गए उन्हीं आंकड़ों को परिचालित किया यहां तक कि संशोधित आंकड़ों में भी प्रस्तुत किए गए मूल आंकड़ों से कोई खास परिवर्तन नहीं दर्शाया गया है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विविध अनुरोध निम्नानुसार हैं :-

- (क) प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर पूरा है और सही है तथा प्रतिवादी को कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई है।

- (ख) जांच की शुरुआत गैर कानूनी है क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े सही और पर्याप्त नहीं हैं। जांच की शुरुआत नियम 6 की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना गलत और स्वयंसेद्ध सूचना के आधार पर की गई है।
- (ग) 21 जनवरी को प्रस्तुत संशोधित आंकड़े अंतिम स्तर पर प्रस्तुत किए गए जबकि पहले से प्रस्तुत आयात आंकड़ों और 2014-15, 2015-16 और 2016-17 की अवधि के लिए संशोधित आंकड़ों के बीच अंतर का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी संशोधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इस प्रकार आंकड़े प्रस्तुत नहीं करना नियम 6.1, 6.2 और 9 का उल्लंघन है।
- (घ) संबद्ध वस्तु पर लागू पाटनरोधी शुल्क 10 वर्षों से पहले ही लागू है और घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिल चुका है। पूर्ववर्ती ए डी डी 12 जनवरी, 2018 तक लागू था और यह समझ में नहीं आता है कि 6 महीने की अवधि के भीतर घरेलू उद्योग को फिर से क्षति होना क्यों शुरू हो गया।
- (ङ.) अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है – कुल भारतीय मांग से संबंधित सूचना, बाजार हिस्से से संबंधित सूचना, अन्य भारतीय उत्पादक के उत्पादन और बिक्री से संबंधित सूचना, आवेदक उद्योग के लागत से संबंधित सूचना, याचिका में लागत संबंधी सूचना की गोपनीयता का दावा किया गया है। उद्योग को ऐसी लागत सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कतिपय अन्य प्रमुख सूचना को भी गोपनीय रखा गया है जो गोपनीयता के अनावश्यक और अवैध दावों के नए कमतर मानक स्थापित करता है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

22. विभिन्न मुद्दों के संबंध में हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए विभिन्न अनुरोधों की निम्नानुसार जांच और समाधान किया गया है :-

- (क) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद वर्तमान जांच शुरू की थी। इसके अलावा, आवेदक तथा संबद्ध देश के दूतावास के साथ विस्तृत चर्चा और परामर्श किए गए थे और चीन जन.गण. में सब्सिडियों की मौजूदगी, जिनके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को अनुचित कीमतों और सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण क्षति हो रही थी, के संबंध में प्रथम दृष्टया आधार से स्वयं को संतुष्ट करने पर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच की शुरुआत की।
- (ख) अत्यधिक गोपनीयता के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने यथा आवश्यक गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षों को प्रकटन नहीं किया गया है। गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षों को उस सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है।
- (ग) अन्य संबंधित पक्षों की मौजूदगी संबंधी दलील के बारे में निर्यातक घरेलू उद्योग के दावे के विरोध में कोई साक्ष्य नहीं दे पाया है।
- (घ) जहां तक इस दलील का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क 10 वर्ष की अवधि से मौजूद था और इसलिए दावा की गई क्षति को समझा नहीं जा सकता है। प्राधिकारी इस संबंध में नोट करते हैं कि चीन से आयातों के विरुद्ध पूर्ववर्ती एस एस आर पाटनरोधी जांच में शामिल पी ओ आई जुलाई, 2015 से सितंबर, 2016 तक थी और वर्तमान जांच में विचारित पी ओ आई बिल्कुल अलग अर्थात् अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक की है। प्राधिकारी ने वर्तमान याचिका की स्वतंत्र रूप से जांच की है और वर्तमान जांच के तथ्य और परिस्थितियां पूर्ववर्ती एडीडी जांच से अलग और बिल्कुल भिन्न हैं।

च. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का आकलन – पद्धति और मापदंड

23. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में संबद्ध देश में प्रति संतुलन योग्य सब्सिडी की मौजूदगी के प्रथम दृष्टया साक्ष्य दिए गए। जी ओ सी को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया, जो नई दिल्ली में 20 जुलाई,

2018 को हुए। जी ओ सी द्वारा याचिकाकर्ता के दावों पर प्रश्न उठाया गया। तथापि, न तो इन योजनाओं को वापस लेने और न ही चीन जन.गण. में सैकरीन के उत्पादकों या निर्यातकों के लिए उनके लागू नहीं होने को दर्शाते हुए कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया गया। विचार-विमर्श के बाद जी ओ सी ने लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए जिनका सारांश निम्नानुसार है :-

- (क) याचिका में पी यू सी के उत्पादन संबंधी आंकड़े जैसे पी यू सी के उत्पादकों की कुल संख्या, समर्थकों तथा विरोधियों आदि की संख्या प्रदान नहीं की गई है अतः याचिकाकर्ताओं की स्थिति सिद्ध नहीं होती है।
 - (ख) याचिका संगत आर्थिक कारकों तथा संकेतकों जिनका उपयोग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो के अधिकृत आंकड़े देने में विफल रही है जिससे क्षति और क्षति का खतरा जैसे क्षमता, उत्पादन, लागत, लाभ, रोजगार, उत्पादकता, मजदूरी, मालसूची, बाजार हिस्सा, क्षमता उपयोग, मांग, पूंजी पर आय आदि साबित होता हो। चूंकि याचिका में पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए गए हैं, इसलिए क्षति विश्लेषण में गंभीर त्रुटि है।
 - (ग) जी ओ सी ने यह भी उल्लेख किया है कि याचिका में पीयूसी के कुछ आयातक भारत में वेल्डेड स्टेनलैस स्टील पाइप और ट्यूबों के उद्योग से हैं। इसलिए सी वीडो से इन आयातकों का नुकसान होगा तथा वेल्डेड स्टेनलैस स्टील पाइप और ट्यूब इंडस्ट्री को भी क्षति होगी और भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
 - (घ) याचिकाकर्ता सब्सिडी कार्यक्रमों की वास्तविक मौजूदगी, राशि और विशिष्टता का साक्ष्य प्रदान करने में विफल रहा है। इसलिए, याचिका को “किसी साक्ष्य के बिना केवल आरोप” के रूप में ढाला जा सकता है।
 - (ङ.) याचिका में उद्धरित सब्सिडीरोधी मामले प्रतिकूल उपलब्ध तथ्य, “ए एफ ए”, या सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना “बी आई ए” पर आधारित है और उनमें विश्वसनीयता नहीं झलकती है। यह भी नोट किया जाता है कि डी एस 379 में डब्ल्यू टी ओ का निर्णय यह है कि किसी एक मामले के निर्धारण को दूसरे मामले के तर्काधार और पर्याप्त स्पष्टीकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः वर्तमान याचिका के उद्धरणों को जांच शुरू करने के लिए सब्सिडीरोधी साक्ष्यों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
 - (च) कतिपय कथित कार्यक्रम सार्वजनिक निकायों द्वारा नहीं चलाए जाते हैं। कोई वाणिज्यिक कंपनी सरकारी कार्यों को वाणिज्यिक कार्यकलाप करते हुए नहीं कर सकती है और इस प्रकार सब्सिडी देने वाला पक्ष नहीं बन सकती है।
 - (छ) कतिपय चीनी कानून, विनियम और नीतियां जिनका आरोप के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया गया है, समाप्त हो चुके हैं और या अब अस्तित्व में नहीं हैं।
 - (ज) जी ओ सी ने कुछ विशिष्ट कथित सब्सिडी कार्यक्रमों पर भी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं। समग्र रूप से ये टिप्पणियां उपर्युक्त पैरा घ से छ तक अनुरोधों में शामिल हैं। आगे यह भी नोट किया जाता है कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में कार्यक्रम सं. 52 को पर्याप्त मूल्य/निविष्टि/सेवाओं से कम पर कच्ची सामग्री के रूप में बताया गया है जबकि जी ओ सी ने “पर्याप्त और उचित बाजार मूल्य से कम पर बिजली का प्रावधान” के संबंध में अपनी टिप्पणियां दीं। जी ओ सी ने कच्ची सामग्री से संबंधित ऊपर उल्लिखित कथित कार्यक्रम के संबंध में कोई स्पष्ट अनुरोध नहीं किया है।
24. जी ओ सी द्वारा प्राधिकारी को उपर्युक्त अनुरोधों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिया गया है।
 25. जांच शुरूआत के बाद जी ओ सी और चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों को विहित ढंग और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी गई और ऐसी सब्सिडियों, यदि कोई हों, की मौजूदगी और राशि के उचित निर्धारण के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था।
 26. जी ओ सी ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। मै. शंघाई फारच्यून कैमिकल कंपनी लिमिटेड (एस एफ सी सी एल), चीन जन. गण. ने प्रश्नावली का अपना उत्तर प्रस्तुत किया था। उक्त निर्यातक

द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर की जांच की गई और प्राधिकारी मानते हैं कि उसे निम्नलिखित कारणों की वजह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

- (क) कंपनी ने बताया है कि उनकी कानूनी संरचना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की है जबकि उसके ईक्यूआर में यह पाया गया कि वह एक "सीमित दायित्व कंपनी (ताइवान, हांगकांग और मकाऊ तथा चीन के बीच संयुक्त उद्यम)" है और संयुक्त उद्यम भागीदारों का ब्यौरा (यह सूचना कि क्या ऐसा भागीदार निजी स्वामित्व अथवा राज्य के स्वामित्व वाला है, सहित) ईक्यूआर में नहीं बताया गया है।
- (ख) ईक्यूआर में दिया गया कार्पोरेट स्वामित्व ढांचा पूरा नहीं है क्योंकि उसकी मूल कंपनी मै. फारच्यून मीटिंग फैक्टरी लिमिटेड (एक विदेशी उद्यम जिसका एस एफ सी सी एल में 96 प्रतिशत हिस्सा है) के शेयरधारकों के ब्यौरे का उल्लेख नहीं किया गया है।
- (ग) अपने ईक्यूआर में कंपनी ने एक कच्ची सामग्री के नाम का अंग्रेजी अनुवाद नहीं बताया है जो अकेले ही कंपनी के कुल कारोबार का 57 प्रतिशत है। इसके अलावा, कैल्शियम कार्बोनेट के आपूर्तिकर्ता के नाम का अंग्रेजी अनुवाद नहीं बताया गया है। इसके अलावा, ई क्यू आर में "एफ 1" का पी यू सी की कच्ची सामग्री के रूप में उल्लेख है। तथापि, प्राधिकारी द्वारा वैब खोज सहित किसी स्रोत से एफ-1 और सैकरीन के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है।
- (घ) इस प्रकार, मै. एस एफ सी सी एल द्वारा संबंधित पक्षकारों के संबंध में अपर्याप्त और विरोधाभासी सूचना प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है।
- (ङ.) कंपनी ने 2015, 2016 और 2017 के दौरान क्रमशः ***, *** और *** एम टी का निर्यात किया है। अतः संबंध कंपनी की निर्यात मात्रा प्रतिनिधि नहीं है और भारत में आयात की मात्रा और कीमत के संबंध में उसकी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
- (च) कंपनी ने ई क्यूआर में उल्लेख किया है कि वह 2017 का वैट कर विवरण और कार्पोरेट आय कर विवरण प्रदान कर रही है जबकि वास्तव में उसने केवल दिसंबर, 2017 माह के लिए वैट कर विवरण और केवल 2017 की चौथी तिमाही के लिए कार्पोरेट आय कर को प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, प्रस्तुत की गई वैट कर विवरणी में उद्योग को टायर विनिर्माता बताया गया है जबकि कार्पोरेट आय कर विवरणी के प्रपत्र 13 में उद्योग को चीनी उद्योग बताया गया है।
- (छ) एस एफ सी सी एल की औसत निर्यात कीमत डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों के अनुसार पी ओ आई के दौरान चीन से संबद्ध वस्तु की औसत निर्यात कीमत के दुगने से अधिक है।

27. चीन के किसी अन्य उत्पादक निर्यातक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

28. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

- (क) घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि जी ओ सी संबद्ध वस्तु के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियां प्रदान कर रहा है और उसने विधान और नीतिगत दस्तावेजों के अनुसार, ऐसी सब्सिडी योजनाओं की मौजूदगी का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया है। घरेलू उद्योग ने ए एस सी एम और भारतीय कानूनों, नियमावली के अर्थ के भीतर चीन जन. गण. में अनेक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी स्कीमों की मौजूदगी की पहचान की है और यह दलील दी है कि चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक/निर्यातक ऐसी सब्सिडियों से लाभान्वित हुए हैं।
- (ख) जी ओ सी और चीन जन. गण. में अन्य सरकारी निकायों के कार्यक्रम निम्नलिखित कारणों की वजह से सब्सिडी माने जाएंगे।
 - (i) सरकार या किसी सरकारी निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान दिया जाता है जहां सरकार की प्रक्रिया निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण दिखाती है (उदाहरण के लिए अनुदान, ऋण और इक्विटी निवेश) या सरकारी राजस्व जो अन्यथा लिया जाना था परंतु नहीं लिया गया (उदाहरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन जैसे कर छूट संबंधी ऋण), सरकार सामान्य अवसंरचना से इतर वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है या वस्तुएं खरीदती है।
 - (ii) ऐसे लाभ जो पी यू सी के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को इस प्रकार दिए जाते हैं, और

- (iii) यह कार्यक्रम भारतीय नियमावली और ए एस सी एम के अर्थ के भीतर विशिष्ट है।
- (ग) चीन के संगत कानून और विनियम, डब्ल्यू टी ओ रिपोर्टें, सरकार की विभिन्न रिपोर्टें, मीडिया रिपोर्टें और स्वतंत्र अध्ययन और विश्लेषण, अन्य जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा उनकी सब्सिडीरोधी जांच में दिए गए जांच परिणाम स्पष्ट रूप से चीन जन. गण. में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रमों की मौजूदगी का पर्याप्त साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य जी ओ सी और चीन जन. गण. में ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों सहित सभी हितबद्ध पक्षों को याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।
- (घ) इस जांच के प्रयोजनार्थ, “चीन जनवादी गणराज्य की सरकार” में सरकार के सभी स्तर अर्थात् संघीय, केन्द्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय या स्थानीय सरकार जैसे नगर पालिका या शहर या कस्बा, सरकार, गांव या स्थानीय विधायिका, प्रशासनिक या न्यायिक एजेंसियां या निकाय, और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम जो जी ओ सी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रभाव के अधीन प्रचालन करते हैं, शामिल हैं, जो ए एस सी एम में यथापरिभाषित शब्द के अर्थ के भीतर “सार्वजनिक निकाय” के रूप में प्रचालित हैं।
- (ङ.) याचिका के अनुसार संबद्ध वस्तु के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडियां प्राप्त हुई हैं। उन्हें निम्नलिखित 6 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- I. अनुदान
 - ii. कर एवं वैट प्रोत्साहन
 - III. वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए प्रावधान
 - iv. ऋण
 - v. निर्यात ऋण वित्तपोषण
 - vi. वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान

जांच शुरूआत की सूचना में विचार की गई सब्सिडी योजनाएं

29. जांच शुरूआत संबंधी सूचना में प्राधिकारी ने निम्नलिखित संभावित सी वी डी कार्यक्रम की पहचान की थी जो वर्तमान जांच के लिए संगत हो सकते हैं।
- I. **चीन जन. गण. में अनुदान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम**
 - (i) कार्यक्रम संख्या 1: राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीनीकरण परियोजना कोष
 - (ii) कार्यक्रम संख्या 2: प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम
 - (iii) कार्यक्रम संख्या 3: पाटनरोधी जांच के लिए अनुदान
 - (iv) कार्यक्रम संख्या 5: निर्यात सहायता अनुदान
 - (v) कार्यक्रम संख्या 6: शेयरों की लिस्टिंग के लिए अनुदान
 - (vi) कार्यक्रम संख्या 7: गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाहरी विस्तार के लिए धन
 - (vii) कार्यक्रम संख्या 8: वित्तीय और तकनीकी नवाचार के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से प्रदान अनुदान
 - (viii) कार्यक्रम संख्या 9: फुयांग शहर को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न अनुदान
 - (क) करों में 10 मिलियन आरएमबी से अधिक भुगतान करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
 - (ख) उप-अनुबंध सेवा कार्यक्रम के निर्यात के तहत अनुदान
 - (ग) उत्कृष्ट नए उत्पाद / प्रौद्योगिकी पुरस्कार के तहत अनुदान
 - (घ) प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग सिटी सरकार से निवेश अनुदान
 - (ङ.) उद्यम संचालन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए अनुदान
 - (च) निर्यात क्रेडिट बीमा शुल्क पर स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान

(छ) हांगजो प्रीफेक्चर और फुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) और (अनहुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक आफरिंग (आईपीओ) अनुदान

- (ix) कार्यक्रम संख्या **10**: निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
- (x) कार्यक्रम संख्या **13**: लघु और मध्यम आकार के उद्यम के लिए समर्थन निधि
- (xi) कार्यक्रम संख्या **14**: तकनीकी छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए धनराशि
- (xii) कार्यक्रम संख्या **15**: टियांजिन बिन्हाई न्यू एरिया और टियांजिन आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में उपलब्ध सब्सिडी
- (xiii) कार्यक्रम संख्या **16**: प्रमुख उद्योग और अभिनव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशेष निधि
- (xiv) कार्यक्रम संख्या **17**: उद्यम विकास निधि
- (xv) कार्यक्रम संख्या **18**: जियांगसु प्रांत द्वारा दिया गया प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान
- (xvi) कार्यक्रम संख्या **19**: जियांगसु प्रांत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान
- (xvii) कार्यक्रम संख्या **21**: पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार (जियांगसू)
- (xviii) कार्यक्रम संख्या **22**: चांगजो क्यूथूआन जिला पर्यावरण संरक्षण निधि (जियांगसू)
- (xix) कार्यक्रम संख्या **23**: चांगजो प्रौद्योगिकी योजना (जियांगसू)
- (xx) कार्यक्रम संख्या **24**: क्यूथूआन जिला (जियांगसू) का उद्यम अभिनव पुरस्कार
- (xxi) कार्यक्रम संख्या **25**: परियोजना बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता निधि
- (xxii) कार्यक्रम संख्या **26**: एलईटीडीजेड के प्रशासन कमीशन (जियांगसू प्रांत)
- (xxiii) कार्यक्रम संख्या **27**: टियांजिन के बिन्हाई न्यू एरिया में निश्चित संपत्तियों पर त्वरित मूल्यहास
- (xxiv) कार्यक्रम संख्या **28**: उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र (जैसे टियांजिन सिटी और जिन्नान जिला)
- (xxv) कार्यक्रम संख्या **29**: बीजिंग सरकारों द्वारा विकास को बनाए रखने के लिए पुरस्कार
- (xxvi) कार्यक्रम संख्या **30**: बीजिंग प्रौद्योगिकी व्यापार प्रोत्साहन केंद्र द्वारा पुरस्कार

II. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात

- (xxvii) कार्यक्रम संख्या **33**: विदेशी निवेश उद्यमों के लिए दो निःशुल्क / तीन हाफ कार्यक्रम
- (xxviii) कार्यक्रम संख्या **34**: भौगोलिक स्थान के आधार पर एफआईई के लिए निर्यात-ओरिएण्टेड एफआईई/आयकर लाभ के लिए कर कटौती
- (xxix) कार्यक्रम संख्या **35**: एफआईई में अनुसंधान और विकास के लिए कर प्रतिपूर्ति
- (xxx) कार्यक्रम संख्या **36**: विदेशी निवेशक द्वारा एफआईई लाभ के पुनः निवेश के लिए आयकर रिफंड
- (xxxi) कार्यक्रम संख्या **38**: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
- (xxxii) कार्यक्रम संख्या **39**: केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमान्य कर छूट
- (xxxiii) कार्यक्रम संख्या **40**: अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां
- (xxxiv) कार्यक्रम संख्या **42**: घरेलू रूप से उत्पादित उपकरण खरीदने के लिए एफआईई के लिए वैट रिफंड
- (xxxv) कार्यक्रम संख्या **43**: निश्चित संपत्तियों की खरीद के लिए वैट और टैरिफ छूट
- (xxxvi) कार्यक्रम संख्या **44**: पसंदीदा उद्योगों के लिए आयातित उपकरण पर वैट और टैरिफ छूट
- (xxxvii) कार्यक्रम संख्या **45**: विदेशी निवेश (एफआईई) के साथ उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित (शंघाई पुडोंग क्षेत्र को छोड़कर)

- (xxxviii) कार्यक्रम संख्या **46**: तटीय आर्थिक ओपन क्षेत्रों में स्थापित और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्रों में एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- (xxxix) कार्यक्रम संख्या **47**: शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफआईई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- (xl) कार्यक्रम संख्या **48**: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में कॉर्पोरेट आयकर छूट और/या कमी
- (xli) कार्यक्रम संख्या **49**: एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/या कमी
- (xlii) कार्यक्रम संख्या **50**: टैरिफ और वैल्यू-एडेड टैक्स (वैट) एसईजेड और अन्य नामित क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपकरणों पर छूट

III. माल और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात

- (xliii) कार्यक्रम संख्या **52**: पर्याप्त भुगतान/इनपुट/सेवाओं से कम पर दिया गया कच्चा माल

IV. ऋण के रूप में अभिज्ञात

- (xliv) कार्यक्रम संख्या **53**: नीतिगत ऋण

V. निर्यात ऋण वित्त पोषण के रूप में अभिज्ञात

- (xlv) कार्यक्रम संख्या **55**: निर्यात क्रेडिट सब्सिडी कार्यक्रम
- (xlvii) कार्यक्रम संख्या **56**: निर्यात-आयात बैंक ऑफ चाइना-क्रेडिट उधार से निर्यात विक्रेता के लिए क्रेडिट
- (xlviii) कार्यक्रम संख्या **57**: चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात क्रेता का क्रेडिट
- (xlviii) कार्यक्रम संख्या **58** : चीन निर्यात और क्रेडिट बीमा निगम से निर्यात ऋण बीमा
- (xlix) कार्यक्रम संख्या **59**: चीन के निर्यात-आयात बैंक से अधिमानी निर्यात वित्त पोषण।
- (l) कार्यक्रम संख्या **60**: क्रेडिट लाइनों का प्रावधान
- (li) कार्यक्रम संख्या **61**: निर्यात-आयात बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिमान्य ऋण "विदेशी निवेश के लिए गोइंग आउट (वैश्विक)" रणनीति

VI. इक्विटी निवेश के रूप में अभिज्ञात

- (lii) कार्यक्रम संख्या **64**: इक्विटी स्वेप के लिए ऋण
- (liii) कार्यक्रम संख्या **65**: इक्विटी निवेश
- (liv) कार्यक्रम संख्या **66**: अप्रदत्त लाभांश

30. याचिका में यथाप्रदत्त स्कीमों संबंधी विचार-विमर्श और जांच के बाद यह नोट किया गया था कि याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित स्कीमों के संबंध में अपर्याप्त साक्ष्य प्रदान किए हैं जिनमें संबद्ध वस्तु या संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के लिए कोई लिंकेज नहीं दर्शाया गया है। अतः इन स्कीमों को जांच शुरूआत के स्तर पर ही वर्तमान जांच के दायरे से हटा दिया गया है।

I. चीन जन.गण. में अनुदान के रूप में अभिज्ञात कार्यक्रम

- अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
- परियोजना निधि भत्ता
- ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि
- सुपर स्टार उद्यम अनुदान
- स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि
- उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए अनुदान

II. कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में अभिज्ञात

- ऐसी कंपनियों के लिए अधिमानी कर नीतियों जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों / उच्च और नई प्रौद्योगिकी उद्यमों के लिए उद्यम आयकर कटौती के रूप में मान्यता दी गई है।

ii. ऐसी कंपनियों को कर अधिमान उपलब्ध है जो कम लाभ पर कार्य करती हैं।

III. माल और सेवा के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात

iii. पर्याप्त और उचित बाजार मूल्य से कम पर विद्युत का प्रावधान

IV. ऋण के रूप में अभिज्ञात

i. क्रेडिट ऋण

ii. विलेख कर (पुनर्गठन)

V. इक्विटी निवेश के रूप में अभिज्ञात

xii. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट

प्रतिसंतुलनकारी उपायों को लागू करने के लिए सब्सिडी के कार्रवाई योग्य होने की जांच

ऐसी सब्सिडी योजनाएं, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा पूर्व की किन्हीं भी जांचों में कार्रवाई योग्य पाया गया और चीन सरकार ने ऐसे पूर्व के निर्धारणों के बाद आगे किसी भी परिवर्तन की सूचना नहीं दी है :

31. प्राधिकारी ने पहले जांच की थी जिसमें कि अनेक योजनाओं की प्रतिसंतुलनकारिता की जांच की गई थी और यह पाया गया था कि अनेक योजनाएं / कार्यक्रम कार्रवाई योग्य हैं (प्रतिसंतुलनकारी हैं, यदि उत्पादक / निर्यातक द्वारा उनसे कोई परिणाम योग्य लाभ प्राप्त किए गए हैं) ऐसे सब्सिडी / कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं :
 - i. कार्यक्रम संख्या 2 : प्रमुख ब्रांड कार्यक्रम
 - ii. कार्यक्रम संख्या 3 : पाटनरोधी जांचों के लिए अनुदान
 - iii. कार्यक्रम संख्या 5 : निर्यात सहायता अनुदान
 - iv. कार्यक्रम संख्या 6 : सूचीबद्ध शेयरों के लिए अनुदान
 - v. कार्यक्रम संख्या 7 : गुआंगडोंग प्रांत में उद्योगों के बाह्य विस्तार के लिए धनराशि
 - vi. कार्यक्रम संख्या 8 : राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय नवाचार के लिए प्रांतीय कोष से अनुदान प्रदान किया गया।
 - vii. कार्यक्रम संख्या 9 : फुयांग शहर के लिए विभिन्न अनुदान प्रदान किए गए :
 - क) 10 मिलियन आरएमबी से अधिक का कर भुगतान करने वाले उद्यमों के लिए अनुदान
 - ख) उप संविदा सेवा कार्यक्रम के निर्यात के तहत अनुदान
 - ग) उत्कृष्ट नए उत्पादों / प्रौद्योगिकियों के पुरस्कार के तहत अनुदान
 - घ) प्रमुख उद्योगों के लिए फुयांग शहर शासन से निवेश अनुदान
 - ङ) उद्यम प्रचालन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के लिए अनुदान
 - च) निर्यात ऋण बीमा शुल्कों के संबंध में स्थानीय और प्रांतीय सरकार प्रतिपूर्ति अनुदान
 - छ) हांगजोऊ प्रीफेक्चर और झुयांग शहर (झेजियांग प्रांत) और (अन्हुई प्रांत) से प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अनुदान
 - viii. कार्यक्रम संख्या 10 : निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधियां
 - ix. कार्यक्रम संख्या 13 : छोटे और मझोले आकार के उद्यमों को सहायता के लिए निधियां
 - x. कार्यक्रम संख्या 14 : प्रौद्योगिकीय छोटे और मझोले आकार के उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचार सहायता के लिए निधियां
 - xi. कार्यक्रम संख्या 15 : तियांजिन बिनहाई न्यू एरिया और तियांजिन आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्र में प्रदान की गई सब्सिडी
 - xii. कार्यक्रम संख्या 16 : प्रमुख उद्योगों और नवाचार प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशिष्ट निधियां

- xiii. कार्यक्रम संख्या 33: विदेशी निवेश वाले उद्यमों के लिए दो फ्री / तीन हाफ कार्यक्रम
- xiv. कार्यक्रम संख्या 34 : निर्यात उन्मुखी एफ आई ई / अन्य कर लाभ के लिए कर कटौती / भौगोलिक स्थान आधारित एफ आई ई के लिए आय कर लाभ
- xv. कार्यक्रम संख्या 38 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमों के लिए अधिमान्य आय कर नीति
- xvi. कार्यक्रम संख्या 39 : केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए अधिमान्य आय कर नीति
- xvii. कार्यक्रम संख्या 40 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) व्यय की कटौती के लिए कर नीतियां
- xviii. कार्यक्रम संख्या 42 : घरेलू रूप से उत्पादित उपस्कर की खरीद करने वाले एफ आई ई के लिए वेट रिफंड
- xix. कार्यक्रम संख्या 43 : नियत परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए वेट और प्रशुल्क छूट
- xx. कार्यक्रम संख्या 45 : विशेष आर्थिक जोनों (शंघाई पुडोंग क्षेत्र सहित) में स्थापित विदेशी निवेश वाले उद्यमों (एफ आई ई) के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- xxi. कार्यक्रम संख्या 46 : तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों में और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास जोनों में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- xxii. कार्यक्रम संख्या 47 : शंघाई के पुडोंग क्षेत्र में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
- xxiii. कार्यक्रम संख्या 50 : विशेष आर्थिक जोनों (सेज) और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में आयातित सामग्रियों और उपस्करों पर प्रशुल्क और मूल्यवर्धन कर (वेट) छूट
- xxiv. कार्यक्रम संख्या 52 : पर्याप्त से कम पारिश्रामिक / इनपुट / सेवाओं के लिए कच्ची सामग्री
- xxv. कार्यक्रम संख्या 53 : नीतिगत ऋण
- xxvi. कार्यक्रम संख्या 64 : इक्विटी स्वेप के लिए ऋण
- xxvii. कार्यक्रम संख्या 65 : इक्विटी इंप्युजन
- xxviii. कार्यक्रम संख्या 66 : अशोधित लाभांश
- 32. चीन सरकार ने कतिपय हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों के मामले में (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 04.07.2017) और उसके बाद बसों और लारियों के लिए न्यू न्यूमेटिक टायर्स (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 25.03.2019) मामले में प्राधिकारी द्वारा इन योजनाओं की पूर्व में जांच किए जाने के बाद इनमें कोई भी परिवर्तन सूचित नहीं किया है अथवा प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए उन्हें कार्रवाई योग्य मानते हैं। तथापि, प्राधिकारी प्राप्त सब्सिडी की मात्रा को तय / गणना करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग इस जांच की किसी भी अवस्था में सब्सिडी मार्जिन की गणना नहीं की है, जिसके लिए न तो कोई स्वीकार्य प्रश्नावली उत्तर है और न ही इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अतः इन योजनाओं में कोई प्रतिसंतुलनकारी उपाय (सब्सिडी मार्जिन) तय नहीं किया गया है।

ऐसी सब्सिडी योजनाएं, जो पहले प्राधिकारी द्वारा कतिपय पूर्व जांचों में कार्रवाई योग्य पाई गई थी और चीन सरकार ने ऐसे पूर्व निर्धारणों के बाद आगे महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना दी है :

- 33. कतिपय योजनाओं के संबंध में, चीन सरकार ने यह सूचित किया है कि 'चीन जन. गण. से बसों और लारियों के लिए के लिए न्यू न्यूमेटिक टायर्स' 'की सी वी डी जांच में इन योजनाओं के मौजूद न होने / समाप्त होने / रद्द होने के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। घरेलू उद्योग ने चीन सरकार के ऐसे दावों के जवाब में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन योजनाओं में आगे कोई जांच व सब्सिडी मार्जिन पर विचार नहीं किया गया है। ये योजना नीचे दी गई हैं -
- xxix. कार्यक्रम संख्या 1 : राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवाचार परियोजना निधि
- xxx. कार्यक्रम संख्या 35 : 10 वर्षों से कम अवधि के लिए प्रचालन हेतु निर्धारित उत्पादनकारी एफ आई ई के लिए कर की दर कम करके अनुसंधान और विकास के लिए टैक्स ऑफसेट
- xxxi. कार्यक्रम संख्या 36 : विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई लाभों के पुनः निवेश के लिए आय कर रिफंड

xxxii. कार्यक्रम संख्या 48 : सेज और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में कार्पोरेट आय कर छूट और / अथवा कटौती

xxxiii. कार्यक्रम संख्या 49 : सेज और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय आय कर छूट और / अथवा कटौती

ऐसी सब्सिडी योजनाएं, जो प्राधिकारी द्वारा पूर्व की किन्हीं भी जांचों में कार्रवाई योग्य होने के संबंध में कभी भी जांची नहीं गई :

34. वर्तमान याचिका में घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. में कतिपय कार्रवाई योग्य योजनाओं के मौजूद होने की आरोप लगाया है, जिनकी प्राधिकारी द्वारा पूर्व में जांच नहीं की गई है। तथापि, इन कार्रवाई योग्य योजनाओं/ कार्यक्रमों के तहत प्रतिसंतुलनकारी उपयोग की गणना के प्रयोजन से घरेलू उद्योग ने इस जांच की किसी भी अवस्था में सब्सिडी मार्जिन की गणना नहीं की है और न तो कोई स्वीकार्य प्रश्नावली उत्तर है और न ही इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में कोई अन्य संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस प्रकार इन योजनाओं के तहत प्रतिसंतुलनकारी उपाय (सब्सिडी मार्जिन) की गणना के लिए अपेक्षित कोई सूचना उपलब्ध न होने पर प्राधिकारी यह विचार करते हैं कि किसी कार्यक्रम की कार्रवाई योग्य होने की जांच मात्र एक सैद्धांतिक कार्यवाही है। अतः प्राधिकारी ने इन कार्यक्रमों के कार्रवाई योग्य होने की जांच नहीं की है। ये कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं -

xxxiv. कार्यक्रम संख्या 17 : उद्यम विकास निधियां

xxxv. कार्यक्रम संख्या 18 : जियांग्सू प्रांत द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

xxxvi. कार्यक्रम संख्या 19 : जियांग्सू प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के तहत अनुदान

xxxvii. कार्यक्रम संख्या 21 : पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार (जियांग्सू)

xxxviii. कार्यक्रम संख्या 22 : चांगझोऊ किसुयान जिला पर्यावरणीय संरक्षण निधि (जियांग्सू)

xxxix. कार्यक्रम संख्या 23 : चांगझोऊ प्रौद्योगिकी योजना (जियांग्सू)

xl. कार्यक्रम संख्या 24 : किसुयान जिला (जियांग्सू) का उद्यम नवोन्मेष पुरस्कार

xli. कार्यक्रम संख्या 25 : परियोजना अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता निधियां

xlii. कार्यक्रम संख्या 26 : एल ई टी डी जेड (जियांग्सू प्रांत) का प्रशासनिक आयोग

xliii. कार्यक्रम संख्या 27 : तियांजिन के विनहाई न्यू एरिया में नियत परिसम्पत्तियों पर त्वरित मूल्यहास

xliv. कार्यक्रम संख्या 28 : उद्यम प्रौद्योगिकी केंद्र (अर्थात् तियांजिन शहर और जिन्नान जिला)

xlv. कार्यक्रम संख्या 29 : बीजिंग सरकारों द्वारा विकास के अनुसंरक्षण के लिए पुरस्कार

xlvi. कार्यक्रम संख्या 30 : बीजिंग प्रौद्योगिकी व्यापार प्रोत्साहन केंद्र द्वारा पुरस्कार

xlvii. कार्यक्रम संख्या 44 : तरजीह वाले उद्योगों के लिए आयातित उपस्कर पर वेट और प्रशुल्क छूट

xlviii. कार्यक्रम संख्या 55 : निर्यात प्रदान सब्सिडी कार्यक्रम

xlix. कार्यक्रम संख्या 56 : एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से निर्यात विक्रेता ऋण उधारियां

i. कार्यक्रम संख्या 57 : एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से निर्यात क्रेता ऋण

ii. कार्यक्रम संख्या 58 : चीन निर्यात और ऋण बीमा निगम से निर्यात ऋण बीमा

iii. कार्यक्रम संख्या 59 : एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से निर्यात वित्तपोषण

iiii. कार्यक्रम संख्या 60 : क्रेडिट लाइंस का प्रावधान

liv. कार्यक्रम संख्या 61 : एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक द्वारा विदेशों में जाने वाले निवेश के लिए "गोइंग ग्लोबल" रणनीति के तहत अधिमान्य ऋण प्रदान किए गए।

ऐसी सब्सिडी योजनाएं, चाहे आरोपित अथवा अन्यथा पाई गई, जहां प्रतिसंतुलनकारी उपायों को लागू करने के लिए परिमाण तय किया गया है :

35. ऐसी योजनाएं, जिन्हें अन्य जांचों में पहले प्रतिसंतुलनकारी पाया गया है और घरेलू उद्योग ने सब्सिडी का आरोप लगाया है, उनकी वर्तमान जांच के लिए जांच की गई है।
36. घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर इन योजनाओं के तहत लाभों की मात्रा प्रदान की है। इसके अलावा प्राधिकारी ने योजनाओं की प्रमात्रा के लिए उसके पास उपलब्ध सभी संगत सामग्री का मूल्यांकन किया है। इन सब्सिडियों के कार्रवाई योग्य होने के संबंध में यहां नीचे संगत पैरा में चर्चा की गई है।

अनुदान :

37. याचिकाकर्ता ने मै० पिंगडिंगशान तियानन कोल इंडस्ट्री कंपनी लि० की वार्षिक रिपोर्ट प्रदान की है, जो कि मै० केफेग जिनहुआ फाइन केमिकल कंपनी की मूल कंपनी है, जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के उत्तर न देने वाले उत्पादक / निर्यातक में से हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी को सरकारी अनुदानों वाली परियोजनाओं के लिए "सरकारी सब्सिडी" शीर्ष के तहत चीन में सरकारी प्राधिकरणों से सब्सिडी प्राप्त हुई है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह संबद्ध देश में एक सार्वजनिक निकाय द्वारा एक वित्तीय अंशदान है, जो लाभ प्रदान कर रहा है और जिसका उपरोक्त कंपनी ने लाभ उठाया है। चूंकि इन अनुदान / सब्सिडी को कंपनी की अलग-अलग वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाया गया है अतः प्राधिकारी ने इसे उद्यम विशिष्ट माना है और इस प्रकार यह कार्रवाई योग्य है। वार्षिक रिपोर्ट से ही यह देखा गया है कि कंपनी ने "सरकारी सब्सिडी" शीर्ष के तहत इन लाभों की सूचना दी है। अतः चीन अथवा चीन सरकार में उत्पादकों से विशिष्ट उत्तर न मिलने पर प्राधिकारी ने मात्रा के प्रयोजन से चीन में सार्वजनिक निकाय द्वारा प्रदान की गई इन कार्रवाई योग्य सब्सिडी पर विचार किया है। तदनुसार, "अनुदान" शीर्ष के तहत सब्सिडी का मार्जिन 30 प्रतिशत होता है।

कर छूट और वेट :

38. चीन सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा अनेक कर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे कतिपय श्रेणी के उद्यमों को कर छूट / कटौती / माफी प्रदान की जाती है, जो उनकी स्थिति अथवा उद्यमों की प्रकृति अथवा प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचार के आधार पर होती है। यह नोट किया गया है कि कार्यक्रम संख्या '37 और 41 को छोड़कर कार्यक्रम संख्या 33 से 50' में चीन जन. गण. के आय कर कानून के तहत इसी प्रकार के कर लाभ प्रदान किए गए हैं, इसके अलावा, कार्यक्रमों की प्रति संतुलनकारिता का पूर्व सी वी डी जांचों में प्राधिकारी द्वारा पहले ही विश्लेषण किया गया है। अतः प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में पूर्व निर्धारणों पर भरोसा किया है। तदनुसार, इस शीर्ष के तहत सब्सिडी मार्जिन 2.14 प्रतिशत तय किया गया है।

पर्याप्त से कम पारिश्रमिक (एल टी ए आर) के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रावधान :

भू-उपयोग अधिकार :

39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पहले न्यू न्यूमेटिक टायर्स की सी वी डी जांच में भू-उपयोग अधिकार के रूप में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी मौजूद होने की विस्तार में जांच की गई थी। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन सरकार पर्याप्त से कम पारिश्रमिक पर कतिपय उद्यमों को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्रदान कर रही है। पर्याप्त से कम पारिश्रमिक पर भूमि के उपयोग के अधिकारों का प्रावधान सेवाओं के प्रावधान के रूप में वित्तीय योगदान है। प्राधिकारी ने यह भी पाया कि बाजार दरों से कम पर प्रदान किए गए भूमि के उपयोग का अधिकार लाभ प्रदान करने में आता है। यह सब्सिडी कार्यक्रम की विशिष्ट है, क्योंकि यह चीन जन. गण. में कतिपय प्रकार के उद्यमों तक सीमित है। अतः प्राधिकारी ने यह पाया है कि चीन सरकार द्वारा भूमि उपयोग के अधिकारों का प्रावधान एक प्रति संतुलनकारी सब्सिडी कार्यक्रम है। तदनुसार इस शीर्ष के तहत सब्सिडी मार्जिन 6.37 आकलित किया गया है।

कच्ची सामग्रियां :

40. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि सरकार अथवा एक सार्वजनिक निकाय की किसी नीति अथवा कार्यक्रम के तहत पर्याप्त पारिश्रमिक से कम दर किसी कारोबारी उद्यम को उपलब्ध कराई जाती है तो कच्ची सामग्रियां वित्तीय योगदान बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्रियां सुलभ कराकर वस्तुओं के प्राप्तकर्ता को लाभ प्रदान किया जाता है। ऐसी सब्सिडी भी विशिष्ट

होती है, क्योंकि यह ऐसे उद्यम तक सीमित होती है, जो ऐसी कच्ची सामग्री / वस्तुओं का उपयोग करता है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने यह पाया है कि पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्राप्त की गई कच्ची सामग्रियां एक कार्रवाई योग्य सब्सिडी है।

41. चीन के उत्पादकों और चीन की सरकार द्वारा सहयोग न करने को देखते हुए प्राधिकारी ने कच्ची सामग्रियों की संगत अंतर्राष्ट्रीय कीमत को बेंचमार्क कीमतों के रूप में विचार किया है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल प्रमुख कच्ची सामग्रियों की वास्तविक खरीद कीमत और खपत मानदंडों पर प्राधिकारी के पास उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के तहत विचार किया गया है।
42. इस प्रकार से निर्धारित कच्ची सामग्रियों की बेंचमार्क लागत और कच्ची सामग्रियों की वास्तविक खरीद लागत के बीच अंतर को पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर चीन के उत्पादकों / निर्यातकों को लाभ के रूप में विचार किया गया है। तदनुसार, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कच्ची सामग्रियों के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी मार्जिन 73.52 प्रतिशत आंका गया है।

उपयोगी सेवाएं (बिजली) :

43. प्राधिकारी ने पूर्व जांचों में यह नोट किया है कि चीन की सरकार अधिमान्य कीमतों पर और पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कार्रवाई योग्य / प्रति संतुलनकारी सब्सिडी के रूप में उद्यमों को बिजली प्रदान कर रही है। इसके अलावा, चीन की सरकार ने यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि यह कार्यक्रम इसके किसी भी रूप में मौजूद नहीं है अथवा प्रति संतुलनकारी सब्सिडी प्रदान नहीं करता। तदनुसार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि इस कार्यक्रम के तहत सब्सिडी एक कार्रवाई योग्य सब्सिडी है।
44. चीन सरकार और चीन के उत्पादकों / निर्यातकों से सहयोग न मिलने पर प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा तय की है। इस प्रकार से तय किया गया सब्सिडी मार्जिन 2.74 प्रतिशत है।
45. प्राधिकारी ने चीन सरकार से ऐसी विशिष्ट कंपनियों के बारे में सूचना मांगी है, जिन्होंने इनपुट उत्पाद / कच्ची सामग्रियों / अन्य वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन किया है और सेकरिन के उत्पादकों तथा उनकी संगत पक्षकार स्वामित्व वाली कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान, खरीद की है। विशेष रूप से चीन की सरकार से ऐसी सूचना मांगी गई थी, जिनसे यह निर्धारित हो सकेगा कि ऐसे उत्पादक अथवा सेवा प्रदाता अधिनियम और नियमों के तात्पर्य से "सार्वजनिक निकाय" है। तथापि, चीन की सरकार ने वर्तमान जांच में प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया था अथवा कोई अन्य सूचना / अनुरोध नहीं किया था जिससे कि यह मूल्यांकन हो सके कि क्या वस्तुओं अथवा सेवा प्रदाताओं के निजी स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ता नियमों के तात्पर्य से "सार्वजनिक निकाय" हैं। उपरोक्त को देखते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में यह पाया है कि आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि चीन के उत्पादक / निर्यातक अधिनियम और नियमों के तात्पर्य से चीन की सरकार अथवा "सार्वजनिक निकाय" द्वारा प्रदान की गई अनेक सब्सिडियों का प्राप्त करने के पात्र हैं, जैसा कि उत्तरवर्ती पैरा में विस्तार से चर्चा की गई है। अन्य प्राधिकारी ने भी चीन जन. गण. के खिलाफ सी वी डी जांचों में ऐसा ही रूख किया है। कथित सब्सिडियों में धनराशियों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, धनराशियों अथवा देयताओं का संभावित प्रत्यक्ष हस्तांतरण, सरकार का राजस्व, जो अन्यथा देय हो, चाहे वह समाप्त हो गया हो अथवा एकत्र न किया गया हो, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान इत्यादि शामिल है।

निष्कर्ष :

46. चूंकि कार्रवाई योग्य सब्सिडियों के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध है और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण और आकलन प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इसलिए इन योजनाओं पर वर्तमान जांच में प्रतिसंतुलनकारिता के उपायों के निर्धारण के प्रयोजन से विचार किया गया है।

छ. क्षति आकलन और कारणात्मक संबंध :

47. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं -

- (i) क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है।
- (ii) संबद्ध देश से सब्सिडी वाले आयातों में विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में विगत वर्षों की तुलना में जांच की अवधि में वास्तविक संदर्भ में वृद्धि हुई है। जबकि आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के

दौरान संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई थी, तदोपरांत जांच की अवधि के दौरान आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है।

- (iii) उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों में जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। यह इस बात के बावजूद है कि भारतीय उद्योग के पास समग्र भारतीय मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है।
- (iv) संबद्ध देश से आयात की कीमतों में कच्ची सामग्री की लागतों में उनके अनुरूप गिरावट आए बिना जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए प्राथमिक कारण रहा है।
- (v) आयात की कीमत में गिरावट होने के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में आयातों में काफी वृद्धि हुई है।
- (vi) संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत निवल बिक्री वसूली से नीचे रही है और यहां तक कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से भी कम रही है।
- (vii) वर्ष 2016-17 के दौरान बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमतों में गिरावट आई है, जहां पर कि लागतों में गिरावट बिक्री कीमत में गिरावट से काफी अधिक थी। जांच की अवधि के दौरान लागत में और भी गिरावट आई लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से काफी अधिक थी। घरेलू उद्योग को इस अवधि के दौरान बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि पहुंच मूल्य में काफी गिरावट आई थी, जो यहां तक कि बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत स्तर से भी कम थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि आयातों के पहुंच मूल्य में गिरावट होने से घरेलू उद्योग को बाजार अंश को बरकरार रखने के लिए जांच की अवधि के दौरान अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- (viii) घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि के दौरान बरकरार रही। घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति अविध के दौरान वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री मात्राओं को बरकरार रखा और वृद्धि की लेकिन ऐसी बिक्रियां उत्पादन की लागत से काफी कम थी।
- (ix) उत्पादन में वृद्धि होने पर उसके समानुपात में बिक्रियों में वृद्धि नहीं होने पाई। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की माल सूची (इन्वेंट्री) में काफी वृद्धि हुई।
- (x) घरेलू उद्योग के बाजार अंश में कुल मिलाकर जांच की अवधि में काफी गिरावट आई है। ऐसा तब हो रहा है जब घरेलू उद्योग अपनी बिक्रियों में कीमतों की लागत पर वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है।
- (xi) लाभ में 2015-16 में थोड़ा सुधार हुआ और उसके बाद 2016-17 में नकारात्मक रुख सामने आया और जांच की अवधि के दौरान काफी अधिक हानि हुई। नकद लाभ में भी वही प्रवृत्ति रही जैसी लाभ में थी और जांच की अवधि में काफी नकारात्मक प्रवृत्ति रही। वर्ष 2015-16 में आर ओ सी ई में सुधार हुआ, यद्यपि इसमें जांच की अवधि में पुनः गिरावट आई और नकारात्मक रही। आयात कीमतों में अधिक गिरावट होने से लाभ, नकद लाभ और आर ओ सी ई में काफी गिरावट की स्थिति रही है।
- (xii) विगत में माल सूची (इन्वेंट्री) अपर्याप्त रही है। तथापि, उनमें संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि आने के साथ ही जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है।
- (xiii) क्षति अवधि के दौरान रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है और भुगतान किए गए वेतन में भी क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- (xiv) संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। घरेलू उद्योग की कीमतों को संचालित करने वाले कारकों में संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमतें और घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत शामिल है।
- (xv) मौजूदा क्षमता का ज्यादातर उपयोग नहीं हो पाया है। वर्तमान क्षमता का उपयोग न होने से और नुकसान होने से पूंजी जुटाने की क्षमता कमजोर हुई है।
- (xvi) लाभ, पी बी आई टी, नकद लाभ और निवेशों पर प्रतिफल के संबंध में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि रियायती आयात के कारण नकारात्मक थी।
- (xvii) आयातों से घरेलू उद्योग को भारी क्षति हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के आयातों में पूर्व वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है। यह आयातों में और भी वृद्धि होने का स्पष्ट संकेत है। अनुचित कीमतों के साथ आयात की मात्रा में इतनी वृद्धि घरेलू उद्योग को बर्बाद कर देगी।

- (xviii) संबद्ध देश से आयातों में कीमतों से संबद्ध वस्तुओं की लागत में उसके अनुरूप कमी आए बिना काफी गिरावट आई है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है तथा आयात ऐसी कीमतों पर हो रहा है कि उससे घरेलू कीमतों पर दमनकारी प्रभाव अथवा काफी गिरावट आ रही है तथा आयातों की आगे और भी मांग बढ़ने की संभावना है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि विगत में हुई पाटनरोधी जांचों से यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की कीमतों में कटौती करने का स्तर जांच की अवधि में काफी अधिक रहा है, लेकिन समीक्षा के अवधि में काफी गिरावट आई है, जिससे निर्यात करने वाले उत्पादकों द्वारा निर्यात की कीमतों में हेराफेरी का साक्ष्य यह है कि वे तत्कालीन पाटनरोधी शुल्क का विस्तार नहीं चाहते। उस समय के शुल्क समाप्त होने के बाद कटौती के स्तर में काफी वृद्धि हुई है और यह वास्तव में समग्र जांच की अवधि में सर्वाधिक रहा है।
- (xix) संबद्ध देश में उत्पादकों के पास उपलब्ध अधिक क्षमता के तथ्य को देखते हुए यह स्पष्ट तौर पर आकलन किया जा सकता है कि विदेशी उत्पादक अल्प अवधि में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
- (xx) संबद्ध देश के उत्पादकों का कम कीमतों पर और अधिक मात्रा में संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करने का एक इतिहास रहा है, जिसमें शुल्क न लगने के मामले में और भी तेजी आएगी।
- (xxi) संबद्ध देश के पास भारी और आसानी से निपटाई जाने वाली क्षमता है, जो भारत में भेजी जा रही है। संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पूर्व में समाप्त निर्णायक समीक्षा जांच में संबद्ध देश में उत्पादकों की अत्यधिक क्षमता और उच्च निर्यातोन्मुखी होना है।
- (xxii) भारी क्षति की आशंका का निर्धारण करने के प्रयोजन से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के केवल क्षतिकारी आयातों पर विचार किया जाए।
- (xxiii) क्षति मार्जिन की गणना करते समय प्राधिकारी को केवल ऐसे लेन देन पर विचार करना चाहिए जो क्षति मार्जिन की गणना के लिए गैर-क्षति कीमत से कम हैं। कोठारी सूगर्स एंड केमिकल्स लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का भी हवाला दिया गया है, जिसमें क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए एन आई पी से अधिक लेन देन पर विचार करने के लिए कहा गया है।
- (xxiv) घरेलू उद्योग ने निर्णायक समीक्षा जांच में 2014-15 तक हानि होने पर विचार किया है और निर्णायक समीक्षा जांच मामले में 2015-16 में और जांच की अवधि में (अर्थात् जुलाई, 2015 से सितम्बर, 2016 तक) लाभ दिखाया है। निर्णायक समीक्षा जांच की अवधि में 2016-17 के 6 माह की अवधि है। संलग्न किए गए उचित आयातों से यह दर्शाया जाएगा कि आयात की कीमतें निर्णायक समीक्षा जांच में विचार की गई जांच की अवधि में सर्वोच्च थी। आयात की कीमतें उस अवधि के दौरान 700 रूपए प्रति कि. ग्रा. के स्तर पर पहुंच गई थी और आयात की कीमतों में 2016-17 में गिरावट दर्ज की गई थी तथा मार्च 2017 के माह में गिरकर 580 रूपए तक आ गई। इस प्रकार आयात की कीमतों में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि याचिकाकर्ता को भी अपनी कीमतों में लागतों के स्तर से कम कीमत पर रखना पड़ा ताकि बाजार अंश बनाया रखा जा सके, जिसके परिणामस्वरूप हानि हुई। ऐसी ही प्रवृत्ति दोनों समर्थकों द्वारा दाखिल किए गए आंकड़ों से देखी जा सकती है। मै० बरदायिनी ने 2016-17 में हानि उठाई और मै० ए.एस. केमोफार्मा को लाभ में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।
- (xxv) इसके अलावा, घरेलू उद्योग के निष्पादन को पूर्व निर्णायक समीक्षा जांच के साथ भी देखा जाना चाहिए जो कि वही है, जो उस समय दर्शाया गया था कि घरेलू उद्योग को रियायती आयातों के कारण वर्तमान जांच की अवधि में भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है।
- (xxvi) रियायती आयातों के अलावा कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा रहा है।
- (xxvii) घरेलू उद्योग के निष्पादन में पूर्व में समाप्त निर्णायक समीक्षा जांच से काफी बदलाव आया है। घरेलू उद्योग को रियायती आयातों के कारण वर्तमान जांच की अवधि में भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि 10 वर्षों के लिए लगाया गया शुल्क उसके अपेक्षित प्रयोजन को पूरा कर पाया है। घरेलू उद्योग के निष्पादन की तुलना पर निर्भरता रही है।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध :

48. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार है -

- (i) मैसर्स स्वाती घाटे में थी और निर्णायक समीक्षा जांच-॥ में कंपनी खराब आर ओ सी ई का सामना कर रही थी। जबकि तत्कालीन घरेलू उद्योग का आर ओ आई सकारात्मक था (3 याचिकाकर्ता), इसमें गिरावट आई और 2016-17 तथा वर्तमान जांच में जांच की अवधि के लिए नकारात्मक है। यह क्षति केवल मैसर्स स्वाती से संबंधित कारकों के कारण से है।
- (ii) प्राधिकारी को प्रमुख उत्पादकों के शेष 60-70 प्रतिशत डाटा भेजने चाहिए और उनकी लागतों और डाटा पर एन आई पी के निर्धारण के लिए विचार करना चाहिए। क्षति का निर्धारण घरेलू बाजार के डाटा के आधार पर किया जाना चाहिए न कि ऐसे डाटा से, जो समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का केवल एक भाग ही दर्शाता है।
- (iii) केवल याचिकाकर्ता का डाटा ही घरेलू उद्योग की समग्र आर्थिक हालत को दर्शाने के लिए काफी नहीं है।
- (iv) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही- विगत वर्षों में आयात की मात्रा के साथ जांच की अवधि में आयात की मात्रा की उचित तुलना संभव नहीं है। विगत वर्षों में आयातों पर पाटन रोधी शुल्कों के कारण से दबाव था।
- (v) मै० स्वाती पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा० लि० के आर्थिक मापदंडों में सुधार आया है।
- (vi) रियायती आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का न होना - क्योंकि क्षति केवल स्वाती को हुई है; निर्णायक समीक्षा में दाखिल किए गए डाटा की तुलना से यह पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी भी शुल्क लागू रहने के बाद भी हानि हो रही थी। इंडोनेशिया से वस्तुओं का पहुंच मूल्य वर्तमान संबद्ध देश से वस्तुओं के पहुंच मूल्य से तुलनीय है, क्योंकि इंडोनेशिया से पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है।
- (vii) दाखिल किए गए संशोधित आयात संबंधी आंकड़ें पूर्व में दाखिल किए गए डाटा से मेल नहीं खाते क्योंकि संशोधित डाटा में दो माह के अतिरिक्त समय के बावजूद आयात की मात्रा में कमी आई है। अन्य देशों से आयात गिरावट को दर्शाते हैं। यहां तक कि पूर्व वर्षों के डाटा भी अलग हैं। ऐसा विभिन्न जांचों में विभिन्न परिणाम प्राप्त करने के लिए किया गया है (इंडोनेशिया के मामले के संदर्भ में)।
- (viii) आयात संबंधी पूर्व आंकड़ें प्रदान नहीं किए गए थे और इस प्रकार से हमें प्रभावी टिप्पणियां देने और तदनुसार प्राधिकारी की सहायता करने में अवरोध पैदा किया गया है।
- (ix) अन्य उत्पादकों को शामिल किए जाने के कारण मात्रा और बिक्रियों की सूचना भी विश्वसनीय नहीं है।
- (x) प्राधिकारी को क्षति के संबंध में जांच पूरी करने से पूर्व अन्य भारतीय उत्पादकों के निष्पादन का विश्लेषण करना चाहिए। चीन जन. गण. - संयुक्त राष्ट्र से ब्राइलर उत्पादों पर पाटनरोधी और प्रति संतुलनकारी शुल्क में डब्ल्यूटीओ पैनल पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कि यह नोट किया गया था कि जांच प्राधिकारी को अपने क्षति निर्धारण में अन्य घरेलू उत्पादकों की स्थिति को नजर अंदाज करने की अनुमति नहीं थी।
- (xi) घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। याचिका में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों तक ही टिप्पणियां सीमित हैं, क्योंकि दिनांक 18.01.2019 के मेल के माध्यम से प्रदान किए गए डाटा (आयात) सुनवाई के समय प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, संशोधित प्रोफार्मा- IVक में उत्पादन, खपत, वास्तविक मांग इत्यादि के संबंध में आयातों को नहीं दर्शाया गया।
- (xii) घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियों में वृद्धि हुई जबकि चीन जन. गण. से आयातों में कमी हुई है। घरेलू उद्योग और अन्य देशों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है जबकि अन्य भारतीय उत्पादकों तथा चीन के आयातों में कमी आई है। चीन जन. गण. से जांच की अवधि में पहुंच कीमतों में गिरावट आई है और ऐसा ही घरेलू उद्योग की कीमतों में हुआ है। चीन के आयातों की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों से ही प्रभावित हुई हैं। अन्य देशों से आयातों और घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी होने के कारण क्षति हुई है।
- (xiii) ऐसा लगता है कि कीमतों और लाभप्रदता को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि घरेलू उद्योग अपने माल को घरेलू बाजार में काफी उच्च कीमतों पर बेच रहा है। बिक्री कीमतें एन सी वी में रेंज अथवा सूचीबद्ध संख्या के रूप में भी प्रकट नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एम सी ए) की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है। उसमें दी गई बिक्री कीमत सही नहीं है, क्योंकि वस्तुएं उच्च कीमतों पर खरीदी गई हैं। ऐसा दावा कि कीमतें 400 रूपए प्रति कि. ग्रा. से कम पर थी, सही

नहीं है और यह कि याचिकाकर्ता से 600 रूपए प्रति कि. ग्रा. से अधिक पर वास्तविक मात्रा की खरीद की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा घोषित कीमतों की गहन जांच किए जाने की जरूरत है और उनकी तुलना उपयोक्ता उद्योग द्वारा अनुरक्षित बहियों और खातों से भारतीय बाजार में प्राप्त की जा रही वस्तुओं की कीमतों से की गई है।

- (xiv) याचिकाकर्ता के लाभ और अन्य उत्पादकों की बिक्री कीमतों की जांच की जानी आवश्यक है। निर्णायक समीक्षा जांच में लाभ में 2015-16 तथा जांच की अवधि अर्थात् 2016-17 के 6 माह (जुलाई, 2015 – सितम्बर, 2016) के लिए वृद्धि हुई है जबकि वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के डाटा से विपरीत प्रवृत्ति दिखाई देती है, जब वे 2016-17 में 295 प्रतिशत हानि दर्शाते हैं उनके लिए सही एनसीवी प्रदान किया जाना चाहिए।
- (xv) लाभप्रदता की प्रवृत्ति में एक भारी बदलाव देखने में आया है, जब ब्लू सर्कल नामक समर्थक की वित्तीय सूचना को भी शामिल कर लिया गया। दिनांक 21.01.2019 को प्रदान किए गए डाटा यह दर्शाते हैं कि यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि अन्य उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता से अलग व्यवहार किया है।
- (xvi) क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्रियों, कर्मचारियों की संख्या, उत्पादकता और औसतन पूंजी में वृद्धि हुई है। जबकि बिक्री कीमत में मामूली गिरावट दिखाई है, लेकिन बिक्रियों की लागत में काफी अधिक कमी आई है।
- (xvii) 2016-17 के 6 माह में कोई भी कम कीमत की बिक्री नहीं हुई। इसके अलावा याचिकाकर्ता कोई भी कम कीमत की बिक्री दर्शाने में विफल रहा है।
- (xviii) कारणात्मक संबंध में कमी है – चीन से आयातों में कमी आई है, जबकि इंडोनेशिया से वृद्धि हुई है। क्षति का कारण भारतीय उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का होना है और घरेलू उद्योग ने अपनी कीमतों में कमी केवल बाजार अंश बढ़ाने के लिए की है। इसके अलावा, उनकी वित्तीय रिकार्ड में वस्तुएं कम कीमतों पर बुक की गई हैं।
- (xix) संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क 10 वर्षों से पहले ही लागू रहा है और घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो चुका है। पूर्व में पाटनरोधी शुल्क 12 जनवरी, 2018 तक लागू था और यह समझ से परे है कि कैसे 6 माह की अवधि में घरेलू उद्योग को क्षति का सामना पुनः करना पड़ रहा है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

- 49. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों / घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने संबद्ध देश से रियायती आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।
- 50. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियम, 1995 के नियम 13 में क्षति के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांतों का प्रावधान है।

13. क्षति का निर्धारण :

(1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का एक जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात से किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हुई है।

(2) उप नियम (3) के तहत क्षति की जांच किए जाने के अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ किसी उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण किया जाएगा।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपवाद मामलों में जहां घरेलू उद्योग के अधिकांश हिस्से को क्षति न हुई हो, तो भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम देंगे, यदि -

(i) किसी एकल बाजार में पाटित आयातों की सघनता हो, और

(ii) पाटित आयातों से ऐसे बाजार के लगभग सभी उत्पाद के उत्पादकों को क्षति हो रही हो।

51. इसके अलावा, संगत आर्थिक मापदंडों में सूचीबद्ध नियमों का, घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है।
52. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और संगत कानूनी प्रावधानों पर विचार किया है। प्राधिकारी ने इन कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है। नीचे दी गई जांच वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों और घरेलू उद्योग को क्षति से संबंधित हितबद्ध पक्षकारों से संबंधित है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव :

मांग / स्पष्ट खपत का मूल्यांकन :

53. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच, भारत में उत्पादन की मांग अथवा स्पष्ट खपत के प्रयोजन से भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों को जोड़कर विचार किया है। इस प्रकार से आकलित की गई मात्रा दर्शाती है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	141	151	152
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	118	110	106
संबद्ध देश से आयात	मी. टन	441	581	308	520
अन्य देशों से आयात	मी. टन	481	308	277	633
कुल मांग/खपत	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	111	94	122

54. यह नोट किया गया है कि मांग में वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 में मामूली गिरावट आई है, लेकिन जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। समग्र मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। यह देखा गया है कि उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में 2016-17 तक गिरावट आई है, लेकिन उसमें जांच की अवधि में और समग्र आकार पर पर्याप्त वृद्धि हुई है।

संबद्ध देश से आयातों की मात्रा :

55. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों में पर्याप्त वृद्धि हुई है अथवा भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में निरपेक्ष अथवा सापेक्ष रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संबद्ध देश	मी. टन	441	581	308	520
अन्य देश	मी. टन	481	307	277	633
कुल आयात	मी. टन	922	888	585	1,153

56. यह देखने में आया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वर्ष 2016-17 के दौरान गिरावट आई है और उसके बाद उसमें जांच की अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्शाई गई है। अन्य देशों से (मुख्यतः इंडोनेशिया से) आयातों में भी वृद्धि हुई है और एक अलग जांच में यह निर्धारित किया गया था इंडोनेशिया से आयातों का पाटन हो रहा है जिनसे क्षति हो रही है, इसलिए उन पर दिनांक 03.05.2019 से 1.63 यूएस डॉलर प्रति कि. ग्रा. का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों की कीमत संबंधी प्रभाव :

57. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे

आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा मंदी आई है अथवा कीमतों में वृद्धि में रुकावट आई है, जो सामान्य अवधि में अन्यथा नहीं होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमतों का न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में है। इस विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत (सीओपी), निवल बिक्री प्राप्त (एनएसआर) की संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत से तुलना की गई है।

कीमत कटौती :

58. कीमत कटौती के विश्लेषण के प्रयोजन से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूटों, कटौतियों, और कमीशन को कम किया गया है और पाटित आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना करने के लिए कार्य बाह्य स्तर पर बिक्री प्राप्त की गई है। तदनुसार संबद्ध देश से पाटित आयातों के कटौती के प्रभाव इस प्रकार निकाले गए हैं :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
आयातों की पहुंच मूल्य	रु/ कि. ग्रा.	478	580	638	473
निवल बिक्री मूल्य	सूचीबद्ध/ रु/कि. ग्रा.	100	116	112	99
कीमत कटौती	सूचीबद्ध/ रु/कि. ग्रा.	100	81	(17)	104
कीमत कटौती	रेंज %	10-15%	7-12%	0-(5)%	12-17%

59. उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से कीमतों में कटौती 2016-17 के आलावा समग्र क्षति अवधि के लिए सकारात्मक रही है। जांच की अवधि में कीमत में कटौती की मात्रा में भी काफी वृद्धि दर्ज की गई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
आयातों का पहुंच मूल्य	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	121	133	99
बिक्री की लागत	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	114	113	109
बिक्री कीमत	रु./ कि. ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	116	112	99

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण :

60. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में काफी मात्रा में ह्रास हो रहा है अथवा कीमत वृद्धि में रुकावट आई है, जो सामान्य अवस्था में अन्यथा नहीं होती। क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन की तुलना इस प्रकार की गई थी :
61. उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16 तक घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है, वर्ष 2016-17 के दौरान कमी आई है और उसके बाद जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि में बिक्रियों की लागत में गिरावट आई है, जो बिक्रियों की लागत के स्तर से काफी कम है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत वर्ष 2016-17 को छोड़कर घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री की कीमत के स्तर से कम रही है। इस प्रकार से घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का दमनकारी प्रभाव रहा है।

कम कीमत पर बिक्री :

62. कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का आकलन किया है और उसकी आयातित वस्तुओं के पहुंच मूल्यों के साथ तुलना की गई है ताकि कम कीमत दर बिक्री तय की जा सके। घरेलू उद्योग द्वारा यह कहा गया है कि संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग पर एक महत्वपूर्ण मार्जिन तक कम कीमत दर बिक्री का प्रभाव है।

विवरण	रु/ कि. ग्रा.	यू एस डॉलर /कि. ग्रा.
गैर क्षतिकारी कीमत	***	***
पहुंच मूल्य	473.43	7.25
कम कीमत पर बिक्री	***	***
कम कीमत बिक्री %	18-23%	18-23%

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

63. नियमों के तहत यह अपेक्षा है कि क्षति का निर्धारण करने में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की एक उद्देश्यपरक जांच होगी। उत्पादकों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का एक उद्देश्यपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए तथा उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले संकेतक शामिल होने चाहिए, जिनमें बिक्रियों लाभ, आउटपुट, बाजार अंश, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट, घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक नकदी प्रवाह माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता से संबंधित संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल है।
64. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपने अनुरोध में दिए गए विभिन्न तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखकर क्षति संबंधी मापदंडों की उद्देश्यपरक जांच की है।

उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियां :

65. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	100	100	100
उत्पादन	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	142	152	172
क्षमता उपयोग	सूचीबद्ध/ %	40-45%	55-60%	60-65%	68-73%
घरेलू बिक्रियां	सूचीबद्ध/ मी. टन	100	141	151	152

66. उपरोक्त सारणी से यह नोट किया गया है कि :

- क) घरेलू उद्योग की क्षमता पूंजी क्षति अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख) घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तथापि, यह संस्थापित क्षमता के स्तर से काफी कम है। घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और यह अनुकूलतम स्तर से काफी नीचे है।
- ग) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घ) क्षति की अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है। तथापि, यह उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप में नहीं हुई है, जिसके कारण वस्तु सूची में वृद्धि हुई है, जिसे नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
सूचीबद्ध/ मी. टन	100	45	14	734

मांग में बाजार हिस्सा :

67. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा पूरी क्षति अवधि के दौरान वही रहा है और अन्य देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2016-17 में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है। भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में 2016-17 में भी वृद्धि हुई है, लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	सूचीबद्ध/ %	100%	127%	160%	127%
अन्य भारतीय उत्पादक	सूचीबद्ध/ %	100%	105%	119%	86%
चीन जन. गण. से आयात	%	23%	27%	17%	22%
अन्य देशों से आयात	%	25%	14%	15%	27%
कुल मांग	सूचीबद्ध /%	100%	100%	100%	100%

लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी लाभ :

68. क्षति की अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकदी लाभ नीचे सारणी में दिया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
पीबीआईटी प्रति यूनिट	सूचीबद्ध/रू/ कि.ग्रा.	100	160	(120)	(1,100)
कुल पीबीआईटी	सूचीबद्ध/रू लाख	100	243	(179)	(1,771)
नकदी लाभ	सूचीबद्ध/रू लाख	100	217	(117)	(1,350)
शामिल पूंजी के औसत प्रतिशत के रूप में पीबीआईटी	सूचीबद्ध/ %	100%	250%	-200%	-1750%

69. यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग हानि उठा रहा था तथा केवल वर्ष 2015-16 के दौरान लाभ अर्जित किया है। तथापि, पाटित आयात में वृद्धि तथा अन्य स्रोत से पाटन के कारण घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के पुनः हानि होनी शुरू हो गई।
70. आर ओ सी ई, पी बी आई टी और नकदी लाभ में इसी तरह की ही प्रवृत्ति रही है और यह जांच की अवधि के दौरान काफी हद तक नकारात्मक रही है।

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी:-

71. क्षति अवधि के दौरान रोजगार और मजदूरी का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है -

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	सूचीबद्ध/ संख्या	100	105	118	125
प्रति दिन उत्पादकता	सूचीबद्ध/ मी.टन/ दिन	100	141	151	172

72. यह नोट किया जाता है कि रोजगार और मजदूरी में क्षति की अवधि से दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्रतिदिन की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

माल सूची (इन्वेंट्री) :

73. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास माल सूची (इन्वेंट्री) का विवरण नीचे सारणी में दिया गया है-

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
प्रारंभ में	मी. टन	100	49	17	4
अंत में	मी. टन	100	36	8	2,220
औसतन	मी. टन	100	45	14	734

74. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की माल सूची (इन्वेंट्री) में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

वृद्धि :

75. उत्पादन और घरेलू विक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग का विकास सकारात्मक रहा है। तथापि, यह देखा गया है कि केवल वर्ष 2016-17 के दौरान ही विक्रियों की लागत, विक्री कीमत, लाभ / हानि, नकदी लाभ और आर ओ आई के संदर्भ में विकास सकारात्मक रहा है लेकिन जांच की अवधि में काफी नाकरात्मक रहा है इस प्रकार आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

पूँजीगत निवेश जुटाने की क्षमता :

76. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध भारी उपयुक्त क्षमताओं और घरेलू उद्योग के समक्ष आ रही हानियों को देखते हुए निवेशों के लिए आगे और पूँजी जुटाने की क्षमता से समझौता किया गया है।

घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक :

77. संबद्ध देश से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, रियायती आयातों के अलावा अन्य ऐसे कारकों की जांच की गई है जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रहे होंगे। आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य विक्री कीमत से और घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत से कम है, जिसके कारण भारतीय बाजार में कीमत कटौती और कम कीमत पर विक्री हो रही है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः विचाराधीन उत्पाद की कीमतें प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों के अनुसार रहनी चाहिए। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वे अपनी कीमतों को बाजार की ऐसी कीमतों के अनुसार रखने के लिए मजबूर हैं, वे संबद्ध देश से विदेशी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई कीमतों से संचालित होती हैं। इस प्रकार से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू कीमतों के निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अनुचित रियायती कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के आयात से प्रभावित हो रहा है।

कारणात्मक संपर्क एवं गैर-आरोपण विश्लेषण

78. घरेलू उद्योग को क्षति सन्निहीकृत अयातों के कारण हुई है। यदि अन्य कारकों के कारण कोई क्षति हुई है तो उसे नीचे वर्णितानुसार अलग कर दिया गया है :

- क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें- जांच की अवधि के दौरान इंडोनेशिया से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबद्ध सामानों के आत काफी थे और कम कीमत पर थे। प्राधिकारी ने हाल ही में ऐसे आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी जांच की है और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई है तथा वित्त मंत्रालय द्वारा 3 मई, 2019 की अधिसूचना द्वारा शुल्क लगाए गए हैं।
- ख. मांग में परिवर्तन - क्षति अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं है। क्षति अवधि में उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि हुई है।
- ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन- विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की पद्धति में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति के कारण नहीं हो सकता।

- घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा- कोई ज्ञात व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।
- ङ. प्रौद्योगिकी में विकास – किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।
- च. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन – घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान निर्यात नहीं किए हैं। इस प्रकार निर्यात मात्रा और अथवा लाभ में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति का कारण नहीं हो सकती।
- छ. घरेलू उद्योग द्वारा खरीदे जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन- घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति विचाराधीन उत्पाद के कारण है। याचिकाकर्ता ने यह सूचना दी है जो केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित है।
79. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि क्षति पूर्णतः याचिकाकर्ता को हुई है और अन्य घरेलू उत्पादकों को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक्स प्रा. लि. ने पूरी सूचना दायर की है। मै. श्री वरदायनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि. और मै. ए एस कैमोफार्मा प्रा. लि. ने भी दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 14/2018 द्वारा निर्धारित प्रपत्र- एच दायर किया है। समर्थकों का निष्पादन नीचे दर्शाया गया अनुसार है :

क. मै. ब्लू सर्किल ऑर्गेनिक्स प्रा. लि.

- क. जांच की अवधि में क्षमता बढ़ी। तथापि, उत्पादन एवं क्षमता उपयोग में जांच की अवधि में गिरावट आई है। जांच की अवधि में बिक्री में आंशिक सुधार हुआ।
- ख. कंपनी को 2015-16 तक हानियां हो रही थीं और 2016-17 में उसने लाभ कमाया। तथापि, जांच की अवधि में उसे फिर हानियां शुरू हो गईं।
- ग. नकद प्रवाह, निवेश पर आय भी यही प्रवृत्ति दर्शाती है। निवेश पर आय जांच की अवधि में काफी नकारात्मक है।

ख. ए.एस. कैमोफार्मा

- क. क्षमता स्थिर रही है तथापि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। उत्पादन एवं बिक्री 2016-17 तक बढ़ी परंतु उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- ख. लाभप्रदता में 2016-17 तक सुधार हुआ और उसमें जांच की अवधि में काफी गिरावट आई।
- ग. नकद प्रवाह, निवेश पर आय भी वही प्रवृत्ति दर्शाते हैं। निवेश पर आय फिर एक अंक नीचे आ गई।

ग. श्री वरदायनी कैमिकल्स

- क. क्षमता स्थिर रही है तथापि, क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। उत्पादन एवं बिक्री में 2015-16 तक वृद्धि हुई परंतु उसके बाद जांच की अवधि में उसमें गिरावट आई।
- ख. लाभप्रदता में 2015-16 तक सुधार हुआ परंतु 2016-17 में हानियां होनी शुरू हुईं जो जांच की अवधि में काफी बढ़ गईं।
- ग. नकद प्रवाह, निवेश पर आय भी वही प्रवृत्ति दर्शाता है। निवेश पर आय जांच की अवधि में काफी नकारात्मक है।

3. इस प्रकार यह देखा जाता है कि समर्थकों के निष्पादन में भी जांच की अवधि में गिरावट आई है जैसा कि याचिकाकर्ताओं के मामले में भी है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन :

80. प्राधिकारी ने नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया गया है। विचाराधीन उत्पाद की गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) का निर्धारण जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सत्यापित सूचना / डाटा को अपनाकर किया गया है। घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) की गणना की गई है और इसे क्षति मार्जिन की गणना

के लिए प्रत्येक संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। एन आई पी का निर्धारण करने के लिए क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग करने पर विचार किया गया है। जांच की अवधि में उत्पादन की गणना सर्वोत्तम क्षमता उपयोग मानकर की गई है और उसी उत्पादन पर प्रति इकाई निर्धारित लागत निकालने के लिए विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत के लिए कोई असाधारण अथवा गैर आवृत्ति व्यय प्रभारित नहीं किया गया था विचाराधीन उत्पाद के लिए शामिल औसतन पूंजी (अर्थात् औसतन निवल निर्धारित परिसम्पत्ति + औसतन कार्यशील पूंजी) पर एक तर्क संगत प्रतिफल (पूर्व कर 22 प्रतिशत की दर से) की अनुमति पूर्व कर लाभ के लिए दी गई थी, ताकि निर्धारित और अनुसरण की जा रही गैर क्षतिकारी कीमत (एन आई पी) निकाली जा सके। इस प्रकार से निर्धारित गैर क्षति कीमत की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना गई है, ताकि निम्नलिखित अनुसार क्षति मार्जिन निर्धारित किया जा सके :

क्र. सं.	उत्पादक देश	उत्पादक	पहुंच मूल्य (यू एस डॉलर/ मी. टन)	एन आई पी (यू एस डॉलर/ मी. टन)	पाटन मार्जिन (यू एस डॉलर/ मी. टन)	क्षति मार्जिन %	रेंज
1.	चीन	कोई भी	***	***	***	***	15-25

प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

81. प्रकटन पश्चात अनुरोधों का सारांश निम्नानुसार है :

क) घरेलू उद्योग के विचार

82 घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अनुरोध किया है :

- अन्य दो समर्थक छोटे आकार की कंपनियां हैं जिनके पास आवश्यक संसाधन नहीं हैं। चूंकि आंकड़े प्रस्तुत करने में काफी कार्य करना पड़ता है, इसलिए समय सीमा के भीतर संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके थे। तथापि, इन कंपनियों ने याचिका का समर्थन किया है। इन उत्पादकों ने अपनी सूचना प्राधिकारी को प्रस्तुत की है जो इन कंपनियों के कार्य निष्पादन को दर्शाएगी। यह केवल सांकेतिक समर्थन नहीं है बल्कि उनके कार्य निष्पादन के संबंध में संगत सूचना सहित समर्थन है। सूचना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि इन कंपनियों का भी नुकसान हुआ है।
- याचिकाकर्ता प्रकटन विवरण का पूरी तरह से समर्थन करता है जब याचिकाकर्ता ने कथित स्कीमों की मौजूदगी और पी यू सी के निष्पादकों पर उनके लागू होने को दर्शाया है तो लाभ प्राप्त करने की पूर्व भावना होनी चाहिए।
- इन स्कीमों को केवल इस कारण से अनदेखा नहीं किया जा सकता कि बाद में यह दर्शाने वाली कोई सूचना नहीं है कि इन स्कीमों का लाभ चीन के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा नहीं लिया गया है।
- होल्डर टोप्सा बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बताया है कि पाटन कानूनों में प्राधिकारी द्वारा असहयोग के सिद्धांत को कैसे अपनाया जाना चाहिए और इसे सब्सिडी पर भी असहयोगी निर्यातकों के लिए सर्वाधिक सी वी डी मार्जिन लागू करके अपनाया जाना चाहिए।
- अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों ने जहां निर्यातकों ने असहयोग किया है वहां यह निष्कर्ष निकाला है कि निर्यातकों ने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं किया। उदाहरण के लिए भारत के मूल के आर्थो क्लोरो पैरा नइट्रे एनीलिन के मामले में चीन द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम जिसमें सी वी डी मार्जिन 166.8% था और भारत से बड़े व्यास के बिल्डेड पाइपों के मामले में यू एस द्वारा जारी अंतिम जांच परिणाम जिनमें सी वी डी मार्जिन जी ओ आई और निर्यातकों के असहयोग के कारण 541.15% रखा गया था।
- प्राधिकारी को इन स्कीमों में से प्रत्येक के लिए सी वी डी मार्जिन वैसे ही निर्धारित करना चाहिए जैसे अन्य प्राधिकारी द्वारा वैश्विक रूप से किया जाता है।
- प्राधिकारी को या तो उपलब्ध तथ्यों (एफ ए) या ऐसी स्कीमों के उपलब्ध प्रतिकूल प्रभाव (ए एफ ए) जिन्हें प्रतिसंतुलन योग्य स्कीमों माना गया है (28 स्कीमों) के आधार पर सी वी डी मार्जिन पर विचार करना चाहिए

और पहले प्राधिकारी द्वारा कभी भी नहीं जांची गई स्कीमों (21 स्कीमों) या स्कीमों की समाप्ति अथवा सैकरीन के विनिर्माताओं पर उनके नहीं लागू होने के संबंध में चीन के उत्पादकों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जाने के आधार पर मार्जिन तय करना चाहिए। .

- viii. याचिकाकर्ता ने ऐसी 5 स्कीमों की मौजूदगी दर्शाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिनके मौजूद नहीं होने/समाप्त होने/ छोड़ दिए जाने का दावा किया गया है। प्राधिकारी को जी ओ सी द्वारा गुमराह किया गया है। इन स्कीमों की मौजूदगी या इन सब्सिडियों के अधीन लाभ के संबंध में प्रमाण याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।
- ix. चूंकि प्रकटन विवरण में निर्धारित सीवीडी की राशि निर्धारित क्षति मार्जिन से काफी अधिक है इसलिए याचिकाकर्ता निर्धारित सी वी डी मार्जिन अथवा स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता के संबंध में आगे कोई चिंता जताना नहीं चाहता है।
- x. यदि प्राधिकारी प्रकटन विवरण पर स्कीमों की प्रतिसंतुलन योग्यता अथवा सी वी डी मार्जिन की राशि के संबंध में वर्तमान में निर्धारित सी वी डी मार्जिन के बारे में पुनर्विचार करने का निर्णय लेते हैं तो याचिकाकर्ता ऊपर किए गए अनुरोधों पर प्राधिकारी से विचार करने का अनुरोध करता है। ऐसी अन्य स्कीमों में सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने का आग्रह करता है जिनमें वर्तमान में सीवीडी मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।
- xi. आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति का खतरा है। अत्यधिक क्षमताओं की मौजूदगी, उच्च निर्यातान्मुखता और सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है कि आयातों के भारी सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर बाजार में आने की संभावना है।
- xii. क्षति मार्जिन कीमत कटौती के लिए केवल क्षतिकारी सौदों पर विचार किया जाना चाहिए।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

83. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों का सार निम्नलिखित है:

- i. प्राधिकारी ने प्रकट किया है कि उत्तरदाता के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर रद्द किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं। यह कार्रवाई कुछ सूचीबद्ध आधारों पर की गई है। तथापि, उत्तरदाताओं के अनुसार इनमें से प्रत्येक गलत और अपूर्ण हैं।
- ii. वह समस्त सूचना जिसे प्राधिकारी “अपर्याप्त” पाते हैं उत्तरदाता के एक प्रश्न का मामला था जिसकी मांग नहीं की गई थी।
- iii. जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है कि निर्यातक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, परंतु निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में “प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी” होने का दावा किया है, यह अनुरोध है कि सही विवरण दिया गया है और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है। जैसा कि व्यापार लाइसेंस और निर्यातक प्रश्नावली उत्तर के साथ संलग्न कंपनी के शेयरधारक ढांचे में सिद्ध किया गया है।
- iv. जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है कि संयुक्त उद्यम भागीदार के ब्यौरे (इस सूचना सहित कि क्या वह भागीदार निजी स्वामित्व अथवा सरकारी स्वामित्व का है) निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में नहीं दर्शाए गए हैं, यह अनुरोध है कि प्रश्नावली के उत्तर में इस संबंध में कोई विशेष प्रश्न नहीं था। टिप्पणियों के साथ संलग्न दस्तावेज अब ये दर्शाते हैं कि मै. फॉरच्यून निटिंग फैक्ट्री लि. व्यक्तिगत हैं और राज्य स्वामित्व वाले उद्यम नहीं हैं।
- v. प्राधिकारी का कंपनी के कुल कारोबार के 57 प्रतिशत के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री का संदर्भ स्पष्ट नहीं है और इस संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध है। विचाराधीन उत्पाद की सबसे महंगी कच्ची सामग्री मेथानेसल्फोनेमाइट है। प्राधिकारी जांच की अवधि के दौरान मेथानेसल्फोनेमाइट की कुल क्रय राशि का विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कुल राशि के साथ पुनर्समाधान कर सकते हैं।
- vi. यह उल्लेख किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा कच्ची सामग्री अर्थात् एफ 1 और विचाराधीन उत्पाद के बीच वैब खोज सहित किसी भी स्रोत से कोई संबंध प्राप्त नहीं किया जा सका। तथापि, उत्तरदाता की निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि जो उत्पाद भारत को निर्यात किया

- गया था, (कैलिश्यम सैकरीन) वह किसी भी तरह कच्ची सामग्री के रूप में एफ 1 का उपयोग नहीं करता ।
- vii. इस प्रस्ताव के संबंध में कि दो आपूर्तिकर्ताओं में से एक का नाम निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में नहीं दिया गया है, उत्तरदाता इस अनदेखी को स्वीकार करते हैं । आपूर्तिकर्ता का नाम शंशाई नौचेंग फार्मास्यूटीकल कं. लि. है जोकि एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है- उत्तरदाता की निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रदर्श- 14 में प्रकट किया गया है ।
- viii. संबद्ध पक्षकारों के संबंध में प्रकटन टिप्पणी में उल्लिखितानुसार अपर्याप्त और विरोधाभासी सूचना स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं की गई है । एक स्पष्टीकरण माना जाना चाहिए था और अपर्याप्तता तत्काल पूरी की जा सकती थी ।
- ix. उत्तरदाता द्वारा दिए गए आंकड़े और डी जी सी आई एंड एस के पास उपलब्ध आंकड़े मेल खाते हैं । आंकड़े पूर्णतः विश्वसनीय हैं और किए गए वास्तविक लेनदेन को दर्शाते हैं । इस प्रकार प्राधिकारी का यह विवरण कि कीमत "'अविश्वनीय" है, अस्पष्ट है ।
- x. प्राधिकारी केवल इस कारण हमारी निर्यात मात्रा और कीमत को रद्द नहीं कर सकते कि वह भारत में समग्र चीनी निर्यातों की "अप्रतिनिधिकारक" प्रतीत होती हैं । हितबद्ध पक्षकार पर सब्सिडीयुक्त और क्षतिकारक कीमत पर निर्यात न करने के लिए दंड नहीं लगाया जा सकता । उत्तरदाता 2015, 2016 और 2017 के दौरान भारी मात्रा में निर्यात करने में मुख्य रूप से भारत द्वारा पाटनरोधी उपायों के कार्यान्वयन के कारण विफल रहे ।
- xi. डब्ल्यू टी ओ सीवीडी करार अथवा भारतीय सी वी डी नियमावली के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो प्राधिकारी को इस कारण प्रतिकारी शुल्क जांच में उत्तर को रद्द करने की अनुमति दे कि भारत को बिक्री की मात्रा अप्रतिनिधिकारक थी ।
- xii. उत्तरदाता ने 22 अप्रैल, 2019 को अपने आंकड़ों के सत्यापन की मांग करते हुए विस्तार में यह स्पष्ट करते हुए एक पत्र दायर किया था कि भारत में उसके उत्पादों की कीमत तीसरे देशों में उसके उत्पादों की कीमत तथा घरेलू बाजार में उसके उत्पादों की कीमत की तुलनीय हैं, जबकि मात्रा इतनी कम हो । इस पत्र और उनके अनुरोधों का प्रकटन विवरण में प्राधिकारी द्वारा उल्लेख भी नहीं किया गया है । भारत और तीसरे देश को किए गए निर्यात कीमत के संदर्भ में तुलनीय हैं ।
- xiii. प्राधिकारी ने पिछले तीन वर्षों में भारत को उत्तरदाता द्वारा निर्यातित मात्रा के प्रकाशन में भारतीय सी वी डी नियमावली और डब्ल्यू टी ओ एससीएम की गोपनीयता की अपेक्षाओं का पूर्णतः उल्लंघन किया है ।
- xiv. आयकर विवरणी 2017 और वैट विवरणी 2017 के लिए आंकड़े प्राधिकारी को दिए गए हैं और कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जिनको उत्तरदाता की 2017 की वार्षिक रिपोर्ट से जांच कर सत्यापित किया जा सकता है । प्राधिकारी ने यह गलत नोट किया है कि 2017 के लिए आंकड़े नहीं दिए गए हैं जबकि वे उन्हीं दस्तावेजों में प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं जिनका प्राधिकारी द्वारा उल्लेख किया जा रहा है ।
- xv. प्राधिकारी ने कभी भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगे हैं और साधारणतः उत्तर का मूल्यांकन करने में विफल रहे हैं । इस प्रकार, एक समयबद्ध तरीके से सूचना मंगाने में प्राधिकारी की विफलता उत्तरदाता की प्रतिभागिता का पूर्वाग्रह नहीं हो सकती और उपलब्ध मानदंड के तथ्यों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे सकते ।
- xvi. समर्थकों के आंकड़ों के मद्देनजर इस बात की जांच किए जाने की आवश्यकता है कि क्या याचिकाकर्ता को भी क्षति केवल उसी को है अथवा क्या वह व्यापक स्थिति में उद्योग को दर्शाती है । समर्थकों के आंकड़ों का अवलोकन यह दर्शाता है कि अन्य घरेलू उत्पादकों में जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता की अपेक्षा बेहतर निष्पादन किया । कोटेड पेपर फाइंडिंग्स का संदर्भ दिया जाता है ।
- xvii. हम यह नोट करते हुए हताश हैं कि प्राधिकारी ने अपनी जांच में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की सत्यता के संबंध में उत्तरदाता के तर्क पर भी विचार नहीं किया है । यद्यपि, उत्तरदाता का

अनुरोध पैरा-47 (xiii) में पुनः प्रस्तुत किया गया है। तथपि, प्राधिकारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

- xxviii. प्रयोक्ता ने अपनी प्रश्नावली के उत्तर में स्वीकार किया है कि संबद्ध सामानों का *** मी.ट. घरेलू उत्पादकों से खरीदा गया है और संबद्ध सामानों का केवल *** मी.ट. आयात किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित केवल अधुलनशील सैकरीन प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं को पास नहीं करता और घरेलू उत्पादों की विशेषताओं के साथ आयातित उत्पादों की तकनीकी विशेषताओं में अंतरों सहित प्रमुख प्रयोगशालाओं के नाम भी दिए गए थे।
- xix. यदि प्राधिकारी उत्तरदाता द्वारा उल्लिखित उत्पाद ग्रेड को सामान्य रूप से अलग करना नहीं चाह रहे हैं तो प्राधिकारी कृपया उत्तरदाता आयातक द्वारा आयातित अधुलनशील सैकरीन को अलग करें।
- xx. जब हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य घरेलू उत्पादकों के नाम दिए तो प्राधिकारी को चाहिए कि वे केवल यह मानने के बजाए अन्य उत्पादकों की मौजूदगी के रूप में स्वतंत्र जांच करें कि इस संबंध में कोई साक्ष्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा नहीं दिया गया है।
- xxi. समर्थकों द्वारा प्रपत्र एच को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे समयसीमा के बाद और यहां तक कि सुनवाई के बाद दायर किए गए हैं। किसी भी परिस्थिति में ऐसी सूचना को रिकॉर्ड में नहीं लिया जा सकता क्योंकि वह हितबद्ध पक्षकारों को उनकी टिप्पणियां पेश करने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई अवसर प्रदान नहीं करती।
- xxii. प्रपत्र एच पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.4 तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-ii के पैरा (iv) के तहत परिकल्पित किए गए अनुसार सभी अनिवार्य कारक शामिल नहीं करता। विशेष रूप से प्रपत्र-एच में मजदूरी, बाजार हिस्सा, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता, नकद प्रवाह पर नकारात्मक प्रवाह और घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में सूचना निहित नहीं होती।
- xxiii. समर्थकों ने "कीमत प्रवाह" के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है जोकि "मात्रात्मक प्रभाव" के साथ एक पूर्व शर्त है।
- xxiv. न तो घरेलू उद्योग और न ही प्राधिकारी ने समग्र रूप से उद्योग की कोई समेकित सूचना दी है।
- xxv. पक्षकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में कोई प्रभावी टिप्पणियां देने में असमर्थ हैं क्योंकि प्राधिकारी ने अपने दिनांक 7.9.2018 के व्यापार सूचना सं. 10/2018 के बावजूद मात्रा संबंधी सूचना को गोपनीय रखा है।
- xxvi. घरेलू उद्योग को चीन से तथाकथित सब्सिडीकृत आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

84. यह नोट किया जाता है कि प्रकटन पश्चात स्तर पर उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा पहले ही जांच कर ली गई है और उपर्युक्त संगत पैराओं में उचित रूप से उनका हल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त संगत पाए गए अतिरिक्त तर्कों को निम्नलिखित रूप में हल किया गया है :

- i. जहां तक इस तर्क का संबंध है, कि प्रश्नावली के उत्तर रद्द करने के लिए उल्लिखित कमियां गलत हैं और साधारण स्पष्टीकरण से हल की जा सकती थीं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर इस तथ्य के साथ प्रश्नावली के उत्तर में कई विसंगतियों और कमियों के कारण रद्द किया गया है कि निर्यात मात्रा और निर्यात कीमत खुद में प्रतिनिधिकारक प्रतीत नहीं होती। यह तर्क देते हुए कि निर्यात मात्रा और कीमत के कारण निर्यातक प्रश्नावली को रद्द करने का कानून में प्रावधान नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अलग बिक्री लेनदेनों में व्यापार की मात्रा तथा उत्पाद के लिए मांग कीमत के साथ-साथ दावे पर विचार करते समय पूरी तरह से अनदेखी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, यह पहली बार नहीं है कि प्राधिकारी ने निर्यात की मात्रा और कीमत को संदिग्ध पाया। उत्तरदाता निर्यातक की मात्रा और कीमत संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांचों की पहली निर्णायक समीक्षा में भी अनुपयुक्त थी, जिसे उपर्युक्त जांच में प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। प्राधिकारी के निर्णय को निर्यातक द्वारा चुनौती दी गई थी परंतु माननीय सेस्टेट द्वारा

उसे रोक दिया गया था। यह नोट किया जाता है कि निर्यातक ने अपनी कीमत और मात्रा का औचित्य बनाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया है। यह स्थिति कि उत्तरदाता निर्यातक संबद्ध सामानों के लिए औसत आयात कीमतों की तुलना में अधिक उच्चतर कीमतों पर भारतीय बाजार में बिक्री करने में समर्थ हैं, समझना कठिन है अथवा कोई व्यापारिक अर्थ निकालना कठिन है। निर्यात लेनदेन निर्यातक द्वारा सामान्य सिद्ध नहीं की किया जा सकता। इस कारक पर विचार करते हुए और वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें संबद्ध सामानों की औसत आयात कीमत की लगभग दुगुनी कीमतों पर नगण्य राशि का आयात किया गया है, प्राधिकारी निर्यात लेनदेन को अपने आप में अविश्वसनीय पाते हैं और उसे अलग सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि जब कुछ कमियों का उत्तरदाता द्वारा अपनी टिप्पणियों के माध्यम से उत्तर दे दिया गया है तो सब्सिडी की जांच करने के लिए संगत व्यवहारिक तथ्यों का भी उत्तर नहीं दिया गया है। एफ-1 का रासायनिक/व्यापारिक नाम भी प्रकट नहीं किया गया है। केवल यह तथ्य कि एफ-1 कैलिशियम सैकरीन का भाग नहीं है, जिसका भारत में निर्यात किया गया है, इस सूचना को मानने के लिए अपर्याप्त आधार है। इसके अतिरिक्त अन्य हितबद्ध पक्षकारों की मौजूदगी का तथ्य जिस पर घरेलू उद्योग ने जोर दिया है और चीन के हेनेन प्राविंस के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से नोटिस को उल्लिखित करते हुए वैब आर्टिकल के माध्यम से सिद्ध किया गया है तथा उसका खंडन नहीं किया गया है। सत्यापनीय साक्ष्य के साथ किसी खंडन के अभाव में प्राधिकारी इसे तथ्यों को वास्तविक रूप से छिपाने के रूप में मानते हैं।

- ii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि समर्थकों के आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसकी इस जांच परिणाम में संगत स्तर पर उचित रूप से जांच की गई है।
- iii. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के सही होने की जांच नहीं की गई थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा मानी गई घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना वर्तमान जांच में विधिवत सत्यापित सूचना है।
- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि समर्थकों द्वारा दायर प्रपत्र एच स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वे समय सीमा के बाद प्रस्तुत किए गए थे और क्योंकि उनमें क्षति विश्लेषण के लिए अपेक्षित पूरी सूचना नहीं है अतः यह नोट किया जाता है कि ब्लू सर्कल की सूचना घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई थी क्योंकि वह उस समानांतर जांच में दायर की गई थी जो इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के संबंध में की जा रही थी। इसके अतिरिक्त ए एस केमोफार्मा और वरदायनी कैमिकल्स द्वारा प्रपत्र- एच मांगे गए थे क्योंकि यह आरोप लगाया गया था कि अन्य उत्पादकों ने समर्थन किया है, तथापि उनके आंकड़े नहीं दिए गए हैं और यह कि क्षति पूर्णतः याचिकाकर्ता को है। इस प्रकार समर्थकों द्वारा प्रपत्र एफ पर कारणात्मक संपर्क विश्लेषण के लिए इस जांच परिणाम में विचार किया गया है और क्षति विश्लेषण के लिए उस पर विचार नहीं किया गया है।
- v. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा बेचे गए अघुलनशील सैकरीन अपेक्षित तकनीकी विशिष्ट को पास नहीं करते और इस प्रकार आयातक ग्रावर एंड वेल को अघुलनशील सैकरीन का आयात करना पड़ा, तथापि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक ने वस्तुतः उपर्युक्त आयातक को अघुलनशील बेचा। इसके अतिरिक्त किसी भी दशा में अघुलनशील सैकरीन विभिन्न अन्य उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है। इस प्रकार किसी भी किस्म के विचाराधीन उत्पाद को एक अंतिम प्रयोग के आधार पर पूर्णतः छूट नहीं दी जा सकती।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों से कोई सीवीडी कार्यक्रम संबद्ध अथवा अभिज्ञात नहीं किया है और न ही मात्रा के लिए कोई सिद्धांत दिया है, यह माना है कि "टायर केस" अथवा "स्टील केस" में पाई गई सब्सिडी यथातथ्यतः वर्तमान उत्पाद पर लागू है। भूमि के प्रयोग, कर योजनाओं तथा विद्युत के निमित्त लाभ के संबंध में यह तर्क दिया गया है कि अन्य मामलों में पाई गई सब्सिडी की मात्रा सीधे ही लागू नहीं की जा सकती। जहां तक कच्ची सामग्री का संबंध है, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री का नाम, माने गए निर्धारण और सी वी डी मार्जिन के परिकलन अभिज्ञात नहीं किए हैं। मूल कंपनी द्वारा प्राप्त/उपलब्ध अनुदान उत्पाद के उत्पादक पर लागू नहीं किए जा सकते। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध

पक्षकारों ने तर्क दिया है कि निर्यातक के प्रश्नावली के उत्तर उस स्थिति में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना है जहां प्राधिकारी ने उत्तर को रद्द करने का निर्णय दिया है।

vii. चूंकि जी ओ सी और चीनी उत्पादकों ने संगत सूचना अपने पास रखी अतः प्राधिकारी ने याचिका में उपलब्ध सूचना सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, चूंकि प्राधिकारी ने हाल ही में दिनांक 25 मार्च, 2019 की अधिसूचना फ. सं.6/8/2018-डी जी ए डी द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से "न्यू न्यूमेटिक टायर्स और बसेज एवं लॉरीज" के मामले में व्यापक जांच की है अतः उस जांच के रिकॉर्ड में सूचना/साक्ष्य का भी वर्तमान मामले में उपयुक्त रूप से संदर्भ दिया गया है। प्राधिकारी ने भारत से निर्यातों के संबंध में और उसमें उभरती हुई न्याय व्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्राधिकारों में अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा की गई जांचों को भी ध्यान में रखा है। प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं जिनमें याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि प्राधिकारी के लिए उस स्थिति में इन योजनाओं की प्रत्येक योजना में सी वी डी मार्जिन की मात्रा बनाना अथवा पुनः निर्धारित करना अपेक्षित नहीं था जिसमें विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों ने असहयोग को प्राथमिकता दी तथा घरेलू उद्योग ने 141.50 प्रतिशत की सीवीडी मार्जिन का दावा किया। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले से संबंधित तथ्यों और जहां तक व्यवहार्य है, उस सीमा तक भारत में की गई जांचों पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा केवल उस स्थिति में होता है जब वर्तमान मामले के रिकॉर्ड में सूचना अथवा विगत में भारत में की गई जांच में सूचना सी वी डी मार्जिन के निर्धारण के लिए पर्याप्त न हो, प्राधिकारी उपलब्ध अन्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अतः घरेलू उद्योग का तर्क स्वीकार नहीं किया जा रहा था।

viii. जहां तक अनुदानों के लिए निर्धारित सी वी डी मार्जिन का संबंध है, प्राधिकारी मानते हैं कि यह संबंधित

सब्सिडी मार्जिन के लिए विस्तृत औचित्य ऊपर 37 में दिए गए हैं

ix. जहां तक कच्ची सामग्री, कर, भूमि के प्रयोग के अधिकार और बिजली का संबंध है प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न योजनाओं, उनकी प्रतिकारिता और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों पर उनकी अनुप्रयोज्यता के संबंध में संगत सूचना दी है। याचिका की एक प्रति जांच की शुरुआत से पूर्व चीनी सरकार को उपलब्ध कराई गई थी। चीनी सरकार ने परामर्श में भाग लिया परंतु याचिकाकर्ताओं के दावों को असिद्ध करने के लिए कोई सत्यापनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किया। चीनी सरकार ने जांच की शुरुआत के बाद प्रश्नावली के उत्तर भी दायर नहीं किए। इस संबंध में प्राधिकारी मानते हैं कि सी वी डी मार्जिन की प्रतिकारिता और निर्धारण की जांच करने के लिए संगत सूचना चीन सरकार और चीनी उत्पादकों के पास है। जब इन पक्षकारों ने असहयोग को प्राथमिकता दी है तो प्राधिकारी के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सी वी डी मार्जिन निर्धारित करना अपेक्षित है। तदनुसार, उपलब्ध तथ्य के आधार पर इन योजनाओं में सब्सिडी मार्जिन निर्धारित किया गया है।

इन शीर्षों के तहत सब्सिडी मार्जिन के लिए विस्तृत औचित्य ऊपर 38, 39, 41 और 42 में दिए गए हैं

क्षति और कारण संबंधी निष्कर्ष

85. इस जांच परिणाम में यथा अभिलिखित उठाए गए मुद्दों और हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष दिए गए तथ्यों की जांच करने के बाद प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि:

- विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देशों से भारत को निर्यात सब्सिडीयुक्त मूल्य पर हुआ है जिससे उत्पाद का सब्सिडीकरण हुआ है।
- विचाराधीन उत्पाद के सब्सिडीकरण से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- यह वास्तविक क्षति संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण हुई है।

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश द्वारा विचाराधीन उत्पाद को लाभ पहुंचाने वाली प्रदान की जा रही सब्सिडियां और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच पर्याप्त कारणात्मक संबंध है।

भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्यतः प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य सब्सिडीकरण के अनुचित व्यापार व्यवहार द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं पक्षपात रहित प्रतिस्पर्धा कायम हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
88. यह माना जाता है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तु की लागत प्रभावित हो सकती है। तथापि, प्रतिसंतुलनकारी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी विशेष रूप से तब जबकि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के उपचार के लिए आवश्यक राशि तक सीमित हो। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण करने से सब्सिडीकरण की प्रक्रियाओं द्वारा अर्जित अनुचित लाभ कम होगा, घरेलू उद्योग का पतन होने से रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में सहयोग मिलेगा।

सिफारिशें

89. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई और उसकी सूचना चीन जन. गण. की सरकार समेत सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान की गई थी और सब्सिडीकरण, क्षति एवं कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमों के अनुसार सब्सिडीकरण, क्षति एवं उनके कारणात्मक संबंध के बारे में जांच शुरू और संपन्न करने के बाद और सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन तथा ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति की पुष्टि करने के उपरांत प्राधिकारी का यह मत है कि सब्सिडीकरण एवं क्षति को समाप्त करने के लिए निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी नीचे दिए गए ढंग और तरीके से चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।
90. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन, इनमें से जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, चीन जन. गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित शुल्क तालिका के कालम 6 में यथा उल्लिखित आयातों के पहुंच मूल्य के प्रतिशत के रूप में निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तुओं का वर्णन	मूलता/निर्यात का देश	उत्पादक	सीआईएफ मूल्य के % रूप में शुल्क राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	29251100	अपने सभी रूपों में सैकरीन	चीन	कोई	20

91. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथानिर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी शुल्क शामिल होंगे।
92. केन्द्र सरकार द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम पर आधारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****FINAL FINDING NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th June, 2019

Case No. CVD - 05/2018

Subject: Countervailing/ Anti-Subsidy Duty investigation concerning imports of “Saccharin” originating in or exported from People’s Republic of China.

F. No. 6/18/2018- DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter also referred to as the “Rules”) thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Whereas, M/s. Swati Petro Products Private Limited (hereinafter also referred to as the “Petitioner” or “Applicant”) filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) seeking initiation of anti-subsidy investigations and imposition of anti-subsidy duties in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time for imposition of Anti-Subsidy duty on imports of “Saccharin” originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the Petitioner, issued a public notice vide Notification No. 6/18/2018 – DGAD dated 10th August, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged injury caused to the domestic industry due to the subsidization of the subject goods, originating in or exported from the subject country, and to recommend the amount of anti-subsidy duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a) The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of the anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (2) Rule 7 of Rules.
 - b) The Authority invited the Government of China PR (hereinafter also referred to as “GOC”) for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). The consultation was held on 20th July, 2018 in New Delhi, which was attended by the representatives of the GOC.
 - c) During the consultations, the GOC claimed that the evidence in the petition was incomplete in certain critical respects, the alleged subsidy schemes/ programs have already been rescinded and the Authority should not consider the petition for initiating the investigation. Post-consultation, GOC submissions which have been summarised in appropriate paragraph in this notification.
 - d) The Authority notes that the GOC did not provide any substantiated evidence in support of their claims made during the pre-initiation consultations.

- e) The Authority considered the petition and the contentions of the GOC and held that it was appropriate to initiate and conduct countervailing duty investigations in order to determine whether the producers/exporters of the product under consideration were benefited from countervailable subsidies and, whether such subsidized imports were causing injury to the domestic industry and if so, whether it is appropriate to recommend imposition of countervailing duty measures (hereinafter referred to as "CVD" or "anti-subsidy duty") on imports of the Product Under Consideration (hereinafter also referred to as "PUC") from China PR and if so, to determine the quantum of CVD that should be imposed on the imports of the product under consideration.
- f) The Authority issued a notification on 10th August, 2018, published in the Gazette of India, extraordinary, initiating anti-subsidy/countervailing duty investigations.
- g) The Authority sent a copy of the initiation notification dated 10th August, 2018 to the Embassy of China PR in India, known producers/exporters from China PR, known importers/users in India, other Indian producers of subject goods and the domestic industry as per the addresses made available by the petitioner and advised them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- h) The Embassy of China PR in India was requested to advise the producers/exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to the Embassy of China PR along with the names and addresses of the known producers/ exporters from China PR.
- i) The Authority provided a copy of the Non-Confidential Version (hereinafter also referred to as "NCV") of the application to the known producers/exporters from China and to the Embassy of China PR in accordance with Rule 7(3) of the Rules .
- j) The Authority sent a questionnaire to the GOC seeking relevant facts/information with regard to various schemes/programs where countervailable benefit might have been conferred onto the producers/exporters of the product under consideration The GOC has refrained from filing any questionnaire response.
- k) The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/ exporters in the subject country in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - (i) M/s. Suzhou Fine Chemicals Group Company Ltd.
 - (ii) M/s. Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd.
 - (iii) M/s. Kaifeng Xinhua Fine Chemicals
 - (iv) M/s. Tianjin Changjie Chemical Co. Ltd.
 - (v) M/s. PMC Beijing Chemical Co. Ltd.
- l) In response, only Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd has filed Exporter's Questionnaire response in the prescribed format.
- m) The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rules:
 - 1) Eagle Trading Company
 - 2) Colgate Palmolive India Ltd.
 - 3) General Import Co. India
 - 4) Jagmohandas & sons
 - 5) C J Shah & Co.
 - 6) Nectar Drugs P Ltd

- 7) Procter & Gamble Hygiene and Health
 - 8) Neeru Marketing P Ltd
 - 9) Speciality Chemicals
 - 10) Nandial Bankatlal Pvt. Ltd.
 - 11) Sun Shine Cosmetics Ltd.
 - 12) Grauer & Weil (India) Ltd.
 - 13) Sandeep Organics
- n) Only M/s. Grauer and Weil (India) Ltd. has responded with questionnaire response.
- o) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- p) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (hereinafter also referred to as “DGCI&S”) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- q) The Non-Injurious Price (hereinafter also referred to as “NIP”) based on the cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (hereinafter also referred to as “GAAP”) has been worked out so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic Industry.
- r) Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present Final Finding.
- s) Verification of the information provided by the producers/exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and has been relied upon for the purpose of present Final Finding.
- t) The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from 1st April, 2017 to 31st March, 2018 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
- u) In accordance with Rule 7(6) of the Anti-Subsidy Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 22nd January, 2019. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals.
- v) The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this Final Finding.
- w) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- x) Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of the facts available.
- y) A Disclosure Statement was issued to interested parties on 06.06.2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 14.06.2019 to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- z) The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1=₹65.33

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”.

Submissions made by the Domestic Industry

5. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:
- a) Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be a low calorie substitute for cane sugar. It is a white crystalline powder form and is odourless. Saccharin is more than 500 times sweeter than sugar. Saccharin can be divided into two types, *i.e.*, soluble and insoluble Saccharin.
 - b) Saccharin is produced in two physical forms that is, granular and powder. Sodium Saccharin in granular form is used in situation where Saccharin will be dissolved powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals.
 - c) Saccharin can be used for a variety of industries such as food and beverages, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, etc. The difference in Saccharin, industrial Saccharin and for food and beverages is the purity of the Saccharin.
 - d) Alleged differences regarding the specifications of the imported product and that produced by the domestic industry have been claimed confidential without sufficient justification. In any case, the responding importer has itself been a regular buyer of the products of the domestic industry which indicates that there is no change in the product produced by the domestic industry and imported by the importer.

Submissions made by the other interested parties

6. Following submissions have been made by the other interested parties with regard to product under consideration and like article.
- a) The product sold by the domestic industry has different specifications and does not match requirements of the user industry.

Examination by the Authority

7. The product under consideration in the present investigation is “Saccharin in all its forms”. “Saccharin is a non-nutritive sweetener and considered to be low calorie substitute for cane sugar. Primarily there are two types of Saccharin *i.e.* soluble and insoluble. In market parlance soluble saccharin is called sodium saccharin whereas insoluble saccharin is called saccharin or saccharin acid. Saccharin is produced in two physical forms, *viz.* granular and powder. Sodium saccharin in granular form is used in situations where saccharin will be dissolved, the powder form which has been grounded and spray dried is used in dry mixes and pharmaceuticals. It is slightly soluble in water. Insoluble form of saccharin is used in many pharmaceutical and medical applications. Saccharin is used in a variety of industry such as food and beverage, personal care products, table top sweeteners, electroplating brighteners, pharmaceuticals, etc. All forms of Saccharin are within the scope of the present investigation.

8. Saccharin is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheadings No. 29251100. However, import of subject goods takes place under several other tariff sub-headings as well. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigations.
9. With regard to the claim on specifications of the product imported from the subject country being different from that of the product being manufactured by the petitioner, the Authority notes, that no evidence has been provided by the interested parties substantiating such argument. Further, the petitioner has placed on record in this regard, the sales invoices for the subject goods sold to the responding party which clearly establishes that the responding party has on multiple occasions procured the subject goods from the petitioner as well. This establishes the fact that the subject goods are being interchangeably used by the consumers.
10. After considering the information on record, the Authority considers that there is no known difference in product under consideration exported from the subject country and the subject good produced by the domestic industry. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the subject goods exported from subject country in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
11. The Authority holds that the subject goods produced by the applicant domestic industry are like article to the product under consideration exported from the subject country, in accordance with the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by the Domestic Industry

12. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to scope of domestic industry & standing are as follows:
 - a) The application has been filed by M/s. Swati Petro Products Private Limited. The applicant has not imported nor is related to any importer or exporter of the subject goods. The application has been supported by M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Pvt. Ltd, M/s. A.S. Chemopharma Pvt. Ltd and M/s Blue Circle Organics Pvt. Ltd.
 - b) To the best of the petitioner's knowledge and as per the market intelligence, there exist only 4 other producers in the country apart from the petitioner itself namely, M/s Blue Circle Organics, M/s. AS Chemopharma Pvt. Ltd., M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Ltd. and M/s. Vishnu Chemicals. M/s. Blue circle, M/s. AS Chemopharma and M/s. Shree Vardayini have already expressed their support to the petition. In any case, the share of those producers who have provided injury data exceeds 50%. The Authority has itself conducted 3 investigations on the subject goods in past and undertook an investigation on subject goods from Indonesia. It was observed that these are the only producers of subject goods in the Indian market. None of the other producers have responded to any of the investigation. Other named producers are likely to be traders or are producers who merely process saccharin further.
 - c) Since information of one of the supporters, M/s. Blue Circle Organics Pvt. Ltd., was placed on record for an anti-dumping investigation against imports of the same product from Indonesia, the same has been filed in the present investigation also for the sake of consistency. However, M/s. Blue Circle Organics Pvt. Ltd. has imported 23 MT of the subject goods. The Authority may consider the scope of the same for the purpose of standing.
 - d) M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Pvt. Ltd., M/s. A.S. Chemopharma Pvt. Ltd. are small scale companies and have supported the petition.

- e) The combined information for Blue Circle and Swati Petro Products Pvt. Ltd. shows injury being suffered by the domestic industry in the POI. For sake of clarity, injury statement considering (a) Swati Petro as the domestic industry and (b) Swati Petro and Blue Circles as the domestic industry has also been submitted.
- f) Petitioner alone constitutes a major proportion of total Indian production under the Rules and agreement. There is no benchmark as to what can be considered as a major proportion. WTO jurisprudence and past cases of the DGTR prove that even below 50% is a “major proportion”. Reference is laid on WTO Panel Report on Argentina – Definitive anti-dumping duties on Poultry from Brazil.
- g) The Authority has also considered proportion less than 50% as a major proportion of total Indian production in the past. Interested parties have argued existence of other producers based on website extracts. Website extracts of some of the companies’ shows a long list of products. These named producers are likely to be traders of the subject goods or are producers who merely process saccharin further. Authority may kindly seek relevant information from the concerned department and may also seek information from the alleged producers of subject goods.

Submission of other interested parties

13. Other interested parties have made the following submissions:

- a) Deliberate selection of M/s. Swati Petro Products Pvt. Ltd. as sole petitioner is for magnifying injury to the domestic industry. Petitioners in the previous investigations have opted not to file an application for the present investigation. There has been clear cherry picking for the present investigation only to magnify that M/s. Swati Petro Products Pvt. Ltd. is suffering injury.
- b) Petitioner does not constitute "domestic industry" and has conveniently stated its share as 30% based on only 5 producers. It has ignored the existence of at least 11 other producers identified by respondent. It is highly unlikely that the petitioner constitutes a major proportion of total Indian production. This figure is bound to be lower after consideration of all other Indian producers. Such a share as claimed is insufficient to consider a major proportion.
- c) The Authority is required to seek data of supporters also as filing petition on behalf of the domestic industry by those with limited share along with simple support letters of major producers has become the norm.
- d) Claims on the number of producers was misleading; another oral hearing be granted after determination of standing.
- e) Discriminatory selection of domestic producers – M/s. Blue Circle has a capacity about 5 times that of the petitioner while M/s. Vishnu alone has a capacity twice of the petitioner yet the same have not been considered as petitioners. While it was claimed that other small scale producers are not capable of filing complex proforma, the very same producers were constituent domestic industry in the previous investigations for the subject country.
- f) As regards the eligibility of importer producers, Authority is of the view that it has discretion under the Anti-Dumping Rules but not under the CVD Rules. Such an interpretation would lead to certain anomalies and absurdity which need to be avoided. Definition in the two statutes have to be read in the context of the entire scheme and not in isolation particularly when different terms exist in the two parallel provisions. The word ‘shall’ under CVD rules have to be read as ‘may’ to ensure that the interpretation is harmonious.
- g) Decision of the Authority that "the petitioner with its other supporters constitutes major share of Indian production and petitioner meets the requirement of the standing in terms of Rule 2(b)" is legally erroneous. Petitioner itself admits that it constitutes a major share of the Indian production

only when the information relating to the supporters is taken into account. Conclusion of the Authority that the petitioner itself "meets the requirement of the standing in terms of Rule 2(b)" is contradictory to the previous statement. It follows that if the major share of the domestic production is constituted of the production of the petitioner as well as the supporters, the domestic industry also ought to be defined taking into account the production of the said supporters.

- h) The Authority has to ensure that the state of the selected domestic industry is reflective of the entire industry of that product in India. "Major proportion" test is not purely mathematical wherein upon reaching a specified number domestic producers would automatically constitute domestic industry. Reference laid on WTO Appellate Body in EC – Fasteners (China) Case wherein it was stated that "a major proportion" should be understood as "a relatively high proportion that substantially reflects the total domestic production" and should have "both quantitative and qualitative connotations." A test that would be purely quantitative would not necessarily ensure that the domestic industry defined on that basis substantially reflects the total domestic production.
- i) In the present investigation M/s. Blue Circle is being considered relevant for one investigation and not for the other even when the period of investigation remains identical for both investigations. Further, the injury determination for both the investigations is also done under the same provision of the Act.
- j) Domestic industry has arbitrarily excluded other Indian producers from the purview of the domestic industry even when they have supported the application. Reference is laid on Trade Notice No. 13/2018 dated 27.09.2018.
- k) Domestic producers have brought forward the most inefficient industry and the state of other Indian producers is different from the domestic industry as is evident from the email dated 21.01.2019.

Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of CVD Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".

- 15. The present application was filed by M/s. Swati Petro Products Private Limited and supported by M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Private Limited, M/s. Blue Circle and M/s. A.S. Chemopharma Private Limited.
- 16. During the course of the investigation, M/s. Blue Circle Organics placed on record its complete information vide letter dated 10th August, 2018. The examination of the submissions revealed that M/s. Blue Circle Organics Pvt. Ltd. has imported 23 MT of the subject goods from the subject country. The Rule 2 (b) of the CVD Rules categorically states that producers who are themselves importers of subject goods shall not form part of the domestic industry. The Rules do not allow for a discretionary approach to be taken by the Authority. Therefore, Authority decided that M/s. Blue Circle Organics Pvt Ltd is not part of the eligible domestic industry. A communication to this effect that M/s. Blue Circle is outside the scope of domestic industry for the purpose of the present investigation was sent to all the stakeholders' post oral hearing.
- 17. As regards, the claim regarding existence of other domestic producers who have not been considered as a part of the investigation, the Authority notes that no evidence has been provided to show that other producers, in fact, produce subject goods. Further, none of the other producers have come forward to either support or oppose the investigation being conducted. In several anti-dumping investigations have been conducted by the Authority including the recently concluded anti-dumping investigation against the

imports of subject goods from Indonesia and no evidence was put forward that the domestic market has any other producers of subject goods. In view of the above, the Authority holds that the known domestic producers of subject goods are M/s. Swati Petro Products Private Limited (petitioner), M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Private Limited, M/s. Blue Circle and M/s. A.S. Chemopharma Private Limited and M/s. Vishnu Chemicals Ltd.

18. The Authority has determined the share of production by the petitioner in total Indian production. It is seen that the share of petitioner is 56 % excluding M/s. Blue Circle's production from total Indian production. Further the share of petitioner's production is 32 % after including M/s. Blue Circle's production in total Indian production. The Authority notes that the petitioner constitutes "a major proportion" of total Indian production in either situation. Further, the petitioner has neither imported subject goods nor is related to any producer or exporter thereof. It is also noted that the petition has been supported by M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Private Limited, M/s. Blue Circle and M/s. A.S. Chemopharma Private Limited. These supporters have also submitted their injury information.
19. In view of the above, the Authority holds that the petitioner satisfies the standing requirement in terms of the Rule 6(3) of the CVD Rules and constitutes the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the CVD Rules.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by domestic industry

20. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- (i) Undue confidentiality has been claimed by the exporter. M/s. Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd. is also known as "M/s. Shanghai Fuxin Chemical Co". This fact was however not disclosed in the questionnaire response. M/s. Shanghai Fuxin Chemical Co. further has an affiliated company in the Xinsi community, known as "Shanghai Fuxin Chemical Xinsi Branch", which has a different address to the headquarters and is involved in trading of the subject goods.
- (ii) M/s. Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd has been acquired by M/s. Kaifeng Xinghua Fine Chemical Co. Ltd, which in turn, is a subsidiary of the Pingmei Shenma Group.
- (iii) The company's factory address was relocated in 2009, to the "Shanghai Chemical Industry Park" which is an industrial zone, primarily specializing in petrochemical and chemical businesses and is operated by Shanghai Municipality on behalf of the Central Government.
- (iv) Exporter has preferred to completely avoid answering any of the issues raised by the petitioner domestic industry.
- (v) On allegations made in context of the initiation of the investigation being bad in law, it is submitted that the Authority on the basis of prima facie evidence submitted to it initiated the investigation against the subsidized imports of the subject goods from the subject country. However, the same is only on the basis of the prima facie evidence submitted to the Authority. It is for the other interested parties contending the claim to prove otherwise by way of evidence.
- (vi) The domestic industry has claimed confidentiality in accordance with Rules and trade notices issued and the importer has practically given nothing in its questionnaire response. Complete blank pages have been provided by them. The importer claimed that the product sold by the domestic industry has different specifications and does not match requirements of the user industry. However, the alleged differences have been treated as confidential without any justification or rational reasons.

- (vii) Information submitted with the Authority is within the purview of the Rules and the investigation has been initiated by the Authority only after it satisfied itself on the sufficiency of the claims of confidentiality. It cannot be said that excessive confidentiality has been claimed when the exporter itself has claimed excessive confidentiality in its own response filed.
- (viii) The importer has practically given nothing in its questionnaire response. Complete blank pages have been provided by them. Importer claimed that the product sold by the domestic industry has different specifications and does not match requirements of the user industry. Alleged differences have been treated as confidential without any justification or rational reasons.
- (ix) The performance of the domestic industry has undergone significant change from the previously concluded SSR investigation. The domestic industry is suffering material injury in the present POI on account of subsidized imports.
- (x) Vide letter dated 13th November, 2018, the domestic industry had already placed revised import statistics on the basis of transaction-wise import data of DGCI&S. The application was initially filed on the basis of the DGCI&S data procured up to the period January, 2018 which was further annualized for the period up to March, 2018 to cover the POI. Upon procurement of the DGCI&S data for the entire POI the same was duly filed vide the above mentioned letter. The domestic industry circulated the same data already filed with the Authority before the oral hearing. Even the revised data does not show any material change from the original data filed.

Submissions made by other interested parties

21. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a) EQR filed by respondent is complete and accurate and no subsidies were availed by the respondent.
- b) Initiation is bad in law as the data provided by the petitioner is not accurate and adequate. The investigation was initiated on the basis of incorrect and self-serving information without satisfying the requirements of rule 6.
- c) Revised data filed on 21st January is at a belated stage while no explanation provided for the difference between import data filed earlier and the revised data for the period 2014-15, 2015-16 and 2016-17. Revised data on economic parameters of the domestic industry has not been provided. Such non provision of data is a violation of Rules 6.1, 6.2 and 9.
- d) The anti-dumping duty on the subject goods has already been in force for over 10 years and the domestic industry has received adequate protection. The previous ADD was in force till 12th January 2018 and it is not understandable how within a span of six months domestic industry has started suffering injury again.
- e) Excessive confidentiality has been claimed - Information relating to total Indian Demand; Information pertaining to the market share; Information pertaining to the production and sales of other Indian producer; Information pertaining to Costing of the applicant industry; costing information in the petition. Industry is required to furnish the non-confidential summary of such costing information; Certain other key information has been kept confidential setting new low standards of unwarranted and illegal claims of confidentiality.

Examination by the Authority

22. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- a) The Authority initiated the present investigation after satisfying itself regarding the sufficiency of the prima facie evidence provided by the domestic industry. Further, elaborate discussions and consultations were held with the applicant as well as the Embassy of the subject country and upon satisfying itself on prima facie basis as regards to the existence of subsidies in China PR which were resulting in the unfairly prices and subsidized imports causing injury to the domestic industry the Authority initiated the present investigation.
- b) As regards to the claims of excessive confidentiality, the Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims where warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. The parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of that information.
- c) As regards the contention on the existence of other related parties, the exporter could not provide any evidence to counter the domestic industry's claim.
- d) As regards the contention that anti-dumping duty was in existence for a period of 10 years and thus the claimed injury is incomprehensible, the Authority notes in this regard that the POI covered in the earlier SSR anti-dumping investigation against imports from China was 'July 2015 to September 2016' and the POI considered in the present investigation is completely different i.e., 'April 2017 to March 2018'. The Authority has independently investigated the present petition and facts and circumstances of the present investigation is unique as well as different than the previous ADD investigations.

F. ASSESSMENT OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN – METHODOLOGY AND PARAMETERS

23. The petition filed by domestic industry provided prima facie evidence of existence of countervailable subsidies in the subject country. GOC was invited for consultation, which was held on 20th July, 2018 in New Delhi. The claims of the petitioners were disputed by GOC, however, no documentary evidence showing either withdrawal of these schemes or their non-applicability to the producers or exporters of saccharine in China PR was put as record. Post consultations, the GOC filed the written submissions which have been summarised as below:

- a) *The petition failed to provide production data of the PUC such as the total number of producer of the PUC, the number of supporters as well as the opponents etc. Therefore, the standing of the petitioners cannot be established.*
- b) *The petition failed to provide authoritative data of relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry to prove injury and threat of injury, such as capacity, production, cost, profit, employment, productivity, wages, inventory, market share, utilization of capacity, demand, return on capital, etc. Since the petition failed to adduce sufficient evidence, the injury analysis is seriously flawed.*
- c) *It is also mentioned by GOC that some of the importers of PUC in the petition are from the industry of the welded stainless steel pipes and tubes of India. Therefore, the CVD will hurt these importers as well as the development of the welded stainless steel pipes and tubes industry, and cause adverse effects on Indian national economy.*
- d) *The petitioner failed to provide evidence of actual existence, amount and specificity of subsidy programs. As such, the petition could be evidently concluded as "simple accusation without substantiation".*

- e) *The anti-subsidy cases quoted in the petition were based on Adverse Fact Available, “AFA”, or Best Information Available, “BIA” and do not reflect the reality. It is also noted that there is WTO’s ruling in DS379, the determination in one case cannot be deemed as reasonable and sufficient explanation of another case. Therefore, the citations in current petition cannot be deemed as anti-subsidy evidences for initiating investigation.*
 - f) *Certain alleged programs are not administered by public bodies. A commercial entity cannot possibly perform governmental functions while conducting commercial activities, and thus could not be the party conferring subsidies.*
 - g) *There are certain Chinese laws, regulation and policies used as evidence of allegation have expired or do not exist.*
 - h) GOC also submitted comments on some specific alleged subsidy programs. As a whole, these comments contain submissions relating to para (d) to (g) above. It is further noted that initiation notification states Program No. 52 as ‘Raw material for less than adequate remuneration /inputs/services’ while GOC has instead given specific comments for “*Provision of Electricity for Less than Adequate & Fair Market Value Remuneration,*” GOC has not given any specific submission with respect to the above said alleged program relating to raw material.
24. No documentary evidences in support of above submissions have been provided to the Authority by GOC.
25. Post initiation, the GOC and producers/exporters from China PR were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
26. The GOC has not filed any questionnaire response, M/s Shanghai Fortune Chemical Co. Ltd. (SFCCL), China PR had filed its questionnaire response. The questionnaire response filed by the said exporter was examined and the Authority holds that the same cannot be accepted for the following reasons:
- a) The company has stated that its legal structure is Private Limited Company. While it has been found in its EQR that it is a “Limited Liability Company (joint venture between Taiwan, Hong Kong and Macau and China)” and the details of the joint venture partners (including the information whether such partner is privately-owned or state-owned) has not been revealed in the EQR.
 - b) The corporate ownership structure given in the EQR is not complete, as the details of shareholders of its parent company, M/s. Fortune Knitting Factory Ltd. (a foreign enterprise who holds 96% shares in SFCCL) have not been mentioned.
 - c) In its EQR, the company has not provided in English translation the name of a raw material which alone accounts for 57% of the total turnover of the company. Moreover, the name of a Calcium Carbonate supplier has not been provided in English translation. Further, the EQR states “F1” as a raw material of the PUC. However, no relationship between F1 and saccharin could be found by the Authority from any source including web search.
 - d) Thus, insufficient and contradictory information in respect of related parties have been presented to the Authority by M/s. SFCCL.
 - e) The company has exported only ***, ***, and *** MT during 2015, 2016 and 2017 respectively. Therefore, the export volume of the subject company is not representative and the price thereof cannot be relied upon having regard to the volume and price of imports in India.
 - f) The company has mentioned in its EQR that it is providing VAT tax return and corporate income tax return of 2017. While actually it has supplied VAT tax return only for the month of Dec-2017 and

the corporate income tax return only for the fourth quarter of 2017. Moreover, the submitted VAT tax return states the industry to be “tyre manufacturing” while the corporate income tax return in Exhibit-13 states the industry to be “sugar industry”.

- g) The average export price of SFCCL is more than double the average export price of subject goods from China during the POI as per the DGCI&S data.

27. There is no other response from any other Chinese producer’s exporters.

28. The following submissions have been made by the domestic industry:

- a) The domestic industry has contended that the GOC is providing countervailable subsidies to its producers/exporters of the subject goods and has provided prima facie evidence of existence of such subsidy schemes in terms of legislation and policy documents. The domestic industry has identified existence of several countervailable subsidy schemes in China PR, within the meaning of ASCM and Indian Laws, Rules and have contended that the producers/exporters of subject goods in China PR have benefited from such subsidies.
- b) The programs of the GOC and other Public Bodies in China PR constitute a subsidy because of the following reasons:
 - (i) There is a financial contribution by Government or a public body, where the Government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), Government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
 - (ii) Benefit is thereby conferred on the Chinese producers/ exporters of the PUC; and
 - (iii) The program is specific within the meaning of Indian Rules and ASCM.
- c) Relevant Chinese laws and regulations, WTO reports, various Government reports, media reports and independent studies and analysis, findings of other investigating agencies in their anti-subsidy investigations clearly constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in China PR. These evidences were made available by the petitioner to all interested parties, including the GOC and the known producers and exporters in China PR.
- d) For the purpose of this investigation, the "Government of People’s Republic of China" covers all levels of government, *i.e.* Federal, Central, Provincial, Regional or Local Government such as Municipal or City or Township Government Village or Local legislative, administrative or judicial agencies/bodies; and State-owned enterprises, operating under the direct or indirect control or influence of the GOC which operate as ‘public bodies’ within the meaning of the term as defined in the ASCM.
- e) As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs at various levels of Government. The same have been classified under following six broad categories:
 - I. Grants
 - II. Tax and VAT incentives
 - III. Provision for Goods and Services
 - IV. Loans
 - V. Export Credit financing
 - VI. Provision of Goods and Services

Subsidy schemes as considered in the notice of initiation

29. In the notice of initiation, the Authority identified the following potential CVD program that may be relevant to the present investigations:

I. Identified Programs in the Form of Grants in China PR

- i. Program No. 1: The State Key Technology Renovation Projects Fund
- ii. Program No. 2: Famous Brands Program
- iii. Program No. 3: Grants for Anti-Dumping Investigations
- iv. Program No. 5: Export Assistance Grant
- v. Program No. 6: Grants for Listing Shares
- vi. Program No. 7: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province
- vii. Program No. 8: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
- viii. Program No. 9: Various grants provided to Fuyang City
 - a. Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
 - b. Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
 - c. Grants under Excellent New Products/Technology Award
 - d. Investment grants from Fuyang City Government for key industries
 - e. Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
 - f. Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
 - g. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
- ix. Program No. 10: International Market Fund for Export Companies
- x. Program No.13: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
- xi. Program No. 14: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises.
- xii. Program No. 15: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
- xiii. Program No. 16: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
- xiv. Program No. 17: Enterprise Development Funds
- xv. Program No. 18: Direct Government Grants given by Jiangsu Province
- xvi. Program No. 19: Grants under the Science and technology Program of Jiangsu Province
- xvii. Program No. 21: Environment Protection Award (Jiangsu)
- xviii. Program No. 22: Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund (Jiangsu)
- xix. Program No. 23: Changzhou Technology Plan (Jiangsu)
- xx. Program No. 24: Enterprise Innovation Award of Qishuyan District (Jiangsu)
- xxi. Program No. 25: Support Funds for Construction of Project infrastructure
- xxii. Program No. 26: Administration Commission of LETDZ (Jiangsu Province)

- xxiii. Program No. 27: Accelerated Depreciation on Fixed Assets in Binhai New Area of Tianjin
- xxiv. Program No. 28: Enterprise Technology Centers (e.g. Tianjin City and Jinnan District)
- xxv. Program No. 29: Award for Maintaining the Growth by Beijing Governments
- xxvi. Program No. 30: Award by Beijing Technology Trading Encouraging Centre

II. Identified in form of Tax and VAT incentives

- xxvii. Program No. 33: Two Free/Three Half Program for Foreign Invested Enterprises
- xxviii. Program No. 34: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs / Income tax benefit for FIEs based on geographical location
- xxix. Program No. 35: Tax Offsets for Research and Development at FIEs
- xxx. Program No. 36: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investor
- xxxi. Program No. 38: Preferential Income Tax Policy for Enterprises in the Northeast Region
- xxxii. Program No. 39: Preferential Tax exemptions for Central & Western Regions
- xxxiii. Program No. 40: Tax Policies for the deduction of Research and Development (R&D) expenses
- xxxiv. Program No. 42: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
- xxxv. Program No. 43: VAT and Tariff Exemptions for Purchases of Fixed Assets
- xxxvi. Program No. 44: VAT and Tariff Exemptions on Imported Equipment for Favored Industries
- xxxvii. Program No. 45: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
- xxxviii. Program No. 46: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- xxxix. Program No. 47: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
- xl. Program No. 48: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- xli. Program No. 49: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- xlii. Program No. 50: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas

III. Identified in form of provision for Goods and Services

- xliii. Program No. 52: Raw material for less than adequate remuneration /inputs/services

IV. Identified in form of loans

- xliv. Program No. 53: Policy Loans

V. Identified in form of Export Credit financing

- xlv. Program No 55: Export Credit Subsidy Programs
- xlvi. Program No. 56: Export Seller's Credits from Export-Import Bank of China- Credit Borrowing
- xlvi. Program No 57: Export Buyer's Credit from Export-Import Bank of China

- xlvi. Program No.58: Export Credit Insurance from the China Export and Credit Insurance Corporation
- xlix. Program No. 59: Preferential Export Financing from the Export-Import Bank of China.
 - 1. Program No 60: Provision of Credit Lines
 - ii. Program No. 61: Preferential loans provided by the Export-Import Bank "going out (global)" strategy for outbound investment

VI. Identified in form of equity infusions

- lii. Program No. 64: Debt for equity swaps
 - liii. Program No. 65: Equity infusions
 - liv. Program No. 66: Unpaid dividends
30. After the consultation and examination of the schemes as provided in the petition, it was noted that the petitioner has provided insufficient evidence with regard to the following schemes showing any linkage to the subject goods or to the producers of subject goods. These schemes have therefore been dropped from the scope of present investigation at the stage of initiation itself.

I. Identified Programs in the Form of Grants in China PR

- i. *Research & Development (R&D) Assistance Grant*
- ii. *Project funds allowance*
- iii. *Special Fund for Energy Saving Technology Reform*
- iv. *Superstar enterprise grant*
- v. *The Clean Production Technology Fund*
- vi. *Grants for High and new technology industries*

II. Identified in form of Tax and VAT incentives

- i. *Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies/ Enterprise Income Tax Reduction for High and New Technology Enterprises*
- ii. *Tax Preference Available to Companies that Operate at a Small Profit*

III. Identified in form of provision for Goods and Services

- iii. *Provision of Electricity for Less than Adequate & Fair Market Value Remuneration*

IV. Identified in form of loans

- i. *Credit Loan*
- ii. *Deed Tax (restructuring)*

V. Identified in form of equity infusions

- xii. *Dividend exemption between qualified resident enterprises*

Examination of Actionability of subsidies for imposition of Countervailable measures

Subsidy schemes earlier held actionable in any of the previous investigations by the Authority and GOC has not further reported any material change after such previous determinations:

31. The Authority had earlier conducted investigations wherein countervailability of a number of schemes were examined and it was found that a number of schemes/ program are actionable (countervailable if any quantifiable benefit is thereby availed by the producer/ exporter) subsidies/ programs as listed below:

- i. Program No. 2: Famous Brands Program
- ii. Program No. 3: Grants for Anti-dumping Investigations
- iii. Program No. 5: Export Assistance Grant
- iv. Program No. 6: Grants for Listing Shares
- v. Program No. 7: Funds for Outward Expansion of Industries in Guangdong Province
- vi. Program No. 8: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
- vii. Program No. 9: Various grants provided to Fuyang City
 - a) Grant for Enterprises Paying Over RMB 10 Million in Taxes
 - b) Grants under the Export of Sub-Contract Services Program
 - c) Grants under Excellent New Products/Technology Award
 - d) Investment grants from Fuyang City Government for key industries
 - e) Grants for Enterprises Operating Technology and Research and Development Centers
 - f) Local and Provincial Government Reimbursement Grants on export Credit Insurance Fees
 - g) Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of Fuyang (Zhejiang Province) & (Anhui Province)
- viii. Program No. 10: International Market Fund for Export Companies
- ix. Program No. 13: Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
- x. Program No. 14: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises.
- xi. Program No. 15: Subsidies Provided in Tianjin Binhai New Area and the Tianjin Economic and Technological Development Area
- xii. Program No. 16: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
- xiii. Program No. 33: Two Free/Three Half Program for Foreign Invested Enterprises
- xiv. Program No. 34: Tax Reductions for Export-Oriented FIEs / Income tax benefit for FIEs based on geographical location
- xv. Program No. 38: Preferential Income Tax Policy for Enterprises in the Northeast Region
- xvi. Program No. 39: Preferential Tax exemptions for Central & Western Regions
- xvii. Program No. 40: Tax Policies for the deduction of Research and Development (R&D) expenses
- xviii. Program No. 42: VAT Refunds for FIEs Purchasing Domestically Produced Equipment
- xix. Program No. 43: VAT and Tariff Exemptions for Purchases of Fixed Assets
- xx. Program No. 45: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
- xxi. Program No. 46: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- xxii. Program No. 47: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Pudong Area of Shanghai
- xxiii. Program No. 50: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
- xxiv. Program No. 52: Raw material for less than adequate remuneration /inputs/services

- xxv. Program No. 53: Policy Loans
 - xxvi. Program No. 64: Debt for equity swaps
 - xxvii. Program No. 65: Equity infusions
 - xxviii. Program No. 66: Unpaid dividends
32. The GOC has not brought forward or contested any changes in these schemes after these were last examined by the Authority in the matter of Certain Hot Rolled and Cold Rolled Stainless Steel Flat Products (Final Finding dated 04.07.2017) and thereafter in the matter of New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries (Final Finding dated 25.03.2019). The Authority holds them actionable for the present investigation, however, the Authority is not able to quantify/compute the quantum of subsidy availed as the domestic industry has not quantified Subsidy margins at any stage of this investigation neither there is any acceptable questionnaire response nor there is any other relevant publicly available information with regard to the availment of benefits under these schemes. Therefore, no countervailing measure (Subsidy margin) has been quantified in these schemes.

Subsidy schemes earlier held actionable in certain previous investigations by the Authority and GOC has further reported material changes after such previous determinations:

33. With regard to certain schemes, the GOC informed that there are material changes with regard to non-existence/ expiry/ rescinding of these schemes in the CVD investigation of “New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries” from People’s Republic of China. The domestic industry has not brought any evidence to counter such claims of GOC. Therefore, no further examination including Subsidy margin has been considered in these schemes. These schemes are listed as below:
- xxix. Program No. 1: The State key technology Renovation Projects Fund
 - xxx. Program No. 35: Tax Offsets for Research and Development by Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a period not Less Than 10 Years
 - xxxi. Program No. 36: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
 - xxxii. Program No. 48: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
 - xxxiii. Program No. 49: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

Subsidy schemes never examined with respect to actionability in any of the previous investigations by the Authority:

34. The domestic industry in the present petition has alleged the existence of certain actionable schemes in China PR which have not been examined by the Authority in the past. However, the purpose of calculation of countervailing measures under these actionable schemes/ programs, the domestic industry has not quantified Subsidy margins at any stage of this investigation nor there is any acceptable questionnaire response nor there is any other relevant publicly available information with regard to the availment of benefits under these schemes. Thus, in the absence of any information required for quantification of countervailing measure (Subsidy margin) under these schemes, the Authority considers that examination of actionability of a program is merely an academic exercise. Therefore, the Authority has not examined actionability of these programs. These programs are as below:
- xxxiv. Program No 17: Enterprise Development Funds
 - xxxv. Program No 18: Direct Government Grants given by Jiangsu Province
 - xxxvi. Program No 19: Grants under the Science and technology Program of Jiangsu Province
 - xxxvii. Program No 21: Environment Protection Award (Jiangsu)
 - xxxviii. Program No 22: Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund (Jiangsu)

- xxxix. Program No 23: Changzhou Technology Plan (Jiangsu)
- xl. Program No 24: Enterprise Innovation Award of Qishuyan District (Jiangsu)
- xli. Program No 25: Support Funds for Construction of Project infrastructure
- xlil. Program No 26: Administration Commission of LETDZ (Jiangsu Province)
- xlilil. Program No 27: Accelerated Depreciation on Fixed Assets in Binhai New Area of Tianjin
- xliv. Program No 28: Enterprise Technology Centers (e.g. Tianjin City and Jinnan District)
- xliv. Program No 29: Award for Maintaining the Growth by Beijing Governments
- xlvi. Program No 30: Award by Beijing Technology Trading Encouraging Centre
- xlvil. Program No 44: VAT and Tariff Exemptions on Imported Equipment for Favored Industries
- xlvilil. Program No 55: Export Credit Subsidy Programs
- xlilx. Program No 56: Export Seller's Credits from Export-Import Bank of China- Credit Borrowing
 - l. Program No 57: Export Buyer's Credit from Export-Import Bank of China
 - li. Program No 58: Export Credit Insurance from the China Export and Credit Insurance Corporation
 - liil. Program No 59: Preferential Export Financing from the Export-Import Bank of China.
 - liilil. Program No 60: Provision of Credit Lines
 - liiliv. Program No 61: Preferential loans provided by the Export-Import Bank "going out (global)" strategy for outbound investment

Subsidy schemes, whether alleged or found otherwise, where CVD quantification has been determined for imposition of countervailable measures:

- 35. The schemes which have been found countervailable earlier in other investigation and domestic industry has alleged subsidy have been examined for the present investigation.
- 36. The domestic industry has provided quantification of benefits under these schemes on the basis of publicly available information. Further, the Authority has evaluated all the relevant material available with it for quantification of the schemes. The Actionability of these subsidies have been discussed under the respective paragraphs herein below.

Grants

- 37. The petitioner has provided the annual report of the M/s. Pingdingshan Tianan Coal Industry Co. Ltd., which is the parent company of M/s. Kaifeng Xinhua Fine Chemical Co. one of the non-responding producer/ exporter of the PUC in the present investigation. Analysis of this annual report shows that the company has received subsidies from the Government Authorities in China under the head of "Government Subsidies" for projects involving Government Grants. Therefore, the Authority holds that it is a financial contribution in the form of discretionary government grants by a public body (by the Govt. authorities, as reported in the annual report under the head "Government subsidies") within the subject country conferring a benefit to the company concerned, and therefore is specific. Hence, a benefit has been specifically conferred onto the above said company, as reflected in the annual report of the parent company. Accordingly, the subsidy margin under the head of 'Grants' reported in the annual report has been considered. For the purpose, total amount reported in the annual report of the parent company under the head "Govt. subsidies" has been considered as the benefit conferred. Further, since the benefit has been reported in the annual report of the parent company, this benefit conferred has been apportioned over the gross turnover of the parent company. The amount of CVD margin thus determined is 0.30%.

Tax incentives and VAT

38. The GOC and its agencies administer a number of tax programs, which provide tax exemption/ reduction/ remission to certain categories of enterprises based on their location or nature of the enterprises or technological innovation. It is noted that the program numbers '33 to 50 except 37 and 41' provide similar tax benefits as per the income tax law of China PR. Further, the countervailability of the programs have already been analyzed earlier by the Authority in the past CVD investigations. Therefore, the Authority has relied upon the past determinations as the best available information for the present investigation. Accordingly, the subsidy margin under this head has been quantified as 2.14%.

Provision of Goods & Services for Less Than Adequate Remuneration (LTAR)**Land-use right**

39. The Authority notes that earlier the existence of countervailable subsidies in the form of land use rights in the CVD investigation of New Pneumatic Tyre was examined in detail. The Authority noted that GOC is providing land use rights to certain enterprises at less than adequate remuneration. Provision of land use rights at less than adequate remuneration amount to financial contribution in the form of provision of services. The Authority also observed that the land use rights provided at less than market rates amounts to conferring of benefit. This subsidy program is also specific because it is limited to certain type of enterprises in China PR. Therefore, the Authority has held that the provision of land use rights by the GOC is a countervailable subsidy program. Accordingly, the subsidy margin under this head has been quantified as 6.37%.

Raw materials

40. The Authority notes that the financial contribution arises, if raw materials becomes available to a business enterprise at less than adequate remuneration under a policy or program of the Government or a public body. In such a situation, benefit is conferred on the recipient of goods by virtue of access to raw materials at less than adequate remuneration. Such subsidy is also specific because it is limited to the enterprise which uses such raw material/ goods. Thus, the Authority holds that the raw materials availed at less than adequate remuneration is an actionable subsidy.
41. In view of non-cooperation by the Chinese producers and GOC, the Authority has considered relevant international prices of raw materials as benchmark prices. Further, the consumption norms and actual purchase price of the major raw materials involved in producing the PUC has been considered as per the best information available with the Authority.
42. The difference between the benchmark cost of raw material so determined and actual purchase cost of specific raw materials have been considered as the countervailable benefit to the Chinese producers/ exporters. Accordingly, the Subsidy margin on account of 'provision of raw material at less than adequate remuneration' has been quantified as 73.52 %.

Utilities (Electricity)

43. The Authority in the previous investigations noted that GOC is providing electricity to enterprises as actionable/ countervailable subsidy at preferential prices and at less than adequate remuneration. Further, the GOC has not provided any evidence to show that this program in any of its form does not exist or does not confer countervailable subsidy. Accordingly, the Authority holds that the subsidy under this program is an actionable subsidy.
44. In the absence of cooperation from the GOC and the Chinese producers/ exporters, the Authority has quantified the subsidy margin based on the best fact available. The subsidy margin thus quantified is 2.74%.
45. The Authority sought information from the GOC regarding the specific companies that produced the input products/ raw materials/ other goods & services that saccharin producers along with their respective cross-owned companies purchased during the POI. Specifically, information was sought from

the GOC that would allow *determinatio* whether such producers or service providers are “public bodies” within the meaning of the Act or Rules. However, GOC did not file the questionnaire response in the present investigation, or given any other information/submission to evaluate whether the privately-owned suppliers of goods or service providers are “public bodies” within the meaning of the Rules. In view of above, the Authority in the present investigation holds that the evidence provided by the applicant shows that the Chinese producers/ exporters are eligible to receive a number of subsidies, as discussed in detail in the succeeding paragraphs, granted by the Government of China or “public bodies” within the meaning of the Act and Rules. The other Authorities have taken similar stand in CVD investigations against China PR. The alleged subsidies consist of direct transfer of funds, potential direct transfer of funds or liabilities; Government revenue that is otherwise due is foregone or not collected; provision of goods and services for less than adequate remuneration; etc.

Conclusion

46. Since there is evidence of actionable subsidies and Subsidy margins have been quantified and assessed by the Authority, these schemes are considered for the purpose of determination of countervailable measures in the present investigation.

G. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

Submission made by the Domestic Industry

47. The submissions made by domestic industry are as follows:

- (i) Demand for the PUC has increased over the injury period.
- (ii) Subsidized imports from the subject country increased in absolute terms in POI as compared to the previous years. While there was a decline in imports from subject country during 2015-2016 as compared to base year; the imports increased thereafter, with a sharp surge during the POI.
- (iii) Imports in relation to production and consumption have increased significantly in the POI. This is despite Indian industry having enough capacity to meet entire Indian demand.
- (iv) Import price from subject country declined significantly in the POI without corresponding decline in the raw material costs. This has been the primary reason for the injury caused to the domestic industry.
- (v) As a result of the decline in import price, there was significant increase in imports in the POI.
- (vi) Landed price of imports from subject country has been below the net sales realization and even below the cost of production of the domestic industry. Imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- (vii) During 2016-17, cost of sales and selling price declined, wherein the decline in costs was more than the decline in selling price. During the POI cost declined further but decline in selling price was more significant than the decline in cost. Domestic industry was compelled to reduce the selling price during this period as the landed value declined significantly, even below the level of selling price and cost of sales. This establishes that declining landed value of imports has forced the domestic industry to keep its prices depressed during the POI to retain the market share.
- (viii) Capacity of the domestic industry remained same throughout the injury period. The production and sales of the domestic industry increased over the injury period. DI maintained and increased their sales volumes but such sales were made much below the cost of production.
- (ix) Increase in production has not been supported by proportionate increase in sales. Resultantly, inventories with the domestic industry increased significantly.
- (x) Market share of the DI as a whole declined significantly in the POI. This is when the domestic industry is trying to increase its sales at the cost of prices.

- (xi) Profits improved slightly in 2015-16, thereafter they turned negative in 2016-17 and the losses intensified significantly during the POI. Cash profits also showed the same trend as that of profits and turned significantly negative in the POI. ROCE improved in 2015-16, however declined again in the POI and became negative. The significant decline in import prices has led to significant deterioration in profits, cash profits and ROCE.
- (xii) Inventories have been insignificant in the past. However, they increased considerably in the POI with surge in imports from the subject country.
- (xiii) Employment level has increased over the injury period and the wages paid have also increased over the injury period.
- (xiv) Landed value of imported material from subject country is below the selling price of the domestic industry. The only factor governing the domestic industry prices are the import prices of the subject goods and the cost of production of the domestic industry.
- (xv) The existing capacity is largely unutilized. With current capacity being unutilized and losses being incurred, the ability to raise capital has weakened.
- (xvi) Growth during the injury period in respect of profits, PBIT, cash profits and return on investments was negative because of subsidized imports.
- (xvii) Imports are further threatening material injury to the domestic industry. Imports of the subject goods have increased significantly in investigation period as compared to the preceding year. This clearly shows threat of further increase in imports. Such rise in the import volumes coupled with unfair prices will decimate the domestic industry.
- (xviii) Imports prices from subject country have declined significantly in POI without corresponding decline in cost of the subject goods. Imports are undercutting the prices of the domestic industry and are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports. The DI has claimed that, it is seen from the ADD investigations concluded in the past that the price undercutting levels of the subject imports remained significantly high in the investigation period but declined significantly in the period of review, thereby evidencing the manipulation of export prices by the exporting producers then for not wanting the extension of the then ADD. Post cessation of the then duty undercutting levels have risen significantly and have in fact been the highest in the entire investigation period.
- (xix) In view of the fact of significant capacity available with the producers in the subject country, it can fairly be assumed that the foreign producers can scale up production in a short period.
- (xx) The subject country producers have had a history of exporting the subject goods at low prices and in significant volumes which is likely to intensify further in case of non-imposition of duty.
- (xxi) Subject country has significant freely disposable capacity which is being directed to India. The previously concluded sunset review investigation on subject goods, noted the fact of excess capacity and high export orientation of the producers in the subject country.
- (xxii) For the purpose of determining threat of material injury, only the injurious imports of the subject goods from the subject country should be considered.
- (xxiii) While calculating injury margin, the Authority should consider only those transactions that are below non injurious price for calculation of injury margin. Reference is also made to the Hon'ble Tribunal's order in the matter of *Kothari Sugars & Chemicals Limited versus Designated Authority* which allowed considering transactions above NIP to calculate injury margin.
- (xxiv) The domestic industry considered in the sunset review investigation was incurring losses till 2014-15 and showed profits in 2015-16 and POI of the SSR case (*i.e.*, July 15-September 16). The POI of SSR case only has 6 months in common of 2016-17. Monthly imports enclosed with the submission will

show that import prices were at the peak in the POI considered in the sunset review investigation. Import prices reached up to the level of Rs 700/kg during that period and import prices witnessed decline in H2 of 2016-17 and declined to Rs 580 in the month of March 2017. Thus import prices declined so significantly that the petitioner also had to reduce its prices below costs level to maintain market share which resulted into losses. Same trend may be seen from the data filed by the two supporters. M/s. Vardayini incurred losses in 2016-17 and the profits of M/s. AS Chemopharma declined by more than 50%!!

- (xxv) Further, the performance of domestic industry with the previous SSR should also be seen as the same would then show that the domestic industry is suffering material injury in the present POI on account of subsidized imports.
- (xxvi) No other factors apart from the subsidized imports are causing injury to the domestic industry.
- (xxvii) Performance of the domestic industry has undergone significant change from the previously concluded SSR investigation. The domestic industry is suffering material injury in the present POI on account of subsidized imports. Thus, it cannot be said that the duty imposed for 10 years has served its intended purpose. Reliance is laid on the comparison of the performance of the domestic industry over the years.

Submission by other interested parties

48. The submissions made by other interested parties are as follows:

- (i) M/s. Swati was into losses and suffering from poor ROCE in the POI of SSR – II. While the ROI of the then domestic industry was positive (3 petitioners) it has declined and is negative for 2016-17 and POI in the present investigation. The injury is due to inherent factors specific to M/s. Swati only.
- (ii) The Authority should bring forward the data of the remaining 60-70% of the major producers and consider their costs and data for determination of NIP. Injury determination should be based on data of the domestic market rather than the data that represents only a part of the domestic producers of the like product
- (iii) Data of petitioner alone is insufficient to reflect the overall economic health of the domestic industry.
- (iv) DI is not suffering any injury – Fair comparison of import volume in POI with import volume in previous years is not possible: Imports in previous years were suppressed due to anti-dumping duties
- (v) There has been an improvement in economic parameters of M/s. Swati Petro Products Pvt Ltd.
- (vi) Absence of Causal Link between Subsidized Imports and Injury – injury being suffered only by Swati; Comparison of data filed in SSR would show that petitioner was suffering losses even when ADD was in force; The landed value of goods from Indonesia is comparable to landed value of the goods from the present subject country, injury being caused due to dumped imports from Indonesia.
- (vii) Revised import statistics filed have been contradictory to the data filed earlier as despite the addition of two months in the revised data the import volumes have decreased. Imports from other countries shows decline. Even the data for previous years is also different. This has been done to achieve different outcomes in different investigation (with reference to the Indonesia Case).
- (viii) Complete imports data was not provided and has thus precluded us from making effective comments and assist the Authority accordingly.
- (ix) Because of not taking other producers into consideration volume and sales information is also unreliable.
- (x) The Authority should analyse performance of other Indian producers before concluding on injury. Reference is laid on the WTO Panel in China PR – Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures

on Broiler Products from United States wherein it was noted that an investigating Authority is not allowed to ignore the situation of other domestic producers in its injury determination.

- (xi) There is no injury to the domestic industry. Comments are limited to the data provided by the domestic industry in the petition as the data (import) provided through mail dated 18.01.2019 was provided on the brink of hearing. Further revised Proforma IV A was not filed showing imports in relation to production, consumption, actual demand etc.
- (xii) Sales of the domestic industry and of the other Indian producers increased, imports from other countries increased while those from China PR decreased; market share of domestic industry and that of other countries increased while that of other Indian producers and Chinese imports decreased; landed prices from China PR declined in the POI and so did the prices of the DI, when the prices of Chinese imports increased so did the prices of the DI. The prices of the Chinese imports are only influenced by the prices of the DI. Injury is on account of imports from other countries and lowered price of domestic industry to acquire share of other Indian producers.
- (xiii) Prices and profitability seem to be misleading as domestic industry is selling goods at much higher prices in the domestic market. Selling prices were not disclosed even in the form of range or indexed numbers in the NCV. Financials of the petitioner have been obtained from the MCA website. Selling prices as listed therein are not correct as the goods have been purchased at higher prices. Claims that the prices were below Rs. 400/Kg are incorrect and that substantial quantity has been bought from the petitioner in excess of Rs. 600/Kg. Prices declared by petitioner need to be thoroughly investigated and compared with prices at which goods are being transacted in Indian market from the books and accounts maintained by user industry.
- (xiv) Profits of the petitioner and the selling prices of the other producers need to be examined. Profits in the SSR increased for 2015-16 and POI *i.e.*, 6 months of 2016-17 (July 2015- September 2016), while data of domestic industry in the present case shows an opposite trend when they demonstrate 295% losses in 2016-17. Correct NCV of the same should also be provided.
- (xv) The trend of profitability witnesses a drastic change when the financial information of the supporter namely, Blue Circle is also taken into account. Data provided vide email dated 21.1.2019 shows that there is enough reason to believe that the other producers behaved differently from the petitioner during the POI.
- (xvi) Capacity utilization, domestic sales, number of employees, productivity and average capital employed increased. While the selling price shows a marginal decline, the cost of sales decreased much more.
- (xvii) In the 6 months of 2016-17 there was no price underselling; further the petitioner has failed to show any price underselling.
- (xviii) There is absence of causal link – imports from China have declined while those from Indonesia have increased; injury is due to competition between the Indian producers and the domestic industry has reduced prices only to increase market share; further the goods have been booked at suppressed prices in their financial records.
- (xix) The anti-dumping duty on the subject goods has already been in force for over 10 years and the domestic industry has received adequate protection. The previous ADD was in force till 12th January 2018 and it is not understandable how within a span of six months, domestic industry has started suffering injury again.

Examination of the Authority

49. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.

50. Rule 13 of the Countervailing Duty Rules, 1995 deals with the principles governing the determination of injury.

13. Determination of injury -

(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the casual link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.

(3) The designated authority may, in exceptional cases, give a finding as to the existence of injury even where a substantial portion of the domestic industry is not injured if –

(i) there is a concentration of subsidized imports into an isolated market, and

(ii) the subsidized imports are causing injury to the producers of almost all of the production within such market.

51. Further, the Rules listed the relevant economic parameters that are required to be evaluated in order to determine the consequent impact of subsidized imports to the domestic industry.
52. The Authority has considered submissions made by various interested parties and relevant legal provisions. The Authority has examined injury to the domestic industry having regard to these legal provisions. The examination here in below *ipso facto* deals with the submissions made by the domestic industry and interested parties concerning injury to the domestic industry.

Volume Effect of Subsidized Imports on the Domestic Industry

Assessment of Demand/Apparent Consumption

53. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is as below:

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Sales of Domestic Industry	Indexed/MT	100	141	151	152
Sales of Other Indian Producers	Indexed/MT	100	118	110	106
Imports from Subject Country	MT	441	581	308	520
Imports from Other Countries	MT	481	308	277	633
Total Demand/Consumption	Indexed/MT	100	111	94	122

54. It is noted that the demand showed a marginal decline in the year 2016-17 as compared to 2015-16 but increased in the POI. Overall demand shows increase over the injury period. It is seen that the subject imports in relation to production declined till 2016-17 but have increased significantly in the POI and on overall basis.

Import Volumes from subject country

55. With regard to the volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subject imports from subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Subject Country	MT	441	581	308	520
Other Countries	MT	481	307	277	633
Total Imports	MT	922	888	585	1,153

56. It is seen that imports of the subject goods from the subject country declined in 2016-17 and thereafter increased significantly in absolute terms in the POI. Imports from other countries, (mainly Indonesia) have also increased and in a separate investigation it was determined that imports from Indonesia are being dumped causing injury, therefore anti-dumping duty of USD 1.63 per Kg has been imposed on them with effect from 03.05.2019.

Price Effect of Subsidized Imports on the Domestic Industry

57. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority has considered whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the Cost of Production (COP), Net Sales Realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

Price Undercutting

58. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level is determined for comparison with the landed value of the subsidized imports. Accordingly, the undercutting effects of the subsidized imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed Price of Imports	Rs./KG	478	580	638	473
Net Selling Price	Indexed/Rs./KG	100	116	112	99
Price Undercutting	Indexed/Rs./KG	100	81	(17)	104
Price Undercutting	Range %	10-15%	7-12%	0-(5)%	12-17%

59. From the aforesaid table, it can be seen that the price undercutting from the subject country has been positive for the entire injury period except 2016-17. The extent of price undercutting has also increased significantly in the POI.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed Price of Imports	□./KG	***	***	***	***
Index		100	121	133	99
Cost of Sales	□/Kg	***	***	***	***
Index		100	114	113	109
Selling Price	□/Kg	***	***	***	***
Index		100	116	112	99

Price Suppression and Depression

60. In order to determine whether the subject imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which

otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

61. It is noted from the table above cost of sales and selling price of the domestic industry increased till 2015-16 and declined thereafter. However, the decline in selling price in the POI is much more than the decline in cost of sales. The level of selling price is below the level of cost of sales. Further, landed price of imports have remained below the level of cost and selling price of the domestic industry throughout the injury period barring 2016-17. Thus imports have had depressing effect on the domestic industry prices.

Price Underselling

62. The price underselling is an important indicator of assessment of injury. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods to arrive at the extent of price underselling. It has been stated by DI that the subject imports are having underselling effect on the domestic industry by a significant margin.

Particulars	Rs/KG	USD/KG
Non Injurious Price	***	***
Landed Value	473.43	7.25
Price Underselling	***	***
Price Underselling %	18-23%	18-23%

Economic Parameters of the Domestic Industry

63. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
64. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

Production, Capacity, Capacity Utilization and Sales

65. Capacity, production, capacity utilization and sales of the domestic industry over the injury period is given in the following table: -

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Installed Capacity	Indexed/MT	100	100	100	100
Production	Indexed/MT	100	142	152	172
Capacity Utilisation Percentage	Indexed/%	40-45%	55-60%	60-65%	68-73%
Domestic Sales	Indexed/MT	100	141	151	152

66. From the above table, it is noted that:

- The capacity of the domestic has remained constant over the injury period.
- Production of the domestic industry increased over the injury period. However, the same is much below the level of capacity installed.

- c) The capacity utilization of the domestic industry has also increased over the injury period.
- d) Domestic sales have increased over the injury period. However, the same has not been in proportion to the increase in production resulting into increase in inventories, as shown in table below.

Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Indexed/MT	100	45	14	734

Market share in demand

67. The Authority notes that the market share of the subject imports remained about the same over the injury period and market share of other countries increased. Market share of the domestic industry increased in 2016-17 however, declined in the POI. Market share of the Indian industry also increased in 2016-17, but declined in the POI.

Particulars	Units	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Domestic Industry	Indexed/%	100%	127%	160%	127%
Other Indian Producers	Indexed/%	100%	105%	119%	86%
Import from China PR	%	23%	27%	17%	22%
Other Countries Imports	%	25%	14%	15%	27%
Total Demand	Indexed/%	100%	100%	100%	100%

Profitability, return on Investment and Cash Profits

68. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
PBIT per unit	Indexed/Rs/Kg	100	160	(120)	(1,100)
Total PBIT	Indexed/Rs Lacs	100	243	(179)	(1,771)
Cash Profits	Indexed/Rs Lacs	100	217	(117)	(1,350)
PBIT as % of Avg Capital Employed	Indexed/%	100%	250%	-200%	-1750%

69. It is noted that the domestic industry was incurring losses and became profitable only in 2015-16. However, with increase in subsidized imports and dumping from other sources the domestic industry again started incurring losses in the POI.

70. ROCE, PBIT and cash profit has also followed the same trend and is significantly negative in the POI.

Employment, Wages and Productivity

71. Employment and wages over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No. Of Employees	Indexed/Nos	100	105	118	125
Productivity per day	Indexed/MT/Day	100	141	151	172

72. It is noted that the employment and wages have increased over the injury period. Further, productivity per day has also increased.

Inventories

73. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Opening	MT	100	49	17	4
Closing	MT	100	36	8	2,220
Average	MT	100	45	14	734

74. It is noted that the inventories with the domestic industry have increased significantly in the POI.

Growth

75. Growth of the domestic industry with regard to production and domestic sales has been positive. However, growth in terms of cost of sales, selling price, profit/loss, cash profit and ROI turned positive only in 2016-17 but turned significantly negative in the POI. Thus, imports have caused an adverse impact on the domestic industry in the POI.

Particulars	UOM	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Production	%	-	41.93	7.17	13.2
Domestic Sales	%	-	41.24	6.94	0.94
Cost of Sales	%	-	14.43	-1.36	-3.85
Selling Price	%	-	15.66	-3.34	-11.66
Return on Investment	%	-	116.55	-177.32	-756.37

Ability to Raise Capital Investments

76. The Authority notes that in view of the largely unutilized capacities available with the domestic industry and the losses being suffered by the domestic industry, their ability to raise any further capital for investments has been compromised.

Factors Affecting Domestic Prices

77. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than subsidized imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market has been undertaken. The data shows that the landed value of imported subject goods from the subject country is below the selling price and the non-injurious price of the domestic industry, causing price undercutting and price underselling in the Indian market. The Authority notes that the prices of the product under consideration in general should move in tandem with the prices of key raw materials. Domestic industry has claimed that they are forced to align its prices to the market prices, which are dictated by the prices offered by the foreign producers/exporters from the subject country. Thus, the landed value of subject goods from the subject country is an important factor for determination of domestic prices. The Authority notes that the domestic industry is getting affected by the import of subject goods at unfairly subsidized prices.

Causal Link & Non Attribution Analysis

78. Injury to the domestic industry has been caused by subsidized imports. Further, injury, if any, due to other factors has been segregated as discussed herein below:

- Volume and prices of imports from third countries- During POI, imports of the subject goods from the imports of product under consideration from Indonesia were significant and at lower price. The Authority has recently concluded antidumping investigation against such imports and the anti-dumping duties have been recommended by the Designated Authority and imposed by Ministry of Finance vide Notification dated 3rd May 2019.

- b. Changes in Demand- There is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period.
 - c. Changes in the patterns of consumption- The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.
 - d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers- There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - e. Developments in technology- None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.
 - f. Export performance of the domestic industry- The domestic industry has not undertaken exports during the injury period. Thus, possible decline in exports volume or profits could not have caused claimed injury to the Domestic Industry.
 - g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry- Claimed injury to the domestic industry is on account of product under consideration. The petitioner has provided information which pertains only to the product under consideration.
79. Various interested parties have argued that injury is solely caused to the petitioner and the other domestic producers have not suffered injury, the Authority notes that M/s Blue Circle Organics Pvt. Ltd have filed complete information. M/s. Shree Vardayini Chemical Industries Pvt. Ltd and M/s. A.S. Chemopharma Pvt. Ltd have also filed Format H prescribed vide Trade Notice 14/2018 dated 1st October, 2018. Performance of the supporters shows as follows:

A. M/s Blue Circle Organics Pvt. Ltd

- a. Capacity increased in the POI. However, production and capacity utilization has declined in the POI. Sales improved marginally in POI
- b. Company was incurring losses upto 2015-16, and earned profits in 2016-17, however again stated incurring losses in the POI.
- c. Cash flow, ROI also shows the same trend. ROI is significantly negative in the POI.

B. AS Chemopharma:

- a. Capacity has remained constant, however capacity utilization has declined. Production and sales increased till 2016-17, however declined thereafter in the POI.
- b. Profitability improved till 2016-17 and the same declined significantly in the POI.
- c. Cash flow, ROI also shows the same trend. ROI has again come down to one digit.

C. Shree Vardayini Chemicals

- a. Capacity has remained constant, however capacity utilization has declined. Production and sales increased till 2015-16, however declined thereafter in the POI.
- b. Profitability improved till 2015-16, however, started incurring losses in in 2016-17 which aggravated significantly in the POI.
- c. Cash flow, ROI also shows the same trend. ROI is significantly negative in the POI.

It is thus seen that the performance of the supporters have also declined in the POI as is the case with the petitioner.

Magnitude of Injury and Injury Margin

80. The Authority has determined Non-Injurious Price for the domestic industry on the basis of principles as per the Rules. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The NIP of the

domestic industry has been worked out and it has been considered for comparing the landed price from each of the subject country for calculating injury margin. For determining NIP, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been done to utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. The production in POI has been calculated considering the best capacity utilisation and the same has been considered for arriving per unit fixed cost. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (*i.e.* Average Net Fixed Assets plus Average Working Capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed and being followed. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country to determine the injury margin as follows:

S. No.	Producer Country	Producer	Landed Value (USD/MT)	NIP (USD/MT)	Injury Margin (USD/MT)	Injury Margin %	Range
1.	China	Any	***	***	***	***	15-25

H. POST DISCLOSURE COMMENTS

81. The post disclosure submissions have been summarized as below:

a) Views of the Domestic Industry

82. The Domestic Industry made the following submissions:

- i. The other two supporters are small sized companies, lacking necessary resources and since the filing of data involves significant exercise, they could not file relevant elaborate information within the time limits. However, these companies supported the petition. These producers have also filed their information with the Authority which would show the performance of these companies. It is not a ceremonial support. It is a support with relevant information with regard to their performance. The information clearly shows that these companies have also suffered
- ii. The petitioner fully supports the disclosure statement. There should be a presumption of availment of benefit, once the petitioner has shown existence of the alleged schemes and applicability to producers of the PUC.
- iii. The schemes may not be ignored only for the reason that there is no information on record to show that these schemes were availed by the Chinese producers/ exporters.
- iv. Hon'ble Supreme Court in Holder Topsoe vs DA has clearly laid down on how the non-cooperation principle has been practiced by the authority in the dumping law and the same should be adopted in the subsidy law by applying the highest CVD margins for non-cooperating exporters.
- v. Other investigating authorities, where the exporters preferred non-cooperation, the authorities have concluded that the exporters have "not acted to the best of their ability" for e.g. final finding issued by China in the matter of Ortho Chloro Para Nitro Aniline Originating from India where CVD margin was 166.8% and final finding issued by US in the matter of Large Diameter Welded Pipe from India, where CVD margin was 541.15% on the basis of non-cooperation of GOI and exporters.
- vi. The Authority should determine CVD margin in each of these schemes as done globally by other authorities.
- vii. The authority may consider the CVD margins on the basis of either Facts available (FA) or Adverse facts available (AFA) for the schemes that have been held countervailable (28 schemes) and for the schemes which were never examined by the Authority in the past (21 schemes) or where there is no evidence

provided by the Chinese producers regarding either termination of the scheme or non-applicability to the manufacturers of Saccharin.

- viii. The petitioner has provided the evidences showing the existence of 5 schemes which have been claimed as non-existent/ expired/ rescinded, the Authority has been misled by the GOC. The proof with regard to the existence of these schemes or the benefits under these subsidies has been submitted by the petitioner.
- ix. Since the CVD quantum determined in the disclosure statement is significantly higher than the injury margin determined, the petitioner does not wish to further raise its concerns regarding the CVD margin determined or countervailability of schemes.
- x. If the Authority decides to reconsider the disclosure statement either with regard to countervailability of schemes or quantification of CVD margin where CVD margins have been determined at present, the petitioner requests the authority to then kindly consider the submissions made herein above and determine subsidy margin in other schemes for which no CVD margin has been determined at present.
- xi. Imports are threatening material injury to the domestic industry. Existence of excess capacities, high export orientation and positive price undercutting shows that imports are likely together the market at significantly subsidised prices.
- xii. Only injurious transactions should be considered for injury margin and price undercutting.

Submission made by Other Interested Parties

83. The comments of other interested parties on Disclosure Statement have been summarised as under:

- i. The Authority has disclosed that the respondent's EQR is proposed to be rejected. Such action has been taken on the basis of certain listed grounds. However, according to the respondents each of them are incorrect and unsound.
- ii. All the information that the Authority finds "insufficient" here was a matter of one question to the Respondent which was not sought.
- iii. As regards the proposition that exporter is a Private Limited Company, but have claimed to be a "private limited liability company" in the EQR, it is submitted that the correct description has been provided and it is further clarified that the company is a private limited Liability company as evidenced in Business License and shareholder structure of the company enclosed with the EQR.
- iv. As regards the proposition that the details of the joint venture partners (including the information whether such partner is privately-owned or state- owned) have not been revealed in the EQR, it is submitted that there was no specific question in this regard in the questionnaire response. Document now enclosed with the comments show that M/s. Fortune Knitting Factory Ltd., are individuals and not state-owned enterprises.
- v. The Authority's reference to the major raw material accounting for 57% of the total turnover of the company is not clear and a clarification is requested in this regard. The costliest raw material of the PUC is Methanesulfonamide. The Authority can reconcile the total purchase amount of Methanesulfonamide during the POI with the total amount sourced from different suppliers.
- vi. It has been stated that no relationship between the raw material, namely, F1 and PUC could be found by the Authority from any source including web search. However, Respondent's EQR shows that the product which was exported to India (calcium saccharin) does not utilize F1 as a raw material at all.
- vii. Regarding the proposition that name of one of the two suppliers has not been provided in the EQR, the Respondent admits the oversight. The name of the supplier is Shanghai Noucheng Pharmaceutical Co., Ltd. which is a privately-owned company- a fact disclosed in Exhibit-14 of the Respondent's EQR.

- viii. The insufficient and contradictory information as mentioned in the Disclosure Comment in respect of related parties have not been clearly laid out. A clarification should have been sought and the insufficiency could have been cured promptly
- ix. The data provided by the Respondent and the data available with the DGCI&S matches. The data is absolutely reliable and reflects the actual transaction made. Thus, the Authority's statement that the price is "unreliable" is unclear.
- x. Authority cannot reject our export volume and price merely because it appears to be "unrepresentative" of overall Chinese exports to India. The interested party cannot be penalised for not exporting at subsidised/injurious price. The Respondent failed to export in large volume during 2015, 2016 and 2017 mainly because of the implementation of the anti- dumping measures by India.
- xi. There is no provision under the WTO CVD Agreement or the Indian CVD Rules which allows the Authority to reject a response in a countervailing duty investigation, owing to the reason that the volume of sales to India was unrepresentative
- xii. Respondent had filed a letter seeking verification of its data on 22 April 2019, explaining in detail that the pricing of its products to India is comparable to pricing of its products to third countries as well as to the domestic market, when the volumes are so low. This letter and its submissions have not even been mentioned by the Authority in the Disclosure Statement. Exports made to India and third country are comparable in terms of prices.
- xiii. The Authority has grossly violated the confidentiality requirements of the Indian CVD Rules and the WTO ASCM in publishing the volumes exported by the Respondent to India over the last three years.
- xiv. The data for the Income Tax Return of 2017 and VAT Returns of 2017 have been provided to the Authority and contain data that may be well cross verified with the Annual Report of 2017 of the Respondent. The Authority has incorrectly noted that the data for 2017 was not provided, when it is available with the Authority in the very same documents that are being cited by the Authority
- xv. The Authority never sought any clarifications and has simply failed to assess the response. Thus, the Authority's failure to seek out information in a timely manner cannot prejudice the Respondent's participation and allow use of facts available standard.
- xvi. In view of the supporters' data, it needs to be examined whether the injury suffered by the Petitioner is isolated to it, or whether it reflects an industry wide situation. Perusal of the supporters' data shows that the other domestic producers performed much better than the Petitioner during the POI. Reference is made to Coated paper Findings
- xvii. We are disappointed to note that the Authority has not even considered the argument of the respondent with regard to correctness of selling price of domestic industry in its examination. While the submission of the respondent has been reproduced in parts in para 47(xiii), the Authority has not dealt with the same.
- xviii. The user has accepted in its questionnaire response that *** MT of the subject goods have been purchased from the domestic producers and only *** MT of the subject goods is imported. Only the insoluble saccharin produced by Domestic Industry does not pass the requirement of user industry and the names of major labs along with the differences in technical characteristics of the imported products with those of domestic products was also provided.
- xix. In case the Authority is not willing to do a general exclusion of the product grade mentioned by the respondent, the Authority may kindly exclude the insoluble saccharin imported by responding importer.

- xx. When the interested parties provided names of other domestic producers, the Authority ought to have carried out independent inquiry as to the existence of other domestic producers instead of merely holding that no evidence in this regard has been supplied by the interested parties.
- xxi. Format-H by supporters cannot be accepted as they have been filed beyond timeline and even after the hearings. Such information cannot under any circumstances be taken on record as it did not provide any opportunity to the interested parties to offer their comments and to defend their interests.
- xxii. Format-H does not cover all the mandatory factors as envisaged under Article 3.4 of the Anti-dumping Agreement and para (iv) of Annexure II of the Anti-dumping Rules. Specifically, the Format-H does not contain information with regard to wages, market share, growth, ability to raise capital investment, negative effect on cash flows and factors affecting domestic prices.
- xxiii. Supporters have not provided any information with regard to the "price effect" which is a precondition along with "volume effect"
- xxiv. Neither the Domestic Industry nor the Authority has provided any consolidated information of the industry as a whole
- xxv. Parties are handicapped to make any effective comments on the injury suffered by the Domestic Industry as Authority has kept even the volume related information as confidential despite their own Trade Notice No. 10/2018 dated 7/9/2018
- xxvi. The Domestic Industry is not suffering any injury on account of the alleged subsidized imports from China
- xxvii. The interested parties have contended that the Designated Authority has not identified or linked any of the CVD programs to producers of the product under consideration, nor provided methodology for quantification, has presumed that the subsidies found in "tyres case" or "steel case" ipso facto applicable to the present product. With regard to land use right, tax schemes and benefit on account of electricity, it has been contended that the subsidy quantum found in other cases cannot be directly applied. As regards raw materials, the interested parties have contended that the authority has not identified the name of the raw material, benchmark considered and calculation of CVD margin. Grants available/received by the parent company cannot be applied to the producer of the product. Further, the interested parties have contended that questionnaire response of the exporter is the best available information even in a situation where the Authority has decided to reject the response.

Examination by the Authority

84. It is noted that the issues raised at post disclosure stage have already been examined by the Authority and addressed appropriately in above relevant paragraphs. Further, additional argument found relevant have been addressed as under:
- i. As regards the contention that the deficiencies pointed out for rejection of questionnaire response is incorrect and could have been resolved with a simple clarification, the Authority notes that the exporter questionnaire response has been rejected on account of number of deficiencies and discrepancies in the questionnaire response coupled with the fact that the export volume and export price itself appears to be not representative. While contending that the law does not provide for rejection of exporter questionnaire on account of export volume and prices, the Authority notes that the volume of business in individual sales transactions and demand for the product, coupled with the price cannot be completely ignored while considering the claim. Further, it is not the first time that the Authority found the volume and price of export doubtful. The volume and price of the responding exporter was inappropriate even in the first sunset review of anti-dumping investigations concerning imports of subject goods from subject country which was not accepted by the Authority in the said investigation. The decision of the Authority was challenged by the exporter, but was upheld by the Hon'ble CESTAT. It is noted that the exporter has not given any cogent reason to justify either its

price or volume. The situation that the responding exporters are able to sell in Indian market at much higher prices as compared to the average import prices for the subject goods is difficult to comprehend or make business sense. The export transaction could not be proved normal by the exporter. Keeping this factor in consideration and having regard to the facts of the present case wherein negligible amount has been exported at almost double the prices of the average import price of subject goods, the Authority find the export transaction itself is unreliable and cannot be accepted for determination of individual subsidy margin. Further, even while some of the deficiencies have been replied to by the Respondent through its comments, pertinent facts relevant to examine subsidy have still not been answered. The chemical/trade name of F1 has still not been disclosed. Mere fact that F1 is not a part of calcium saccharin which have been exported to India is insufficient ground for withholding such information. Further, the fact of existence of other related parties which has been emphasized by domestic industry and evidenced through web article quoting notice from Department of Industry and Information Technology of Henan Province, China and the same has not been rebutted at all. In the absence of any rebuttal with verifiable evidence, the Authority considers this as a material suppression of facts.

- ii. As regards the argument that the supporter's data must be examined, the Authority notes that the same have been examined appropriately in relevant paras in this finding.
- iii. As regards the argument that correctness of selling price of the domestic industry was not examined, the Authority notes that the information pertaining to domestic industry considered relevant by the Authority in the present investigation was duly verified and accepted.
- iv. As regards the contention that Format H filed by supporters cannot be accepted as they were submitted beyond time lines and because they do not have all the information required for injury analysis, it is noted that information of M/s Blue circle was filed by the domestic industry, however the same was not accepted or considered on account of their ineligibility to be considered as an eligible domestic producer. As for M/s AS Chemopharma and M/s Vardayini Chemicals, the information was sought to have a comprehensive analysis of causal link and non-attribution factors, however, the supporter information has not been considered for injury analysis as per the general practise of the Directorate.
- v. As regards the argument that insoluble saccharin sold by domestic industry does not pass technical specification required and thus the importer, Grauer & Weil has to import insoluble saccharin, it is noted that the domestic producer has in fact sold insoluble saccharin to the said importer as was made known during verification. Therefore, importer's statement is baseless and incorrect to this extent.
- vi. With regard to contentions of the interested parties on countervailability of scheme, their applicability to the PUC and quantification thereof, the Authority notes that the petitioner had filed petition alleging existence of a large number of countervailable subsidy programs and schemes and provided all relevant evidence in support thereof. The petitioner had identified various schemes applicable to various saccharin producers by identifying nature of the business enterprise, its location and linking the same to various schemes. Further, a large number of schemes were linked to exports. After receipt a petition, an opportunity for consultation was provided to the GOC, which was duly availed by the GOC on 20th July 2018, followed by written submissions of their statement. However, the GOC did not provide any verifiable documents at the time of consultation.
- vii. Since the GOC and the Chinese producers have not come forward with details/documents contesting the claims of existence of subsidises, the Authority has made determination on the basis of available information. Further, the Authority has also relied upon recently conducted investigation in the matter of "New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries" from China PR vide notification no F. No.6/8/2018-DGAD dated 25th March, 2019, and held them countervailable, however, the subsidy have been quantified/ not-quantified as per the detailed reasoning given in para 32 – 42 above.

- viii. As regards CVD margin determined for grants, the Authority has given detail rationale in the para 37 above.
- ix. As regards to countervailability of raw materials, tax, land use rights and electricity, the Authority notes that the petitioner provided relevant information with regard to various schemes, their countervailability and applicability to the producers of the product under consideration. A copy of the petition was made available to the Chinese Govt. prior to initiation. The Chinese Govt. attended consultation, but did not provide any verifiable documentary evidence to disprove the claims of the petitioners. Nor has the GOC filed questionnaire response post initiation of investigations. The Authority holds in this regard that relevant information for examination of countervailability and determination of CVD margin is in possession of the Govt. of China and the Chinese producers. When these parties have preferred non-cooperation, the Authority is required to determine CVD margin on the basis of best available information. Accordingly, the detailed rationale for subsidy margin under these heads are given in para 38, 39, 41 & 42 above.

CONCLUSION ON INJURY AND CAUSATION

85. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the Authority concludes that:
- i. The product under consideration has been exported to India from subject countries at subsidized value, thus resulting in subsidization of the product.
 - ii. The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
 - iii. The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.
86. The Authority notes that there is sufficient causal link between subsidies being provided by the subject country benefitting the product under consideration and causing injuring the domestic industry.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

87. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.
88. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

RECOMMENDATION

89. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including Government of China PR and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to

recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR in the form and manner described hereunder.

90. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive countervailing duty as a percentage of the landed value of imports as mentioned in Col 6 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

Duty Table

S. No.	Heading/Sub heading	Description of goods	Country of Origin/Export	Producer	Duty amount as % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	29251100	Saccharin in all its forms	China	Any	20

91. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
92. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated General